चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 13 अप्रैल –19 अप्रैल 2015 | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

भाजपा का विकल्प जनता परिवार है

> भारत की राजनीति एक नाज़ुक मोड़ पर है. देश के प्रजातांत्रिक विकास और देश में प्रजातंत्र के भविष्य की दिशा-दशा तय होने का वक्त है. यह मोड़ नाज़ुक इसलिए है, क्योंकि यह तय होना है कि भविष्य में सत्ता के लिए कौन-कौन सी शक्तियां आपस में मुकाबला करेंगी, इन शक्तियों का प्रारूप क्या होगा? वे कौन लोग होंगे, जो देश को नेतृत्व देंगे? यह तय होना है कि क्या भारत की राजनीति में विचारधारा का महत्व रहेगा या नहीं? इन सवालों का समीक्षात्मक विश्लेषण करना इसलिए ज़रूरी हो गया है, क्योंकि तूफानी बदलाव के इस दौर में पहली बार देश की प्रमुख समाजवादी पार्टियों का राष्ट्रीय स्तर पर विलय हुआ है.

मनीष कुमार

आज़ादी से पहले और आज़ादी के 45 वर्षों बाद तक देश में एक पार्टी का वर्चस्व रहा. कांग्रेस अकेली पार्टी थी, जिसका दबदबा राज्यों और केंद्र में रहा. अपवाद के तौर पर बीच में एक बार 70 के दशक में जनता पार्टी और 80 के दशक में वीपी सिंह के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आई, लेकिन वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी. सामाजिक विकास और सशक्तिकरण के संघर्ष के बाद, भारत की राजनीति बड़ी कठिनाई से एक पार्टी के वर्चस्व से बाहर निकली. किसी एक पार्टी का वर्चस्व किसी भी प्रजातंत्र के लिए ख़तरनाक होता है. स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए यह ज़रूरी है कि स्थिर सरकार के साथ-साथ एक मजबूत विपक्ष भी हो, जो सत्तारूढ़ दल को चुनाव में पटखनी देने का सामर्थ्य रखता हो. प्रजातंत्र में सत्तारूढ़ पार्टी का विकल्प जनता के पास हमेशा मौजूद रहना चाहिए. जनता को विपक्ष पर अनिवार्य रूप से यह भरोसा होना चाहिए कि यदि सत्तारूढ़ पार्टी सरकार चलाने में विफल हो जाए, तो दूसरी पार्टी और नेता उस ज़िम्मेदारी को उठा सकते हैं. अगर सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष में वैचारिक मतभेद हो तथा नीतियों को लेकर सैद्धांतिक विरोध हो, तो प्रजातंत्र न सिर्फ़ मजबूत होता है, बल्कि सामाजिक एवं राजनीतिक विकास के लिए अमृत बन जाता है. राजनीतिक-सामाजिक विकास का रास्ता विचार और सिद्धांत से तय होता है, जिस पर भौतिकवाद चहलक़दमी करता है. कहने का मतलब यह कि स्थिर सरकार व मजबूत नेतृत्व के साथ-साथ सामर्थ्यवान विपक्ष, मुख्य पार्टियों में वैचारिक मतभेद, नीतियों पर सैद्धांतिक विरोध, सत्ता परिवर्तन का अवसर, चौकस मीडिया, सक्रिय सिविल सोसाइटी और सत्ता के बाहर विश्वसनीय नेताओं की मौजूदगी स्वस्थ प्रजातंत्र की निशानी है. भारत में प्रजातंत्र के इन मूल तत्वों में से कुछ मौजूद हैं और कुछ नदारद. देश में प्रजातंत्र को जीवंत बनाने का दायित्व राजनीतिक दलों का है, इसलिए जो मूल तत्व मौजूद नहीं हैं, उनकी ज़िम्मेदारी भी राजनीतिक दलों की ही है.

2014 में नरेंद्र मोदी को बहुमत देकर देश की जनता ने केंद्र में एक सशक्त और स्थिर सरकार स्थापित की. जनादेश ऐसा था कि किसी भी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिलीं, जिससे उसे विपक्षी पार्टी घोषित किया जा सके. इसके बाद कुछ राज्यों में चुनाव हुए. इन राज्यों में जो नतीजे आए, वे भी लोकसभा की तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले गए. इससे एक ख़तरे की आशंका पैदा हो गई है. भारत की राजनीति फिर से उसी एक पार्टी वर्चस्व की राह की ओर मुड़ गई है, जिससे काफी मशक्कत के बाद पीछा छूटा था. भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हर राज्य में फैल रही है, उससे एक पार्टी वर्चस्व का ख़तरा पैदा हो गया है. यह ख़तरा इसलिए भी पैदा हो गया, क्योंकि दस वर्षों के यूपीए शासनकाल के दौरान जिस तरह से भ्रष्टाचार और घोटाले हुए. संस्थानों की साख ख़त्म की गई, उससे कांग्रेस पार्टी जनता की नज़रों में गिर गई. लोगों में इस कदर नाराज़गी है कि न सिर्फ़ लोकसभा में, बल्कि हर राज्य में वे कांग्रेस पार्टी को सजा देने लग गए. आज कांग्रेस की हालत यह है कि कर्नाटक को छोड़कर वह हर बड़े राज्य में सत्ता से बाहर हो गई है.

> **कुछ लोग इस विलय की तुलना तीसरे मोर्चे से करते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि देश में तीसरा मोर्चा केंद्र की सत्ता के लिए बनाया गया, जबकि यह विलय देश के कई राज्यों में एक विकल्प के रूप में उभर रहा है. लोकसभा चुनाव 2019 में होंगे. इसलिए यह साफ़ है कि समाजवादियों की यह नई पार्टी देश में एक वैकल्पिक राजनीति की ज़मीन तैयार करने मैदान में उतरी है.**

हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस लगभग समाप्त हो गई.

कांग्रेस की समस्या सिर्फ़ यह नहीं है कि जनभावना उसके ख़िलाफ़ हो गई है. इससे भी बड़ी समस्या यह है कि राहुल गांधी कुछ ही दिनों में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं और उनकी छवि एक विमुख और अनिच्छुक नेता की हो गई है. वैसे भी जो शख्स बजट सत्र जैसे महत्वपूर्ण समय में देश से नदारद हो जाए, उस पर लोग कैसे विश्वास करेंगे. जब देश में भूमि अधिग्रहण बिल के ख़िलाफ़ किसान आंदोलन कर रहे हों, बेमौसम बारिश की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हों और तब एक नेता छुट्टियां मना रहा हो, तो फिर लोगों का भरोसा उठना लाजिमी है. कांग्रेस का जितना नुक़सान चुनाव हारने से नहीं हुआ, उससे ज़्यादा बड़ा झटका राहुल गांधी के अज्ञातवास से लगा है. इसी तरह के बर्ताव की वजह से लोगों का भरोसा कांग्रेस और राहुल गांधी से उठ चुका है. हाल तो यह है कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ही वह एक बोझ लगने लगे हैं. कांग्रेस के अंदर अब प्रियंका वाड्रा को मैदान में उतारने की मांग उठने लगी है. इन्हीं वजहों से लोगों को लगने लगा है कि राहुल गांधी किसी भी हालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते. लोगों ने अब यह मान लिया है कि राहुल गांधी में नरेंद्र मोदी का विकल्प बनने की क्षमता नहीं है. इसलिए विपक्ष के नाम पर देश में शून्य और खालीपन प्रतीत होने लगा है.

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद कई लोगों को यह लगा कि अरविंद केजरीवाल 2019 में एक विकल्प के रूप में खड़े हो सकते हैं. लेकिन, पिछले एक महीने से जिस तरह से ख़बरें आ रही हैं और आम आदमी पार्टी के अंदर जो गृहयुद्ध चल रहा है, उससे यह आशा भी धराशायी हो गई. केजरीवाल न ढंग से पार्टी चला पा रहे हैं और न सरकार चला पा रहे हैं. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और लोकपाल के मुद्दे पर अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी एक विचारधाराविहीन

(शेष पृष्ठ 2 पर)

राह से भटक गई आप

पेज-03

एनटीपीसी : सांसदों को पटाने के लिए पंच सितारा होटल में भोज दी

पेज-04

हसदेव अरण्य : कोल ब्लॉक आवंटन के खिलाफ खड़े हुए ग्रामीण

पेज-07

साई की महिमा

पेज-12

भाजपा का विकल्प जनता परिवार है

पृष्ठ 1 का शेष

और सिद्धांतविहीन पार्टी बनकर राजनीति करना चाहती है. यही वजह है कि केजरीवाल दिल्ली जैसे छोटे और कम ज़िम्मेदारी वाले राज्य को एक अच्छी सरकार देने में उलझ गए हैं. पूरी पार्टी का दिल, दिमाग और ताकत दिल्ली पर केंद्रित है, फिर भी कोई नतीजा दिख नहीं रहा है. अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली एक क्षेत्रीय–पारिवारिक पार्टी के नेता जैसी है, इसलिए दो वर्षों के अंदर ही पार्टी के अंदर टूट–फूट शुरू हो गई है. ज़्यादातर संस्थापक सदस्य पार्टी से बाहर जा चुके हैं. आम आदमी पार्टी के उमेश सिंह के स्टिंग ऑपरेशन से केजरीवाल की छवि को काफी नुक़सान हुआ है. हर राज्य में पार्टी दो हिस्सों में बंट गई है. इसलिए आम आदमी पार्टी के पूरे देश में भाजपा से मुकाबला करने की स्थिति में आने की संभावना न के बराबर है. केजरीवाल ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली को अच्छी सरकार दे सकें, यही उनकी सफलता मानी जाएगी.

वर्तमान स्थिति में यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी न तो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन सकती है और न राहुल–अरविंद इस स्थिति में हैं कि वे मोदी को चुनौती दे सकें. इन दोनों ही पार्टियों की अपनी–अपनी समस्याएं हैं और सीमा है. लेकिन, सबसे बड़ी बात यह है कि इन पार्टियों में वैचारिक समानताएं हैं. ये सभी पार्टियां फ्री मार्केट इकोनॉमी की समर्थक हैं. ये निजीकरण और नव–उदारवादी आर्थिक व्यवस्था के ज़रिये ही विकास का मॉडल पेश करती हैं. जो फ़र्क़ है, वह सिर्फ़ कुछ मुद्दों को लेकर अलग–अलग धारणाओं की वजह से है. इसलिए वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से ये विकल्प पेश करने में विफल हैं. भारत जैसे विकासशील देश, जिसकी आबादी का बहुसंख्यक ग़रीब है, में आर्थिक नीतियों और विकास के मॉडल पर वैचारिक बहस अत्यंत आवश्यक है. बहस वहीं संभव है, जहां विचार और सिद्धांत में परस्पर प्रतिस्पर्धा हो. इस लिहाज से देश की समाजवादी पार्टियों का एक साथ आना ऐतिहासिक टर्निंग प्वाइंट है और यह देश के प्रजातंत्र को नई ऊर्जा देने वाली घटना है.

जनता परिवार के विलय को लेकर महीनों से बातचीत चल रही थी. इस विलय में मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, शरद यादव, एचडी देवेगौड़ा और केसी त्यागी की भूमिका अहम है. कई विश्लेषकों और राजनीतिक समीक्षकों ने जनता परिवार के विलय को खारिज कर दिया. कई लोगों ने इसे तीसरे मोर्चे का एक नया प्रयोग बताया. हक़ीक़त यह है कि इस विलय को मोर्चा कहना ही ग़लत है. इन नेताओं ने एक मोर्चा नहीं बनाया है, बल्कि एक पार्टी बनाई है. यह पहले की तरह कोई चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं है, बल्कि इसका मकसद भारतीय राजनीति में एक विकल्प के रूप में उभरना है. इस विलय के साथ ही समाजवादी धारा को एक बल मिला है. दो बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश और बिहार में इसकी सरकारें हैं. एचडी देवेगौड़ा के साथ आने की वजह से दक्षिण भारत में पार्टी की एक मजबूत मौजूदगी दिखेगी और इंडियन नेशनल लोकदल ने इस पार्टी को हरियाणा के साथ–साथ दिल्ली और राजस्थान के कई इलाकों में पहुंचा दिया. कहने का मतलब यह कि विलय के पहले दिन से ही यह एक राष्ट्रीय पार्टी है.

कुछ लोग इस विलय की तुलना तीसरे मोर्चे से करते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि देश में तीसरा मोर्चा केंद्र की सत्ता के लिए बनाया गया, जबकि यह विलय देश के कई राज्यों में एक विकल्प के रूप में उभर रहा है. लोकसभा चुनाव 2019 में होंगे. इसलिए यह साफ़ है कि समाजवादियों की यह नई पार्टी देश में एक वैकल्पिक राजनीति की ज़मीन तैयार करने के लिए मैदान में उतरी है. यह सिर्फ़ लोकसभा में चुनाव से पहले का ग़ैर–कांग्रेस और ग़ैर–भाजपा गठबंधन नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के कमजोर होने की वजह से जो राजनीतिक खालीपन पैदा हुआ है, यह उस पर कब्जा करने की कवायद है. कांग्रेस एवं भाजपा की आर्थिक नीतियों और सामाजिक विकास के दृष्टिकोण में कोई फ़र्क़ नहीं है. नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह के विकास मॉडल एक जैसे हैं. यही वजह है कि जबसे भाजपा सत्ता में आई है, वह कांग्रेस की नीतियों को ही आगे बढ़ा रही है. फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि भाजपा की कार्यशैली कांग्रेस से ज़्यादा पारदर्शी और तीव्र है. उदाहरण के तौर पर कोयला खदानों के आवंटन को देखिए. कांग्रेस और भाजपा में फ़र्क़ सिर्फ़ आवंटन की विधि को लेकर है.

कांग्रेस पार्टी ने मंत्रालय में कोयला खदानें निजी कंपनियों को दे दीं, वहीं भाजपा ने नीलामी के ज़रिये कोयला खदानें निजी कंपनियों को दे दीं. किसी ने यह नहीं पूछा कि राष्ट्रीय संपदा को निजी हाथों में देकर हम निजी कंपनियों को फ़ायदा क्यों पहुंचा रहे हैं? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों से सिर्फ़ अमीरों का फ़ायदा होता है, बड़ी–बड़ी कंपनियों को फ़ायदा होता है. दुनिया के किसी भी देश में नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों से ग़रीबों को फ़ायदा नहीं पहुंचा है. देश में लड़ाई नव–उदारवादी व्यवस्था को लेकर होनी चाहिए. एक तरफ़ वे पार्टियां हैं, जो नव–उदारवाद का समर्थन करती हैं और दूसरी तरफ़ इसे ग़रीब विरोधी और जनविरोधी व्यवस्था मानने वाली पार्टियां हैं. दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा की ज़रूरत है. जब तक इन मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचारों के बीच बहस नहीं होगी, तब तक आम जनता और ग़रीबों का भला नहीं होगा.

जहां तक बात चुनावी राजनीति की है, तो भारतीय जनता पार्टी की नज़र बिहार और उत्तर प्रदेश पर लगी है. भाजपा इन दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव जीतकर अपराजेय बनने के लिए तत्पर है. इन दोनों राज्यों में जीत का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी का पूरे हिंदी हार्टलैंड पर कब्जा. इससे एक बार फिर से देश की राजनीति के एक पार्टी वर्चस्व के दौर में फिसलने का ख़तरा पैदा हो जाएगा. जनता परिवार की पहली चुनौती यही होगी कि वह भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ बिहार में रोके. बिहार में हाल में ही हुए उपचुनाव के नतीजों ने यह साबित किया है कि अगर जनता परिवार एकजुट होकर लड़े, तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी. बिहार में हुआ उपचुनाव लालू यादव और नीतीश कुमार ने एकजुट होकर भाजपा के ख़िलाफ़ लड़ा था और वे 10 में से छह सीटें जीतने में कामयाब हुए थे. मतलब यह कि जनता परिवार की पहली चुनौती बिहार चुनाव है. इसमें अगर नीतीश कुमार सफल हो जाते हैं, तो इससे न सिर्फ़ भाजपा का विजय रथ रुकेगा, बल्कि जनता परिवार देश के सामने एक विकल्प के रूप में उभर जाएगा.

बिहार जीतने के लिए जनता परिवार के नेताओं को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी. बिहार में जनता परिवार के सामने कई चुनौतियां हैं, जो विलय से पैदा हुए विरोधाभासों से पैदा हुई हैं. इन विरोधाभासों को ख़त्म करना पहली ज़िम्मेदारी होगी. इसके लिए जनता परिवार के नेताओं को अपने अहंकार पर काबू पाना होगा. वह इसलिए, क्योंकि जनता परिवार का भविष्य पूरी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव पर टिका है. बिहार में अगर जनता परिवार हार जाता है, तो यह विलय अर्थहीन हो जाएगा. जनता परिवार के लिए अच्छी ख़बर यह है कि बिहार में नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने से सरकार की साख बढ़ी है. मांझी सरकार के दौरान हुई ग़लतियां सुधारना और क़ानून व्यवस्था दुरुस्त करना नीतीश कुमार की प्राथमिकता होनी चाहिए. विधानसभा चुनाव में अभी क़रीब छह महीने बाकी हैं. इस दौरान नीतीश कुमार को यह साबित करना होगा कि वह सुशासन के साथ–साथ बिहार का विकास करने में सक्षम हैं. याद रखने वाली बात यह है कि बिहार की जनता ने लोकसभा चुनाव में जाति–पांत से ऊपर उठकर वोट दिया था. बिहार में जीत की कुंजी इस बार भी यही है. बिहार में इस बार वही पार्टी चुनाव जीतेगी, जो युवाओं और ग़ैर–समर्पित मतदाताओं का समर्थन पाने में कामयाब रहेगी. ■

manishbph244@gmail.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 06
दिल्ली, 13 अप्रैल –19 अप्रैल 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

आईएएस लॉबी में असंतोष

दिलीप चेरियन

आईएएस लॉबी का ग़ैर आईएएस लॉबी के साथ मतभेद कोई नई बात नहीं है. आईएएस लॉबी हमेशा से ही अपनी प्रतिद्वंद्वी ग़ैर आईएएस लॉबी की आंखों में खटकती रही है. ग़ैर आईएएस लॉबी को पावरफुल आईएएस लॉबी द्वारा उसके साथ भेदभाव को लेकर हमेशा शिकायत भी रहती है. पोस्टिंग का मसला हो या अपने उच्चाधिकारियों को प्रभावित करने का, आईएएस लॉबी हमेशा ग़ैर आईएएस लॉबी पर हावी रही है. हालांकि, आईएएस लॉबी कभी इस बात को स्वीकार नहीं करती. हाल में आईएएस सेंट्रल एसोसिएशन के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मिले थे, तब इस मुलाकात को लेकर लोगों की भौंहें तन गई थीं. इन अधिकारियों ने मंत्री जी से अपने काम के हालात को लेकर शिकायत की. सूत्रों का कहना है कि एसोसिएशन के सचिव संजय भुसरेड्डी ने ऐसे आईएएस अधिकारियों की सूची तैयार की है, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं. अगर इन अधिकारियों की मांगें नहीं मानी जाती हैं, तो इनमें असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है. विभिन्न मांगों के अतिरिक्त इन अधिकारियों की एक मांग यह भी है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली पहुंचने वाले आईएएस अधिकारियों के बच्चों का दाखिला राजधानी के प्रतिष्ठित स्कूल में स्वत: हो जाए. अधिकारियों का मानना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तो यह उनका असंतोष बढ़ाएगा और उन्हें हतोत्साहित करेगा. मंत्री जी ने अधिकारियों की चिंताएं एवं मांगें ध्यान से सुनीं और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को उनका मूल्यांकन करके एक नोट तैयार करने के निर्देश दिए. आम तौर पर नौकरशाह किसी मुद्दे पर या तो धीमी गति से कार्रवाई करते हैं या उन्हें फाइल की याद ही नहीं रहती, लेकिन चूंकि यहां उनकी अपनी समस्याएं हैं, इसलिए वे चाहेंगे कि उनका समाधान जल्द से जल्द हो. ■

अच्छे दिनों का इंतज़ार

पिछले साल हरियाणा में जब भाजपा सत्ता में आई, तो आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने यह ज़रूर सोचा होगा कि उनके करियर में उत्पन्न गतिरोध समाप्त हो जाएगा और हुड्डा सरकार के समय की परेशानियों से निजात मिल जाएगी, लेकिन नई सरकार भी खेमका को किसी प्रकार की राहत देती नज़र नहीं आ रही है. इसके अतिरिक्त खेमका के ख़िलाफ़ जो आरोप–पत्र दायर किया गया है, उसे भी खट्टर सरकार ने अब तक वापस नहीं लिया है. हाल में खेमका उस समय सोशल मीडिया पर सामने आए थे, जब सीएजी रिपोर्ट राज्य विधानसभा में रखी गई थी. लोगों का मानना है कि खेमका ने राजनीतिक दबाव की परवाह किए बिना विवादास्पद भूमि सौदे को रद्द किया. खेमका के इस निर्णय से कांग्रेस का हरियाणा से सफाया हो गया और भाजपा का राज्य में आगमन हुआ. इसलिए खेमका को आज भी अच्छे दिनों का इंतज़ार है. ■

बाबुओं की कमी

कुछ समीक्षकों का मानना है कि उत्तराखंड में बाबुओं की कमी के पीछे राजनेताओं की सतही राजनीति ज़िम्मेदार है. 120 अनुशंसित आईएएस अधिकारियों में से सिर्फ़ 67 आईएएस अधिकारी ही राज्य के पास हैं, जिनमें से 16 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं. बाबुओं की कमी की इस स्थिति के पीछे पांच अधिकारियों का सेवानिवृत्त होना भी है. सेवानिवृत्त अधिकारियों में केडी राजू और विनोद चंद के नाम भी हैं, जो कुछ दिनों पहले सेवानिवृत्त हुए हैं. इस महीने के अंत में मुख्य सचिव एन रविशंकर भी सेवानिवृत्त होने वाले हैं. वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पीएस जंगपांगी भी ऐसे अधिकारियों में शामिल हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य सरकार का इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं है या वह इसके समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है. सूत्रों के अनुसार, पिछले साल मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे कुछ आईएएस अधिकारियों की राज्य में वापसी को लेकर केंद्र सरकार से बात की थी, लेकिन रावत की बात केंद्र ने अनसुनी कर दी और आईएएस अधिकारियों को राज्य में नहीं भेजा. कुछ लोगों का मानना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसीलिए केंद्र ने राज्य सरकार की मांग नज़रअंदाज कर दी. केंद्र के इस रवैये का खामियाजा राज्य और वहां के निवासियों को भुगतना पड़ रहा है. ■

dilipcherian@gmail.com

राह से भटक गई आप

आम आदमी पार्टी का तर्क है कि प्रशांत भूषण एवं योगेंद्र यादव के ख़िलाफ़ कार्यवाही इसलिए की गई, क्योंकि वे पार्टी को चुनाव में हराना चाहते थे और उन्होंने शांति भूषण के साथ मिलकर पार्टी को हराने का हरसंभव प्रयास किया. ठीक है, अगर उनके ख़िलाफ़ पुख्ता सुबूत थे, तो उन पर कार्यवाही होनी ही चाहिए थी. लेकिन, इसी तर्क के आधार पर फिर अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ कार्यवाही क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि उन्होंने डंके की चोट पर एक स्टिंग में यह कहा कि वह पार्टी तोड़कर अपने 67 विधायकों के साथ मिलकर एक नई पार्टी बना लेंगे.

धर्मेन्द्र कुमार सिंह

पूरे मार्च महीने के दौरान और उसके बाद आम आदमी पार्टी के भीतर जो कुछ भी हुआ और हो रहा है, वह इस पार्टी के स्वराज, पारदर्शिता और अलग राजनीति के दावे को खोखला साबित करता है. मौजूदा घटनाक्रम से यह संदेश गया कि आम आदमी पार्टी एक व्यक्ति-केंद्रित पार्टी है. आम आदमी पार्टी का तर्क है कि प्रशांत भूषण एवं योगेंद्र यादव के ख़िलाफ़ कार्यवाही इसलिए की गई, क्योंकि वे पार्टी को चुनाव में हराना चाहते थे और उन्होंने शांति भूषण के साथ मिलकर पार्टी को हराने का हरसंभव प्रयास किया. ठीक है, अगर उनके ख़िलाफ़ पुख्ता सुबूत थे, तो उन पर कार्यवाही होनी ही चाहिए थी. लेकिन, इसी तर्क के आधार पर फिर अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ कार्यवाही क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि उन्होंने डंके की चोट पर एक स्टिंग में यह कहा कि वह पार्टी तोड़कर अपने 67 विधायकों के साथ मिलकर एक नई पार्टी बना लेंगे. पूरे घटनाक्रम के दौरान केजरीवाल ने यह संदेश दिया कि पार्टी में क्या होता है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है. इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक (चार मार्च) के दौरान वह इलाज कराने बंगलुरू चले गए. दूसरी बैठक यानी राष्ट्रीय परिषद के दौरान वह अपनी बात कहकर चले गए.

इसके अलावा, प्रशांत भूषण एवं योगेंद्र यादव को जिस तरीके से निकाला गया, वह भी ठीक नहीं था. निश्चित तौर पर उससे पार्टी की छवि खराब हुई है. कुछ और असहज सवाल हैं, जिनका जवाब पार्टी को देना होगा. गुटबंदी हर पार्टी में होती है, लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाही उनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए, जिन्होंने अनुशासनहीनता की हो या जनता के बीच पार्टी के निर्णय के ख़िलाफ़ कुछ कहा हो. प्रोफेसर आनंद कुमार के ख़िलाफ़ कार्यवाही क्यों की गई, यह नहीं बताया गया. मारलीना की प्रवक्ता पद से क्यों छुट्टी हुई, इसके लिए भी एक लुंजपुंज सा बहाना पेश किया गया. आम आदमी पार्टी में चल रही अंदरूनी लड़ाई का सबसे कुरूप चेहरा राष्ट्रीय परिषद की बैठक में दिखा, जब प्रशांत भूषण एवं योगेंद्र यादव को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया. भारी हंगामे और नाटकीय घटनाक्रम के बीच आनंद कुमार एवं अजीत झा को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाने के लिए राष्ट्रीय परिषद में प्रस्ताव पारित किया गया और आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए. केजरीवाल समर्थकों के मुताबिक, प्रशांत-योगेंद्र को बहुमत की मर्जी से राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर किया गया. जबकि योगेंद्र यादव एवं प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि बैठक के दौरान उनके समर्थकों के साथ मारपीट की गई. अनुशासन समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाने के बाद पार्टी ने असंतुष्ट नेताओं (योगेंद्र यादव एवं प्रशांत भूषण) को प्रवक्ता पद से भी हटा दिया.

कापसहेड़ा में राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू से ही हंगामेदार रही. बैठक शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया. वहां पर योगेंद्र यादव के पहुंचते ही केजरीवाल समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी. सदस्यों को अंदर प्रवेश दिए जाने को लेकर भी सवाल उठे. योगेंद्र यादव ने इस सबको लोकतंत्र की हत्या तक बताया. इस बैठक में आप के आंतरिक लोकपाल रामदास को भी आने से मना किया गया. लोकपाल की मांग को लेकर देश भर में बड़ा आंदोलन करने और इसी मुद्दे पर पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ने वाले केजरीवाल ने अपनी ही पार्टी के आंतरिक लोकपाल को हटा दिया. वह भी सिर्फ़ इसलिए, क्योंकि रामदास ने पार्टी के नीतिगत मुद्दों पर सवाल उठाए थे. अरविंद केजरीवाल पर स्टिंग में कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने और साथी नेताओं को गाली देने के आरोप भी सामने आए. इस सबके बाद आप नेता मेधा पाटकर ने मुंबई में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और पार्टी से अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया. उन्होंने दावा किया कि योगेंद्र और भूषण कभी भी पार्टी के ख़िलाफ काम नहीं कर सकते.

जाहिर है, इस पूरे घटनाक्रम के बाद से आम आदमी पार्टी की झाड़ू के एकजुट तिनके बिखरने लगे हैं. देश में लोकपाल की मांग करने वाली पार्टी ने अपने लोकपाल को ही बिना कारण बताए निकाल दिया. आंतरिक लोकतंत्र का नारा सिर्फ़ नारा भर रह गया है. सवाल उठाने वाले हर एक आदमी को पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है. नवनियुक्त तीन सदसयीय लोकपाल के एक अहम सदस्य राकेश सिन्हा को नियुक्ति के कुछ ही दिनों बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, सिर्फ़ इस वजह से कि उन्होंने रामदास को निकालने के मुद्दे पर सवाल उठाए थे. आप लोकपाल जनांदोलन से निकली पार्टी थी, जिसने आंतरिक लोकतंत्र और पारदर्शिता पर आधारित वैकल्पिक राजनीति का वादा किया था. लेकिन, आम आदमी पार्टी के आंतरिक घमासान में सिद्धांतों पर व्यक्तिगत मतभेद भारी पड़ रहे हैं. तो क्या वैकल्पिक राजनीति के सपने का अंत हो गया?■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार

अब बंगले पर राजनीति

सुकांत

नीतीश कुमार | भीम सिंह | वृषिण पटेल | जीतन राम मांझी | नरेन्द्र सिंह | नीतीश मिश्रा | राकेश कुमार

नीतीश कुमार के दशकों पुराने विशिष्ट सहयोगी के तौर पर विख्यात और राज्य के संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने साफ़ कहा है कि मांझी को अण्णे मार्ग स्थित बंगला खाली करना होगा, क्योंकि यह मुख्यमंत्री आवास के तौर पर चिन्हित है. सभी को क़ानून का पालन करना होगा. यह सभी को जान लेना चाहिए कि नीतीश राज में क़ानून अपना काम बखूबी करता है, कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो. श्रवण कुमार के इस बयान को गंभीरता से लिया जा रहा है. श्रवण जब कुछ बोलते हैं, तो ज़ुबान उनकी और बातें नीतीश कुमार की मानी जाती हैं. अब डॉ. मिश्र के पुत्र एवं पूर्व मंत्री नीतीश मिश्र ने भी अपने पिता के लिए सर्कुलर रोड स्थित उसी बंगले की मांग कर दी है.

जीतन राम मांझी सरकार में मंत्री रहे नेताओं की परेशानियों का अंत होता नहीं दिखता. उनकी विधायकी पर अनौपचारिक तौर पर तो पहले से ही तलवार लटक ही रही है, अब उनके बेघर होने की नौबत भी आ गई है. इन पूर्व मंत्रियों को बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा के अंदर सरकारी बंगले खाली करने के लिए कहा है. विभाग द्वारा मंत्रियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि उन्हें यह सरकारी आवास बतौर मंत्री मिला था और अब वह मंत्री नहीं रहे, लिहाजा उन्हें बंगला खाली करना होगा. यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर बंगला खाली नहीं किया जाता है, तो सरकार उचित कार्रवाई करेगी. यानी बंगले बलपूर्वक खाली कराए जाएंगे. भवन निर्माण विभाग ने बतौर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र को बेली रोड स्थित सरकारी बंगले का आवंटन भी रद्द कर दिया है. यह आवंटन जीतन राम मांझी सरकार ने किया था. तत्कालीन नीतीश सरकार ने डॉ. मिश्र को पूर्व मुख्यमंत्री के नाते हार्डिंग्ज रोड पर एक बंगला आवंटित किया था. बिहार सरकार के नए आदेश के तहत अब उन्हें हार्डिंग्ज रोड के बंगले में वापस जाना होगा.

मुख्यमंत्री आवास के तौर पर चिन्हित अण्णे मार्ग स्थित बंगले को लेकर सबसे रोचक और उत्तेजक माहौल बन गया है. मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के डेढ़ महीने बाद भी जीतन राम मांझी इस बंगले पर काबिज हैं. हालांकि, उनके लिए भवन निर्माण विभाग ने स्ट्रैंड रोड पर बंगला आवंटित किया है, लेकिन वह इतने मात्र से अपना बंगला खाली करने के लिए तैयार नहीं हैं. मांझी का कहना है कि पहले नीतीश कुमार उस बंगले को खाली करें, जो बतौर पूर्व मुख्यमंत्री उन्हें आवंटित किया गया था. मांझी का तर्क है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री हैं और इस नाते अण्णे मार्ग स्थित बंगला तो उन्हें मिलेगा ही, फिर दूसरा बंगला भी रखने का क्या औचित्य है? यह विवाद इसलिए पैदा हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अण्णे मार्ग स्थित सरकारी बंगले (मुख्यमंत्री आवास) से वह कामकाज निपटाएंगे, लेकिन रहेंगे सर्कुलर रोड स्थित बंगले में. नीतीश कुमार के दशकों पुराने विशिष्ट सहयोगी के तौर पर विख्यात और राज्य के संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने साफ़ कहा है कि मांझी को अण्णे मार्ग स्थित बंगला खाली करना होगा, क्योंकि यह मुख्यमंत्री आवास के तौर पर चिन्हित है. सभी को क़ानून का पालन करना होगा. यह सभी को जान लेना चाहिए कि नीतीश राज में क़ानून अपना काम बखूबी करता है, कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो. श्रवण कुमार के इस बयान को गंभीरता से लिया जा रहा है. श्रवण जब कुछ बोलते हैं, तो ज़ुबान उनकी और बातें नीतीश कुमार की मानी जाती हैं. अब डॉ. मिश्र के पुत्र एवं पूर्व मंत्री नीतीश मिश्र ने भी अपने पिता के लिए सर्कुलर रोड स्थित उसी बंगले की मांग कर दी है. उनका कहना है कि नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री अण्णे मार्ग स्थित बंगला मिलना ही है, लिहाजा डॉ. जगन्नाथ मिश्र के नाम पर सर्कुलर रोड स्थित बंगला आवंटित किया जाए.

बिहार के राजनीतिक हलकों में बंगला प्रकरण खासा रोचक बन गया है. राजनीति और सरकार में माना जाता रहा है कि मंत्री पद से मुक्त होने के बाद किसी भी राजनेता को एक महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली कर देना है. उसे वे सारी सुविधाएं भी त्याग देनी हैं, जो बतौर मंत्री मिली थीं. यह आदर्श स्थिति है, जो सामान्यत: दिखती नहीं है. बिहार में तो इसका पालन कभी हुआ ही नहीं. जद (यू) और भाजपा के अलग-अलग होने के बाद भाजपा के मंत्रियों को भी नोटिस जारी किया गया था, पर किसी ने नोटिस को तवज्जो नहीं दी. वस्तुत: आज की राजनीति में जिन सुविधाओं को राजनेता की हैसियत (स्टेटस) का पैमाना मान लिया गया है, उनमें सरकारी बंगला, बॉडीगार्ड और अन्य तामझाम शामिल हैं. ऐसे में कोई बड़े-बड़े सरकारी बंगले कैसे खाली करेगा! पर, मंत्री होने के साथ राजनेता विधान मंडल के किसी सदन के सदस्य भी होते हैं, इसलिए जिन्हें बंगला खाली करने का नोटिस मिला है, उनके आवास की व्यवस्था विधान मंडल प्रशासन ने की है या नहीं, यह महत्वपूर्ण है. विधान मंडल प्रशासन द्वारा उन्हें आवास उपलब्ध कराए जाने की बात अभी तक सामने नहीं आई है. ऐसे में, पूर्व मंत्रियों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था के बगैर बंगला खाली कराना विवेक सम्मत कतई नहीं है. जिन राजनेताओं को बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है, उनमें वे लोग भी शामिल हैं, जो पच्चीस-तीस वर्षों से विधायक हैं.

यदि मांझी के निकटवर्ती सूत्रों पर भरोसा करें, तो इस समूह का मानना है कि बंगला खाली न किया जाए, सरकार चाहे तो बल प्रयोग करके बंगला खाली करा ले. यह उनकी राजनीति का हिस्सा है. बीते फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में नीतीश कुमार की बतौर मुख्यमंत्री चौथी पारी शुरू हुई है और फरवरी की अंतिम तारीख से जीतन राम मांझी ने नीतीश विरोधी अभियान छेड़ दिया है. इस अभियान का चुनावी राजनीति में क्या असर होगा, यह कहना अभी कठिन है.

बंगला प्रकरण राजनीतिक रूप ग्रहण करता जा रहा है. जीतन राम मांझी और उनके साथी पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह, वृषिण पटेल, सम्राट चौधरी, शाहिद अली खान, महाचंद्र प्रसाद सिंह, नीतीश मिश्र एवं भीम सिंह आदि आवास खाली करने को कतई तैयार नहीं दिखते. मंत्री न रहने के कारण उन्हें भवन निर्माण विभाग नहीं, विधान मंडल के पूल से आवास मिलने हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें विधान मंडल प्रशासन से अनुरोध करना होगा, जो उन्होंने अब तक नहीं किया है और शायद करने का विचार भी नहीं है. यदि मांझी के निकटवर्ती सूत्रों पर भरोसा करें, तो इस समूह का मानना है कि बंगला खाली न किया जाए, सरकार चाहे तो बल प्रयोग करके बंगला खाली करा ले. यह उनकी राजनीति का हिस्सा है. बीते फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में नीतीश कुमार की बतौर मुख्यमंत्री चौथी पारी शुरू हुई है और फरवरी की अंतिम तारीख से जीतन राम मांझी ने नीतीश विरोधी अभियान छेड़ दिया है. इस अभियान का चुनावी राजनीति में क्या असर होगा, यह कहना अभी कठिन है. बिहार में नीतीश कुमार को सुशासन बाबू और विकास पुरुष जैसे विशेषण हासिल हैं, लेकिन इस चौथी पारी में अपने उक्त विशेषण बचा पाने में वह कामयाब होंगे अथवा नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है. विधि व्यवस्था लागू करने या विकास की गाड़ी पटरी पर लाने के लिए उन्हें बगैर समय गंवाए तेजी से काम करना है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं अधिकारियों को सुस्ती त्याग कर काम की रफ्तार बढ़ाने को कहा है. नीतीश को सत्ता की राजनीति हो या प्रशासन, एक बड़ी लकीर खिंचनी होगी. और, यह उनके लिए मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि वह तो इसके माहिर रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया में ख़बर छपने और संसद में आवाज़ उठने से बौखलाए एनटीपीसी के सीएमडी ने

सांसदों को पटाने के लिए पंच सितारा होटल में भोज दी

चौथी दुनिया के ख़िलाफ़ बंटवाए जा रहे हैं अशालीन-अभद्र पर्चे

अंदरूनी विभागीय कार्रवाई में एनटीपीसी ने चौथी दुनिया के प्रधान संपादक को गवाह बनाया

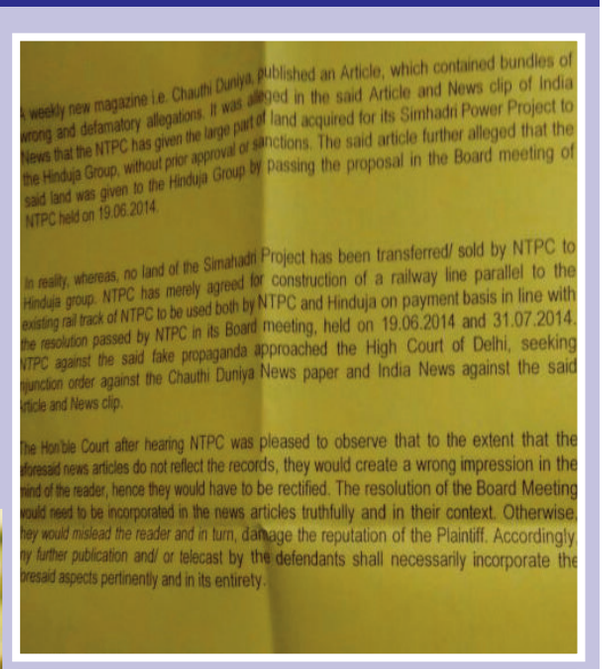

A weekly new magazine i.e. Chauthi Duniya, published an Article, which contained bundles of wrong and defamatory allegations. It was alleged in the said Article and News clip of India News that the NTPC has given the large part of land acquired for its Simhadri Power Project to the Hinduja Group, without prior approval or sanctions. The said article further alleged that the said land was given to the Hinduja Group by passing the proposal in the Board meeting of NTPC held on 19.06.2014.

In reality, whereas, no land of the Simahadri Project has been transferred/ sold by NTPC to Hinduja group. NTPC has merely agreed for construction of a railway line parallel to the existing rail track of NTPC to be used both by NTPC and Hinduja on payment basis in line with the resolution passed by NTPC in its Board meeting, held on 19.06.2014 and 31.07.2014. NTPC against the said fake propaganda approached the High Court of Delhi, seeking injunction order against the Chauthi Duniya News paper and India News against the said Article and News clip.

The Hon'ble Court after hearing NTPC was pleased to observe that to the extent that the aforesaid news articles do not reflect the records, they would create a wrong impression in the mind of the reader, hence they would have to be rectified. The resolution of the Board Meeting would need to be incorporated in the news articles truthfully and in their context. Otherwise, they would mislead the reader and in turn, damage the reputation of the Plaintiff. Accordingly, any further publication and/ or telecast by the defendants shall necessarily incorporate the aforesaid aspects pertinently and in its entirety.

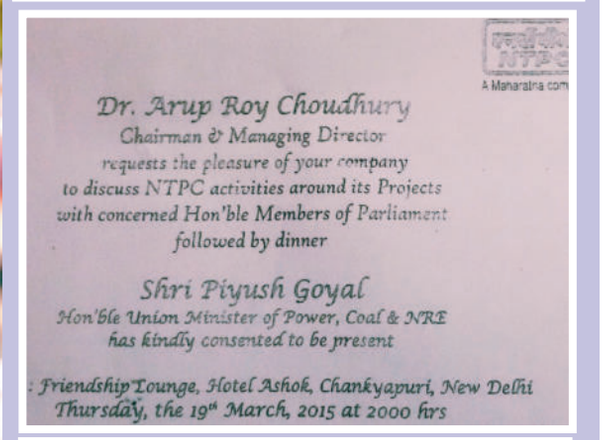

Dr. Arup Roy Choudhury
Chairman & Managing Director
requests the pleasure of your company
to discuss NTPC activities around its Projects
with concerned Hon'ble Members of Parliament
followed by dinner

Shri Piyush Goyal
Hon'ble Union Minister of Power, Coal & NRE
has kindly consented to be present

Friendship Lounge, Hotel Ashok, Chankyapuri, New Delhi
Thursday, the 19th March, 2015 at 2000 hrs

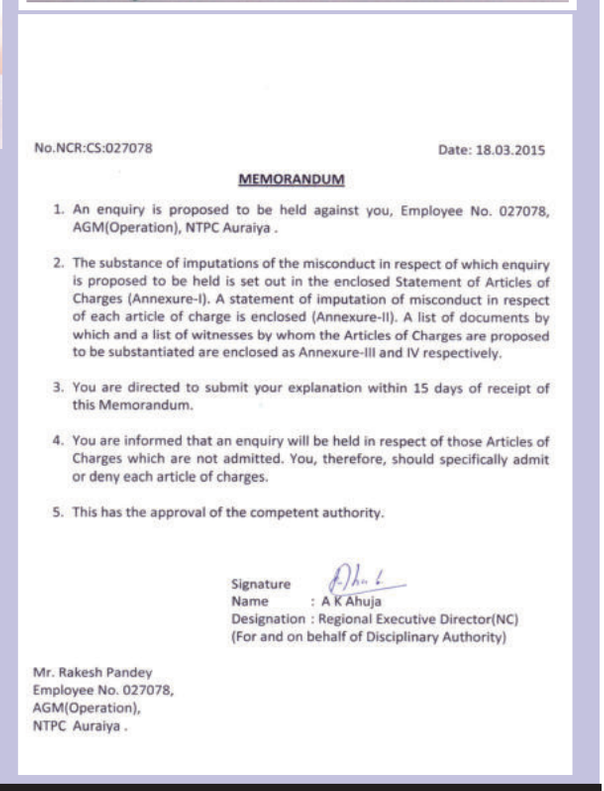

No.NCR:CS:027078 Date: 18.03.2015

MEMORANDUM

1. An enquiry is proposed to be held against you, Employee No. 027078, AGM(Operation), NTPC Auraiya .
2. The substance of imputations of the misconduct in respect of which enquiry is proposed to be held is set out in the enclosed Statement of Articles of Charges (Annexure-I). A statement of imputation of misconduct in respect of each article of charge is enclosed (Annexure-II). A list of documents by which and a list of witnesses by whom the Articles of Charges are proposed to be substantiated are enclosed as Annexure-III and IV respectively.
3. You are directed to submit your explanation within 15 days of receipt of this Memorandum.
4. You are informed that an enquiry will be held in respect of those Articles of Charges which are not admitted. You, therefore, should specifically admit or deny each article of charges.
5. This has the approval of the competent authority.

Signature
Name : A K Ahuja
Designation : Regional Executive Director(NC)
(For and on behalf of Disciplinary Authority)

Mr. Rakesh Pandey
Employee No. 027078,
AGM(Operation),
NTPC Auraiya .

प्रभात रंजन दीन

नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) के सीएमडी अरूप रॉय चौधरी की करतूतों के ख़िलाफ़ चौथी दुनिया के विभिन्न संस्करणों में ख़बर प्रकाशित होने के बाद रॉय चौधरी ने चौथी दुनिया के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक पर्चेबाजी शुरू कर दी है. सीएमडी के इशारे पर ये पर्चे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वितरित किए जा रहे हैं और अख़बारों में संलग्न किए जा रहे हैं. सीएमडी रॉय चौधरी की बौखलाहट इसलिए भी है कि चौथी दुनिया की ख़बर को संज्ञान में लेकर भाजपा सांसद कौशल किशोर ने एनटीपीसी के भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ संसद में मामला उठा दिया और प्रधानमंत्री से सीएमडी को बर्खास्त करने की मांग की. संसद में आवाज़ उठते ही अरूप रॉय चौधरी ने पेशबंदी की व्याकुल हरकतें शुरू कर दीं. उन्होंने देश के ऊर्जा मंत्री और सांसदों को पटाने के इरादे से 19 मार्च को दिल्ली के आलीशान अशोका होटल में शानदार डिनर का आयोजन कर डाला. पंच सितारा होटल में डिनर आयोजित करते हुए एनटीपीसी के सीएमडी यह भी भूल गए कि केंद्र सरकार ने बाकायदा अधिसूचना जारी करके किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (पीएसयू) द्वारा पंच सितारा होटलों में ऐसे खर्चीले आयोजन करने पर पाबंदी लगा रखी है. सवाल यह भी है कि जब ढेरों सांसदों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया, तो उस सांसद को क्यों छोड़ दिया गया, जिसने सीएमडी के घोटालों को संसद तक पहुंचाया था?

चौथी दुनिया के ख़िलाफ़ बंटवाए जा रहे पर्चे में आपत्तिजनक और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और सीएमडी ने अपनी करतूतों को एनटीपीसी के कंधे पर थोपने की कोशिश की है. एनटीपीसी की सिमाद्री परियोजना की ज़मीन हिंदुजा समूह को दिए जाने के अवैध प्रयासों के बारे में छपी ख़बर पर सीएमडी ने पर्चे के ज़रिये सफाई देने की कोशिश की है. उस सफाई में भी खुद दायित्व स्वीकार करने के बजाय एनटीपीसी को ही आगे किया गया है. चौथी दुनिया के सभी भाषा संस्करणों यथा, हिंदी–अंग्रेजी–उर्दू में ख़बर प्रकाशित होने के बाद एनटीपीसी के सीएमडी को अगर कोई आपत्ति थी, तो नियमत: उन्हें अख़बार से संपर्क करके औपचारिक रूप से अपना पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नियम का पालन करना उचित नहीं समझा और बेजा हरकतों पर उतरना अधिक उपयुक्त समझा. बेचैनी इतनी ज़्यादा थी कि एनटीपीसी एक्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया (नेफी) के अध्यक्ष राकेश पांडेय के ख़िलाफ़ जो विभागीय चार्जशीट जारी की गई, उसमें एनटीपीसी प्रबंधन ने चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय का नाम गवाह (विटनेस) के रूप में डाल दिया. इस बारे में श्री भारतीय समेत अख़बार के सभी लोग हैरत में हैं कि एनटीपीसी अपनी अंदरूनी कार्रवाइयों में बाहरी लोगों को घसीटने की हरकतों पर क्यों उतारू है!

बहरहाल, 19 मार्च को दिल्ली के आलीशान अशोका होटल में आयोजित भव्य डिनर कार्यक्रम में थोड़ी देर के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे ज़रूर, लेकिन माजरा समझ कर वह कुछ ही मिनटों में वहां से चले गए. डिनर के लिए छपे आमंत्रण कार्ड पर बाकायदा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का नाम प्रकाशित किया गया था. कार्ड पर यह भी लिखा था कि डिनर के साथ–साथ प्रोजेक्ट पर विचार–विमर्श भी किया जाएगा, लेकिन डिनर के आयोजन में प्रोजेक्ट पर डिस्कशन तो एक बहाना भर था. यही साबित भी हुआ और सुस्वादु डिनर में डिस्कशन विलुप्त हो गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल को केंद्र सरकार की अधिसूचना का हवाला देते हुए पंच सितारा होटल में किए गए ग़ैर–क़ानूनी डिनर आयोजन को संज्ञान में लेने का औपचारिक आग्रह किया गया है. प्रमुख समाजसेवी महेंद्र अग्रवाल ने नवरत्नों में शुमार एनटीपीसी को भ्रष्टाचारियों और अराजक तत्वों के चंगुल से निजात दिलाने की अपील की है और सीएमडी की करतूतों की पूरी फेहरिस्त भेजी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

महाकुंभ घोटाला

निशंक पर जांच की आंच पड़नी तय

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पर उनके कार्यकाल में संपन्न हुए हरिद्वार महाकुंभ घोटाले की जांच की आंच पड़नी तय मानी जा रही है. राज्य सूचना आयोग ने 2010 के हरिद्वार महाकुंभ घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है. राज्य सूचना आयुक्त इसके पहले राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की दवाओं के मामले में भी राज्य सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुके हैं, जिसे सरकार ने मान लिया था. महाकुंभ घोटाले को 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मुद्दा भी बनाया था. 2010 में प्रदेश में भाजपा सत्ता में थी. सूचना आयुक्त अनिल कुमार शर्मा ने महाकुंभ घोटाले से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री के सचिव को भेजे गए अपने पत्र में कहा है कि कुंभ आयोजन के लिए आवंटित 565 करोड़ रुपये के इस्तेमाल की केंद्र सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि 180.07 करोड़ रुपये की लागत के कार्य निर्माण के अभाव में 31 जुलाई, 2010 तक अपूर्ण रहे थे. इन 180.07 करोड़ रुपयों का हिसाब–किताब न तो शासन ने दिया और न मेलाधिकारी कार्यालय हरिद्वार ने. यही नहीं, शासन ने भी हिसाब–किताब की खोजबीन का कोई सार्थक प्रयास किसी जांच एजेंसी से नहीं कराया. ऐसी परिस्थिति में जनहित एवं राजस्व हित में गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई से कराई जाए. चूंकि आवंटित धन केंद्र सरकार का था, इसलिए इसके खर्च के हिसाब–किताब की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराना न्याय हित में आवश्यक है. सूचना आयुक्त ने इस संबंध में अपीलार्थी से प्रार्थना–पत्र देने को कहा है.

ग़ौरतलब है कि धर्मशाला माई गिंदा कुंवर बरेली ट्रस्ट सुभाष घाट हरिद्वार के ट्रस्टी रमेश चंद्र शर्मा ने कई आरटीआई याचिकाओं के ज़रिये शासन और मेलाधिकारी से महाकुंभ के विभिन्न अधूरे निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी मांगी थी. जब उन्हें सूचनाएं नहीं मिलीं, तो उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील कर दी. शर्मा का कहना था कि कुंभ मेले के आयोजन के लिए केंद्र से मिले 180 करोड़ रुपये का कोई हिसाब–किताब नहीं है. कांग्रेस नीत संप्रग सरकार ने राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार को मेले के आयोजन के लिए 565 करोड़ रुपये का अनुदान दिया था. मेले के दौरान लोकहित के 54 कार्य पूरे नहीं हो सके. इससे दुनिया भर से हरिद्वार आए लाखों श्रद्धालुओं को असुविधाओं का सामना करना पड़ा. कैग की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि राज्य सरकार के 34 विभागों के 311 कार्यों के लिए 565 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिनमें से 180 करोड़ रुपये के 54 कार्य अधूरे रह गए. जानकारी होने पर भी तत्कालीन राज्य सरकार ने मामले की जांच नहीं कराई. सूचना आयुक्त ने रमेश चंद्र शर्मा की ओर से उठाए गए विषयों पर संज्ञान लिया और मामले का निस्तारण करते हुए कहा कि इतनी बड़ी धनराशि का हिसाब न तो शासन दे रहा है और न मेलाधिकारी कार्यालय. उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात तो यह है कि शासन इस मामले की जांच कराना भी उचित नहीं समझ रहा. इसके बाद आयोग ने सीबीआई जांच की सिफारिश करते हुए मुख्यमंत्री के सचिव को अपने पत्र की प्रति भेज दी. मुख्यमंत्री के सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाए, ताकि वह मामले की सीबीआई जांच का फ़ैसला ले सकें.

राज्य सूचना आयुक्त अनिल कुमार शर्मा के आदेश पर कुंभ मेला अधिकारी सह लोक सूचनाधिकारी ने आवेदक रमेश चंद्र शर्मा को जो सूचनाएं मुहैया कराई हैं, उनसे साफ़ है कि शासन महाकुंभ–2010 में हुई 180 करोड़ रुपये की अनियमितताओं के प्रति बेपरवाह रहा. 54 अधूरे निर्माण कार्यों की लागत के 180.07 करोड़ रुपये नोडल अधिकारियों की लापरवाही के चलते तब मेलाधिकारी कार्यालय में जमा नहीं कराए गए और न शहरी विकास विभाग ने शासन की किसी भी एजेंसी से इसकी जांच कराने की ज़िम्मेदारी निभाई.

राज्य सूचना आयुक्त अनिल कुमार शर्मा के आदेश पर कुंभ मेला अधिकारी सह लोक सूचनाधिकारी ने आवेदक रमेश चंद्र शर्मा को जो सूचनाएं मुहैया कराई हैं, उनसे साफ़ है कि शासन महाकुंभ–2010 में हुई 180 करोड़ रुपये की अनियमितताओं के प्रति बेपरवाह रहा. 54 अधूरे निर्माण कार्यों की लागत के 180.07 करोड़ रुपये नोडल अधिकारियों की लापरवाही के चलते तब मेलाधिकारी कार्यालय में जमा नहीं कराए गए और न शहरी विकास विभाग ने शासन की किसी भी एजेंसी से इसकी जांच कराने की ज़िम्मेदारी निभाई. यही नहीं, सूचनाएं देने के लिए आवेदक को पौने पांच साल तक टरकाया जाता रहा. रमेश चंद्र शर्मा ने जुलाई 2010 में महाकुंभ के बाबत सूचनाएं मांगी थीं, जिनमें से कुछ इस साल तीन मार्च को राज्य सूचना आयोग के दखल के बाद मिल सकीं. रमेश चंद्र शर्मा ने पूछा था कि बची हुई 180.07 करोड़ रुपये की धनराशि में से कितनी धनराशि किस रूप में शहर के विकास में इस्तेमाल हुई है और अवशेष धनराशि किस खाता संख्या के माध्यम से राजकोष में जमा कराई गई. ■

feedback@chauthiduniya.com

फरवरी 2010 में सपा से निष्कासित होने के बाद अमर सिंह पांच अगस्त, 2014 को जनेश्वर मिश्र की जयंती पर सपा के सार्वजनिक मंच पर प्रकट हुए थे. छोटे लोहिया कहे जा रहे जनेश्वर मिश्र के नाम पर बने पार्क के लोकार्पण समारोह में अमर सिंह खास तौर पर न्यौते गए मेहमान थे. उन्हें यह न्यौता खुद मुलायम सिंह यादव ने दिया था. इस आमंत्रण पर आजम खान एवं प्रोफेसर राम गोपाल यादव जैसे दिग्गज नाराज़ भी हो गए थे और कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए थे. तब कहा गया था कि अमर सिंह राज्यसभा की सांसदी बचाने के लिए व्याकुल हैं, लेकिन उस कथित व्याकुलता का कोई नतीजा नहीं निकला.

यूं ही नहीं मुलायम कह रहे अमर-अमर!

प्रभात रंजन दीन

बेनी प्रसाद वर्मा और अमर सिंह फिर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे. इन दिनों यह चर्चा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के स्तर पर सरगर्म है. मुलायम सिंह यादव के अस्वस्थ होने पर बेनी प्रसाद वर्मा उनसे उनके घर पर जाकर मिले थे. मुलायम का हाल-चाल लेने अमर सिंह गुड़गांव के मेदांता अस्पताल तक गए थे. स्वस्थ होने के बाद घर लौटे मुलायम सिंह ने अमर सिंह की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की. बेनी पर अभी मुलायम चुप हैं. इस चुप्पी के तकनीकी कारण भी हैं. 2017 का विधानसभा चुनाव दरवाजा खटखटाए, उसके पहले ही सपाई परिवार के पुराने सदस्यों को घर में दाखिल करा लेना चाहते हैं अभिभावक मुलायम सिंह यादव. अमर सिंह की प्रशंसा तब हुई, जब पार्टी के अन्य नेताओं के बारे में मुलायम अपनी नकारात्मक राय रख रहे थे. मसलन, सपा नेता पढ़ते-लिखते नहीं, उन्हें कोई जानकारी नहीं रहती, वे खुद चापलूस हैं और चापलूसों से घिरे रहते हैं, वे पार्टी कार्यकर्ताओं के कामकाज पर न नज़र रख सकते हैं और न उन्हें कोई सीख देने की क्षमता रखते हैं. ऐसे नेता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को महत्वपूर्ण जानकारियां या सलाह कैसे दे सकते हैं, वगैरह-वगैरह. मुलायम ने यह कहते हुए अमर सिंह की खूब तारीफ़ की. यानी अमर सिंह में वे सारी खूबियां हैं, जो अन्य नेताओं में नहीं हैं.

स्वाभाविक है कि इस तारीफ़ का ताप कई नेताओं के ऊपर चढ़ा होगा. उनमें से कई नेताओं को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मंडल में अमर सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा को सपा में वापस लाने के बारे में हुए विचार और सहमति की जानकारी नहीं है. जानकारी होती, तो उन्हें समझ में आ जाता कि लोहिया जयंती के मौक़े पर अमर सिंह की सार्वजनिक प्रशंसा और उसके तीन दिन बाद ही अमर सिंह और मुलायम की लखनऊ में हुई मुलाकात आकस्मिक नहीं, बल्कि सोची-समझी थी. अब अमर-जयाप्रदा और बेनी की पार्टी में वापसी के तौर-तरीकों के बारे में मंथन हो रहा है. इसके पहले अमर सिंह ने प्रोफेसर राम गोपाल यादव और आजम खान के प्रति मुलायमियत भरे शब्दों का सार्वजनिकीकरण करना शुरू कर दिया है. सपा प्रमुख मुलायम से मिली सराहना के चौथे दिन अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात क़रीब घंटे भर चली. स्वाभाविक है कि घंटे भर की मुलाकात में केवल कुशलक्षेम ही नहीं पूछा गया होगा. यह सियासी ज़रूरत है कि दोनों के बीच हुई बातचीत फिलहाल जग-जाहिर न हो, लेकिन पार्टी में चर्चाओं को कौन रोक सकता है. मुलायम से मिलकर बाहर निकले अमर ने इतना ही कहा कि लोहिया जयंती पर मुलायम ने उनकी जो सराहना की थी, वह उनके उस बड़प्पन का शुक्रिया अदा करने गए थे. अखिलेश से मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री से नहीं, बल्कि अपने भतीजे से मिलने गए थे. अगर मुख्यमंत्री से मिलने जाते, तो घंटा भर नहीं रुकते, 10-15 मिनट में ही लौट आते. सपा में वापसी के बारे में अमर ने चुप्पी साध ली. इन सब बातों-संवादों के अपने निहितार्थ हैं.

राजनीतिक प्रेक्षक भी यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार होने के बावजूद समाजवादी पार्टी संक्रमण की स्थितियों से गुजर रही है, इसलिए पार्टी के विभिन्न रंग पटल पर आ रहे हैं. सरकार में शामिल मंत्रियों के भ्रष्टाचार का मसला हो या सपा नेताओं की गद्दारी का, भ्रष्ट मंत्रियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न करने की मुख्यमंत्री अखिलेश की जिद हो या पार्टी में नेतृत्व के स्तर पर गहरा रही खेमेबंदी हो, यह सारी स्थिति पार्टी का भीषण नुक़सान कर रही है.

सपा से टिकट चाहिए, तो लोहिया को पढ़ो

मुलायम सिंह यादव ने कहा कि पार्टी का टिकट लेने वालों के लिए शर्त होगी कि वह लोहिया को पढ़ें. जो लोहिया को पढ़ेगा, उसे ही टिकट मिलेगा. मुलायम ने कहा कि सिर्फ़ नारेबाजी और तारीफ़ों से काम नहीं चलेगा. समाजवादी पार्टी में पदाधिकारियों और टिकटार्थियों के लिए पहले लोहिया को पढ़ने और समझने की शर्त होगी. समाजवादी आंदोलन बड़े संघर्ष और कुर्बानियों से आगे बढ़ा है. इसके इतिहास और नेतृत्व के बारे में नौजवानों को जानना चाहिए. बड़े संघर्ष के बाद पार्टी सत्ता में आई है. हमें लोहिया के सिद्धांतों पर चलना होगा.

जो शख्स यह कहता हो कि करगिल के युद्ध में केवल मुसलमानों ने शहादत दी, वह किसी भी स्तर पर नीचे गिर सकता है. ऐसा कहना शहीदों और देश का अपमान है. शहीद का कोई धर्म नहीं होता, वह केवल हिंदुस्तानी होता है. अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा. और, यह आजम खान देश और सेना पर कटाक्ष कर रहा है! तो यह किसे छोड़ देगा! क्या यह मुलायम, अखिलेश और शिवपाल को छोड़ देगा! खैर, अब यह समय पर है कि सपा की सियासत किसे छोड़ती है और किसे पकड़ती है.

राजनीतिक प्रेक्षक भी यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार होने के बावजूद समाजवादी पार्टी संक्रमण की स्थितियों से गुजर रही है, इसलिए पार्टी के विभिन्न रंग पटल पर आ रहे हैं. सरकार में शामिल मंत्रियों के भ्रष्टाचार का मसला हो या सपा नेताओं की गद्दारी का, भ्रष्ट मंत्रियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न करने की मुख्यमंत्री अखिलेश की जिद हो या पार्टी में नेतृत्व के स्तर पर गहरा रही खेमेबंदी हो, यह सारी स्थिति पार्टी का भीषण नुक़सान कर रही है.

...तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेगी सपा

समाजवादी पार्टी में तमाम अंदरूनी खींचतान के बीच जनता दल परिवार को एक छत के नीचे लाने की तैयारी को औपचारिक शक्ल देने की कवायद चल रही है. समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव इस परिवार के नेता तो होंगे ही, लेकिन नेतृत्व का विकेंद्रीकरण कैसे होगा और समाजवादी पार्टी के नेता-कार्यकर्ता किस-किसको अपना नेता मानेंगे, इसे लेकर भीषण पचड़ा फंसा हुआ है. जनता परिवार का नाम क्या होगा, इस पर भी मतभेद है. समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सपा का नाम बदले जाने को लेकर कतई सहमत नहीं हैं. उनका कहना है कि जिस नाम को इतने संघर्षों के बाद स्थापित किया गया, उसे बदलना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा. तब, जबकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सामने है. पार्टी का चुनाव चिन्ह (सिंबल) और झंडा जैसे महत्वपूर्ण मसले भी फंसे हुए हैं. पहले तय हुआ था कि सपा के साइकिल चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ा जाए और जनता दल परिवार का भी यही अधिकारिक सिंबल हो, लेकिन दक्षिण में तेलगुदेशम पार्टी का भी चुनाव चिन्ह यही है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में नेशनल पैंथर्स पार्टी, केरल में केरल कांग्रेस और मणिपुर में मणिपुर पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह भी साइकिल है. इससे जनता दल परिवार के राष्ट्रीय पार्टी होने पर चुनाव चिन्ह का मसला खड़ा होगा. जनता परिवार का झंडा कैसा हो, इस पर भी तमाम परस्पर विरोध और अंतर्विरोध के बीच प्रयास जारी है. नई पार्टी के संविधान और राजनीतिक एजेंडे पर भी अभी फ़ैसला होना बाकी है.

फरवरी 2010 में सपा से निष्कासित होने के बाद अमर सिंह पांच अगस्त, 2014 को जनेश्वर मिश्र की जयंती पर सपा के सार्वजनिक मंच पर प्रकट हुए थे. छोटे लोहिया कहे जा रहे जनेश्वर मिश्र के नाम पर बने पार्क के लोकार्पण समारोह में अमर सिंह खास तौर पर न्यौते गए मेहमान थे. उन्हें यह न्यौता खुद मुलायम सिंह यादव ने दिया था. इस आमंत्रण पर आजम खान एवं प्रोफेसर राम गोपाल यादव जैसे दिग्गज नाराज़ भी हो गए थे और कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए थे. तब कहा गया था कि अमर सिंह राज्यसभा की सांसदी बचाने के लिए व्याकुल हैं, लेकिन उस कथित व्याकुलता का कोई नतीजा नहीं निकला. अमर सिंह राज्यसभा की सांसदी नहीं बचा पाए, लेकिन उसके बाद भी उनकी सपा प्रमुख से मुलाकातें होती रहीं. सपा नेताओं का एक खेमा अमर सिंह को पार्टी में फिर से शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को कुछ नेताओं की नहीं, बल्कि पार्टी के भविष्य की चिंता है. मुलायम अब समाजवादी पार्टी के तमाम अनुत्पादक तत्वों को किनारे करना चाहते हैं, इसलिए वह पार्टी को बार-बार यह एहसास करा रहे हैं कि अमर सिंह जब पार्टी में थे, तो उन्होंने पार्टी के लिए क्या-क्या किया था. लोकसभा चुनाव में स्वनामधन्य दिग्गजों ने क्या प्रदर्शन किया और उसका क्या नतीजा निकला, उसे सब देख चुके हैं. लिहाजा पार्टी में यह समय आ गया है कि ग़ैर-उत्पादक नेताओं और उत्पादक नेताओं के बीच स्पष्ट लाइन खींची जाए. मुलायम यही चाहते हैं. उनके स्वास्थ्य ने उनकी इस चिंता को और प्रगाढ़ किया है.

अमर सिंह ने पिछले दिनों चौथी दुनिया से बात करते हुए कहा था, भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए. लिहाजा वर्तमान यही है कि अमर सिंह की सपा में वापसी की तैयारियां शुरू हैं. सपा में आने की फिर से शुरू चर्चा पर अमर सिंह ने कहा था, मैं क्या करूं, अगर चर्चा होती है तो. मैं कुछ भी करता हूं, तो चर्चा होती है और बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, तो चर्चा नहीं होती. यही तो मलाल है लोगों को, तो इसके लिए मैं क्या करूं? लेकिन, इन चर्चाओं के बरक्स अमर सिंह अगर यह भी कहते हैं कि सियासत की अपनी ज़ुबान होती है, लिखा हो इंकार तो इकरार पढ़ना, तो उसके गहरे मायने हैं ही. सियासत की इस ज़ुबान के गहरे अर्थ के नज़रिये से देखें, तो अमर की बातें समझ में आती हैं. इस बार आजम खान और राम गोपाल यादव के लिए अमर सिंह का सुर पूरी तरह बदला हुआ था, लेकिन पिछली बार उन्होंने ही कहा था, आजम खान जैसे लोग देश, समाज और राजनीति की विसंगति हैं. मैं आजम की दुनिया का कभी हो नहीं सकता. जो शख्स यह कहता हो कि करगिल के युद्ध में केवल मुसलमानों ने शहादत दी, वह किसी भी स्तर पर नीचे गिर सकता है. ऐसा कहना शहीदों और देश का अपमान है. शहीद का कोई धर्म नहीं होता, वह केवल हिंदुस्तानी होता है. अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा. और, यह आजम खान देश और सेना पर कटाक्ष कर रहा है! तो यह किसे छोड़ देगा! क्या यह मुलायम, अखिलेश और शिवपाल को छोड़ देगा! खैर, अब यह समय पर है कि सपा की सियासत किसे छोड़ती है और किसे पकड़ती है.

स्वाभाविक है कि इस तारीफ़ का ताप कई नेताओं के ऊपर चढ़ा होगा. उनमें से कई नेताओं को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मंडल में अमर सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा को सपा में वापस लाने के बारे में हुए विचार और सहमति की जानकारी नहीं है. जानकारी होती, तो उन्हें समझ में आ जाता कि लोहिया जयंती के मौक़े पर अमर सिंह की सार्वजनिक प्रशंसा और उसके तीन दिन बाद ही अमर सिंह और मुलायम की लखनऊ में हुई मुलाकात आकस्मिक नहीं, बल्कि सोची-समझी थी.

जया बच्चन पर गुस्सा निकल ही आया

राम गोपाल और आजम के लिए संयत शब्दों का इस्तेमाल करने वाले अमर सिंह जया बच्चन पर अपना गुस्सा रोक नहीं पाए. अमर ने कहा कि जया बच्चन जैसे लोग केवल एसी में बैठकर राजनीति करते हैं और एमपी बन जाते हैं. इन जैसे लोगों ने गांव-गांव जाकर काम किया होता, तो नतीजे कुछ और होते. अमर सिंह ने आजम खान से मतभेद से इंकार किया और कहा कि आजम से उनका कोई बैर नहीं है. आजम से उनका मतभेद केवल रामपुर के चुनाव तक ही सीमित था, जयाप्रदा वहां से चुनाव लड़ रही थीं और अब उन्होंने रामपुर छोड़ दिया, तो कोई विवाद ही नहीं बचा.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चाहे जितना भी कहें कि उत्तर प्रदेश में जनता की सरकार है और जनता के विचारों पर सरकार काम कर रही है, लेकिन उनका यह बयान छद्म है, ज़मीनी हक़ीक़त उससे अलग और विद्रूप है. मुख्यमंत्री चाहे कितना भी कहते रहें कि समाजवादी पार्टी की सरकार नेताजी के रास्ते पर चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का यह बयान छद्म है, क्योंकि मुलायम बार-बार भ्रष्ट मंत्रियों की करतूतों का जिक्र करते रहे, सार्वजनिक मंचों से मुख्यमंत्री को ललकारते रहे, लेकिन अखिलेश पर इसका कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा और उन्होंने भ्रष्ट एवं चाटुकार मंत्रियों पर कोई कार्रवाई नहीं की. मुलायम के यह कहते-कहते तीन वर्ष बीत गए. परेशान मुलायम ने पिछले दिनों यह भी कह दिया कि पार्टी के कुछ लोग उनकी निगरानी कर रहे हैं, उनकी जासूसी करा रहे हैं. वे यह जानकारी लेने में लगे रहते हैं कि लखनऊ से दिल्ली तक मैं किनसे मिल रहा हूं, क्या बातें कर रहा हूं. संपूर्ण विपक्ष ने मुलायम के इस बयान को अत्यंत गंभीर बताया. बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा कि यदि सत्ताधारी दल के मुखिया अपने ही लोगों पर जासूसी का आरोप लगा रहे हैं, तो यह एक गंभीर मामला है. इस पर सपा सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए. इससे ज़्यादा शर्मनाक हालत अखिलेश सरकार के लिए कुछ और नहीं हो सकती. मौर्य ने कहा कि सपा सरकार की अराजकता अब मुलायम सिंह यादव के मुंह से अभिव्यक्त हो रही है और इसकी जांच कराई जानी चाहिए कि उनकी जासूसी कौन करा रहा है. भाजपा प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने भी कहा कि सपा प्रमुख खुद कह रहे हैं कि पार्टी के कुछ लोग उनकी निगरानी कर रहे हैं. उनका यह बयान दर्शाता है कि पार्टी में परस्पर विश्वास की कमी है. भाजपा ने आशंका जताई कि जब सपा प्रमुख की निगरानी हो रही है, तो विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक के नेताओं की भी हो रही होगी. पाठक ने कहा कि जब मुलायम को मालूम है कि उनकी निगरानी कौन कर रहा है, तो उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ■

राज करने वाले को चुभता है बब्बर का कांटा

समाजवादी पार्टी की अंदरूनी गतिविधियों पर गहरी नज़र और जानकारी रखने वाले वरिष्ठों का कहना है कि अमर सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा को सपा में शामिल करने पर हुए विचार में एक प्रस्ताव राज बब्बर को भी वापस लाने के बारे में था. तब राज बब्बर उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए चुने नहीं गए थे या कहें, तब तक कांग्रेस आलाकमान ने इस बारे में विचार नहीं किया था. लेकिन, जैसे ही कांग्रेस को यह भनक मिली कि राज बब्बर को सपा में लाने की सुगबुगाहटें चल रही हैं, उत्तराखंड से उनका राज्यसभा में जाना फाइनल हो गया. पर उधर बब्बर का नाम प्रस्तावित करने वाले नेता की तो वाट लग गई. फिरोजाबाद चुनाव में डिंपल यादव की राज बब्बर के हाथों हुई हार का कांटा इस कदर चुभा हुआ है कि वह नाम पार्टी में मिसाइल का असर दिखा रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

आईआरएनएसएस-1डी

आसमान पर बादशाहत की ओर भारत का एक क़दम

नया शहर हो या आप कहीं भटक गए हों, बस या ट्रेन का आप घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके आगमन-प्रस्थान की सही जानकारी नहीं मिल पा रही, आप टूर पर निकले हों या आकस्मिक विपदाओं के समय सहायता के लिए कार्यरत संस्थाओं को सूचना संबंधी ज़रूरत हो या फिर आपको बेहतर मोबाइल सेवाएं देने का मसला हो, आपकी हर समस्याओं का सटीक समाधान है जीपीएस यानी ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम. आईआरएनएसएस-1डी के सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत नेवीगेशनल सिस्टम के लिए अब तैयार है.

राजीव रंजन

देश का चौथा नेवीगेशन सेटेलाइट पीएसएलवी-सी27 का उपग्रह आईआरएनएसएस-1डी पिछले दिनों श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया. मिशन की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसरो के चेयरमैन एएस किरण कुमार ने इसरो टीम को बधाई दी. यह मिशन बहुत खास इसलिए है कि अब तक सिर्फ़ अमेरिका ही उपग्रह आधारित जीपीएस प्रणाली में अपने क़दम बढ़ा सका है. मिशन की कामयाबी से भारत की उपग्रह आधारित जीपीएस प्रणाली अमेरिका की जीपीएस प्रणाली के बराबर पहुंच जाएगी. यह प्रणाली दक्षिणी एशिया पर लक्षित है और इसे कुछ इस तरह तैयार किया गया है कि देश के भीतर और इसकी सीमा से 1,500 किलोमीटर तक की दूरी के क्षेत्र में प्रयोगकर्ताओं को बिल्कुल सही जानकारी उपलब्ध हो सकेगी. इस मिशन के सभी सात उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के बाद ही अगले साल जून-जुलाई में इसरो की योजना इसे सक्रिय करने की है. आईआरएनएसएस के सक्रिय होने के साथ ही नौवहन व्यवस्था के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता ख़त्म हो जाएगी. हालांकि, इसरो के अधिकारियों का कहना है कि इस साल दो और नौवहन उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाना है.

क्या है जीपीएस

यह अमेरिका के स्पेस पर आधारित एक रेडियो नेवीगेशन सिस्टम है. जीपीएस एक स्पेस आधारित सैटेलाइट नेवीगेशन सिस्टम है, जिसका प्रबंधन अमेरिका करता है. इसके ज़रिये हर मौसम में धरती पर कहीं से भी किसी भी जगह की जानकारी और समय की सूचना मिल सकती है.

मुख्य तथ्य

- भारत का चौथा नेवीगेशन सेटेलाइट पीएसएलवी-सी27 का आईआरएनएसएस-1डी
- श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया.
- आईआरएनएसएस-1 डी का भार 1,425 किलोग्राम है.
- इस सीरीज के सभी उपग्रहों का जीवनकाल 10 साल है.
- 1,500 किलोमीटर का क्षेत्र इसकी सीमा है.
- अमेरिका के जीपीएस और रूस के ग्लोनास के बाद भारत तीसरा देश बनेगा, जिसके पास अपना नेवीगेशन सिस्टम होगा.
- आईआरएनएसएस-1डी के शुरू होते ही हम इससे मिलने वाले डाटा का इस्तेमाल सेना की मदद के लिए कर सकते हैं.
- इंडियन रीजनल सैटेलाइट नेवीगेशन सिस्टम (आईआरएनएसएस) के लिए सात उपग्रहों में से आईआरएनएसएस-1डी को लेकर चार उपग्रह छोड़े जा चुके हैं.
- इस सिस्टम के ज़रिये पूरी दुनिया में सैन्य, नागरिक और व्यवसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए अहम जानकारियां उपलब्ध होती हैं. जीपीएस रिसीवर के ज़रिये इसे आसानी से एक्सेस किया जा सकता है.

इस सिस्टम के फायदे

यह सिस्टम आपको न केवल आपके वर्तमान स्थान के बारे में बताएगा, बल्कि आप जिस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, उसका सही रास्ता भी बताएगा. यह सिस्टम आम लोगों को टाइमिंग सर्विस (सही वक्त बताने की सेवाएं) भी प्रदान करता है. जीपीएस अपने बहुत सारे उपयोगकर्ताओं को सही समय और सही स्थान बताने की सेवाएं प्रदान करता है. बसों एवं ट्रेनों के आने के सही समय की जानकारी, आपातकालीन सहायता, बैंक, मोबाइल और विद्युत ग्रिड आदि सभी सेवाएं जीपीएस पर ही निर्भर रहती हैं. जीपीएस के माध्यम से चलने वाली सबसे लोकप्रिय सेवा वेहिकल ट्रैकिंग बहुत सफल रही है. पर्वतारोहियों को दिशा संबंधी सूचनाएं भी इससे मिलती हैं. एक खास तकनीक से तैयार किए गए गुब्बारे जीपीएस की मदद से ओज़ोन की परत में होने वाले नुक़सान की जानकारी समय-समय पर प्रदान करते रहते हैं. सच कहा जाए, तो इस तकनीक का भविष्य शायद हमारी सोच से भी ऊपर है.

आईआरएनएसएस से दो सेवाएं मिल सकेंगी, जिसमें से स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस के जरिये इसका आम लोग उपयोग कर सकेंगे और दूसरी प्रतिबंधित सेवा होगी, जो सेना के उपयोग के लिए होगी. आईआरएनएसएस-1 डी का प्रक्षेपण इसलिए भी जरूरी था कि बिना इसके प्रक्षेपण के हम नेविगेशनल प्रक्रिया शुरू ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कक्षा में चार उपग्रह की न्यूनतम जरूरत थी, जो इस उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ ही पूरी हो गई.

क्यों है ज़रूरी

हमें अपने नेवीगेशन सिस्टम की ज़रूरत थी, क्योंकि विदेशी सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले नेवीगेशन सिस्टम का उपयोग प्रतिबंधित हो सकता है और विपरीत परिस्थितियों में यह बाधित भी हो सकता है. आईआरएनएसएस से दो सेवाएं मिल सकेंगी, जिनमें से स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस के ज़रिये इसका आम लोग उपयोग कर सकेंगे और दूसरी प्रतिबंधित सेवा होगी, जो सेना के उपयोग के लिए होगी. आईआरएनएसएस-1डी का प्रक्षेपण इसलिए भी ज़रूरी था, क्योंकि बिना इसके हम नेवीगेशनल प्रक्रिया शुरू ही नहीं कर सकते थे. इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कक्षा में चार उपग्रहों की न्यूनतम ज़रूरत थी, जो इस उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ ही पूरी हो गई. अब जो चार उपग्रह बच गए हैं, उनके प्रक्षेपण से नेवीगेशन सिस्टम कुशल और पूरी तरह से कारगर हो जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

इलाहाबाद

क़ानून के पैरोकारों ने एक-दूसरे के ख़िलाफ़ कसी कमर

शिवा शंकर पांडेय

ज़िला कचहरी में एक वकील व एक दारोगा की नासमझी ने पुलिस महकमे और वकील बिरादरी को प्रतिष्ठा की लड़ाई में इस कदर उलझा दिया है कि राज्य के कई ज़िले इसकी चपेट में आ गए. आंदोलन और धरना-प्रदर्शन की आंच हाईकोर्ट के वकीलों तक जा पहुंची. क़ानून के पैरोकार कहे जाने वाले पुलिस विभाग और वकील बिरादरी एक-दूसरे के ख़िलाफ़ आमने-सामने आकर आंदोलन को धार देने में जुट गए हैं. एक पखवाड़े से ज़्यादा समय बीत चुका है. इलाहाबाद और प्रदेश के ज़्यादातर कचहरी स्थल धरना-प्रदर्शन, महापंचायत, विरोध सभाओं के अखाड़े बन गए हैं. हर जगह न्यायिक कार्य पूरी तरह ठप है. रोज़ाना हज़ारों वादकारी कचहरी से बैरंग वापस लौटने के लिए मजबूर हो रहे हैं. आंदोलन थमने के आसार फिलहाल नहीं दिख रहे हैं. उत्तर प्रदेश के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है, जब राज्य पुलिस और वकीलों के बीच टकराव विद्रोह के स्तर तक आ पहुंचा है. बीते 11 मार्च को इलाहाबाद ज़िला कचहरी में रोज़ाना की तरह न्यायिक कार्य चल रहा था. दोपहर क़रीब साढ़े बारह बजे पेशी में आए दारोगा शैलेंद्र सिंह और वकील नबी अहमद के बीच पहले कहा-सुनी, फिर मारपीट होने लगी. आसपास मौजूद पुलिसकर्मी और वकील वहां आ गए. दारोगा ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से गोली चला दी. गोली लगने से वकील नबी अहमद ने मौक़े पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अजय नागर नामक सिपाही घायल हो गया. घटना से गुस्साए वकीलों का समूह सड़क पर उतर आया. प्रदर्शन, पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ के साथ बवाल बढ़ने लगा. अधिकारी भी पुलिस फोर्स के साथ सड़क पर आ गए. लगातार बिगड़ते हालात देखकर जजों ने कचहरी परिसर में ही आपात बैठक बुला ली.

आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने भीतर घुसकर कई जजों की पिटाई कर दी. मुश्किल से तीन घंटे भी नहीं बीते होंगे कि हालात बेकाबू होने लगे. स्मार्ट सिटी बनने जा रहे इलाहाबाद शहर में पुलिसिंग धड़ाम नज़र आई, तो क़ानून व्यवस्था औंधे मुंह पड़ी रही. बवाल ने तक़रीबन आधे शहर को अपनी चपेट में ले लिया. वकील और पुलिस दोनों आक्रामक हो गए. पुलिस ने कई बार लाठीचार्ज के साथ फायरिंग की. राह चलते बेकसूर लोग भी पिटाई के शिकार हुए. कई दर्जन वाहन आग के हवाले कर दिए गए. आईजी बृजभूषण शर्मा, डीएम भवनाथ और एसएसपी दीपक कुमार फोर्स के साथ मौक़े पर पहुंचे तो, लेकिन हालात पर नियंत्रण पाने में वे काफी देर बाद कामयाब हो सके. तब तक शहर के कई हिस्से पुलिस छावनी में बदल चुके थे. प्रशासन को जगह-जगह आरएएफ और पीएसी तैनात करनी पड़ी. 16 मार्च को वकीलों ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, वहीं दूसरी तरफ़ पुलिसकर्मियों ने भी बांह पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जाहिर किया. 20 मार्च को वकीलों के विभिन्न संगठनों ने महापंचायत करके आंदोलन तेज करने का ऐलान किया. दूसरे ही दिन यानी 21 मार्च को पुलिसकर्मियों ने पूरे प्रदेश भर में विरोध दिवस मनाया. किसी भी पुलिस मेस में भोजन नहीं बना. पुलिसकर्मियों ने भूखे रहकर असंतोष जाहिर किया. इस बीच लखनऊ से आए आईजी (सिविल डिफेंस) अमिताभ ठाकुर ने घटना में घायल सिपाही अजय नागर से अस्पताल जाकर मुलाकात की. उन्होंने सिपाही को एक दिन का वेतन देने की घोषणा कर दी. इसके बाद अमिताभ ठाकुर ने वकील की हत्या के आरोपी दारोगा शैलेंद्र सिंह के आवास राजरूपपुर पहुंच कर उसके परिवारीजनों से मुलाकात कर उन्हें हिम्मत से काम लेने को कहा. मीडिया से बातचीत के दौरान अमिताभ ठाकुर ने कचहरी कांड को एक हादसे की संज्ञा दी. उन्होंने कहा कि दारोगा शैलेंद्र सिंह की हरसंभव मदद सरकार को करनी चाहिए.

पुलिसकर्मियों को अनुशासन विभाग का सरकारी कर्मचारी माना जाता है. पुलिस फोर्स द्वारा इस कदर खुलकर विरोध करने से अधिकारियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं. वकीलों ने अपने आंदोलन को धार देने के लिए संघर्ष समिति का गठन किया और रणनीति बनाई. समिति की बैठक में प्रदेश के 40 ज़िलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. 23 मार्च को सभी ज़िलों के संघों ने अपने ज़िला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन आला अधिकारियों को सौंपा. इलाहाबाद में वकीलों ने कमिश्नर को ज्ञापन दिया. संघर्ष समिति में प्रदेश के सभी अधिवक्ता संघ के अध्यक्षों और इलाहाबाद के सभी संघों के अध्यक्षों समेत पूर्व पदाधिकारियों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है. आंदोलन की कमान बार काउंसिल के सदस्य एवं पूर्व उपाध्यक्ष आईके चतुर्वेदी को सौंपी गई है. शीतला मिश्र कार्यवाहक अध्यक्ष और देवेंद्र नगरहा सचिव बनाए गए. उधर, वकील हत्याकांड और पुलिस हमले की जांच की ज़िम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी गई है. लेकिन वकीलों और पुलिस के बीच लगातार बढ़ता टकराव तथा पुलिस फोर्स द्वारा इस कदर विद्रोह पर उतर आना निश्चित रूप से शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है. दो व्यक्तियों के आपसी विवाद के पुलिस विभाग बनाम वकील बिरादरी में बदल जाने से हर खास-ओ-आम चिंतित दिखाई दे रहा है.

एसएसपी का तबादला

एक राजनीतिक परिवार के क़रीबी होने का फ़ायदा उठाकर इलाहाबाद में पिछले काफी समय से जमे एसएसपी दीपक कुमार को वकीलों के लाख विरोध के बावजूद नहीं हटाया गया, लेकिन यूपीपीएससी-2015 की प्री-परीक्षा के पेपर रद्द करने की मांग को लेकर हुए उपद्रव, आगजनी और उसके बाद हुई पुलिस फायरिंग की घटना उन्हें महंगी पड़ गई. दीपक कुमार को बीते एक अप्रैल को डीजीपी मुख्यालय लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया और उनके स्थान पर जौनपुर के एसपी वीरेंद्र प्रताप श्रीवास्तव को एसएसपी बनाकर भेजा गया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

देश में पहली बार वाम दलों के संगठन एक साथ आए हैं. पहले वाम दलों के संगठन समर्थक की भूमिका में होते थे, लेकिन इस बार वे आंदोलन के आयोजक हैं. डॉ सुनीलम ने कहा कि इतने कम समय में किसी राष्ट्रीय नेता के खिलाफ वातावरण बना है. जमीनी मुद्दा पहली बार राजनीतिक मुद्दा बना है. यह लड़ाई किसानों के अस्तित्व की लड़ाई है. अभी तक ये लड़ाई भूमि अधिग्रहण के खिलाफ थी, लेकिन अब यह भू–अधिकार की लड़ाई बन गई है. मेधा पाटकर ने कहा कि सरकार को अच्छी तरह मालूम है कि उसका संसद से सड़क तक विरोध हो रहा है.

हसदेव अरण्य

कोल ब्लॉक आवंटन के खिलाफ खड़े हुए ग्रामीण

शशि शेखर

हसदेव अरण्य क्षेत्र में समृद्ध वन संपदा एवं ग्रामसभाओं के प्रस्ताव को नजरंदाज कर के किए गए कोयला खदानों के आवंटन के विरोध में ग्रामीण फिर से खड़े हो गए हैं. उनकी मांग है कि ये आवंटन रद्द किए जाएं. केन्द्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा पांचवी अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभाओं के प्रस्तावों को नजरंदाज करते हुए कोयला खदानों के आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. 24 मार्च, 2015 को कोयला मंत्रालय के द्वारा हसदेव अरण्य कोल फील्ड में परसा, पतुरियाडांड एवं गिधमुडी कोयला खदानों का आवंटन किया गया है, जबकि परसा कोयला खदान से प्रभावित गांव फतेहपुर, हरिहरपुर, साल्ही, घातबर्रा की ग्रामसभाओं ने पूर्व में ही विशेष ग्रामसभा आयोजित करके खदानों के आवंटन या नीलामी का विरोध किया था. इसी प्रकार पतुरियाडांड एवं गिधमुडी गांव की ग्रामसभाओं ने भी विशेष ग्रामसभा आयोजित करके खदानों के आवंटन को रोकने का प्रस्ताव पारित कर कोयला मंत्रालय को भेजा है.

छत्तीसगढ़ के कोरबा, सरगुजा एवं रायगढ़ जिलों में स्थित सम्पूर्ण हसदेव अरण्य सघन वन एवं आदिवासी बाहुल्य इलाका है, जो संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत आता है. यहां पर रहने वाले आदिवासियों की आजीविका, संस्कृति और जीवन–शैली पूर्ण रूप से जंगल और खेती पर ही निर्भर है, जिसका वो पीढ़ियों से संरक्षण एवं संवर्धन करते आए हैं. यह सम्पूर्ण जंगल बहुत ही समृद्ध तथा जैव विविधता से परिपूर्ण है और यह कई महतवपूर्ण वन्य–जीवों का आवास स्थल भी है. इसलिए यह वन सम्पदा न सिर्फ स्थानीय, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. यही वजह है कि 2009 में इस सम्पूर्ण

कोल फील्ड को खनन के लिए नो गो क्षेत्र घोषित किया गया था. मौजूदा केन्द्रीय सरकार द्वारा नो गो क्षेत्र के प्रावधान को ख़त्म करते हुए कोयला खदानों का आवंटन किया जा रहा है.

हसदेव अरण्य में संचालित परसा ईस्ट एवं केते बासन कोयला खदान की वन अनुमति को ग्रीन ट्रिब्युनल ने 24 मार्च, 2014 को निरस्त कर दिया था. हालांकि, यह मामला उच्चतम न्यायलय में लंबित है और न्यायालय का फैसला आने के पूर्व खदान का आवंटन केंद्र सरकार की हड़बड़ी एवं प्रो कार्पोरेट मंशा को स्पष्ट करता है. इस संबंध में छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन ने केंद्र सरकार से मांग किया है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में आवंटित कोयला खदानों को तुरंत निरस्त किया जाए और पूरे हसदेव अरण्य को खनन से मुक्त रखा जाए. इसके साथ ही केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोयला खदानों के इनवायलेट और नॉट इनवायलेट के निर्धारण के लिए करवाए गए अध्ययन रिपोर्ट को भी सार्वजनिक कर यह बताना चाहिए की किन मापदंडों के आधार पर हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन की अनुमति प्रदान की जा रही है. छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन हसदेव अरण्य क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर आने वाले दिनों में खदानों के आवंटन के विरोध में व्यापक आन्दोलन करने की भी तैयारी कर रहा है.

दरअसल, छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र के करीब 20 ग्राम सभाओं ने एक प्रस्ताव पारित कर यह साफ़ कर दिया था कि वे अपने क्षेत्र में होने वाले कोल ब्लॉक आवंटन और कोयला खनन का विरोध करेंगे. गौरतलब है कि पिछली बार जब कोयला के ब्लॉक का आवंटन हुआ था, तब 218 कोल ब्लॉक में 30 फीसदी सिर्फ छत्तीसगढ़ में आवंटित हुए थे. छत्तीसगढ़ के सरगुजा और कोरबा में फैले हसदेव अरण्य में करीब 30 कोल ब्लॉक है. इसमें से 16 कोल ब्लॉक पहले जिन कम्पनियों को आवंटित हुए थे, उन्हें आज तक पर्यावरण मंजूरी नहीं मिली और इस वजह से वहां खनन नहीं शुरू हो सका था. अलबत्ता, तीन कोल ब्लॉक ऐसे थे, जहां अदानी की कंपनी ज्वायंट वेंचर के तहत खनन का काम कर रही थी. इन तीन कोल ब्लॉक्स को पर्यावरणीय मंजूरी भी मिल गई थी. हालांकि, बाद में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस मंजूरी को रद्द कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहां भी खनन कार्य रूका हुआ है.

इस इलाके के बीस ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभा की बैठक कर एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें गांव वालों ने स्पष्ट रूप से

प्रस्ताव पारित करने वाले ग्राम सभाओं के नाम

हसदेव अरण्य क्षेत्र की मोरगा, मदनपुर, खिलती, धजाक, उचलेंगा, घाटवल्ला, साली, हरिहरपुर, फतेहपुर, सेंदू, सुष्कम, पटोगिया, पुटा, पतुरिया डांड, अरसिया और करहियापारा ग्रामसभा. मांड रायगढ़ की चार ग्राम सभा नरकारोह, करौंधा, दुलियामोड़ और चैनपुर.

इस क्षेत्र में खनन कार्य का विरोध किया था. यहां के निवासियों का कहना है कि चूंकि हमारे क्षेत्र में पेसा एक्ट (पंचायत एक्सटेंशन टू शिड्यूल एरिया एक्ट, जो आदिवासी इलाकों को विशेषाधिकार देता है) लागू है, इसलिए किसी भी कोल ब्लॉक के लिए जमीन अधिग्रहण करने से पहले सरकार के लिए यहां की ग्राम सभाओं की अनुमति लेना आवश्यक है. हसदेव अरण्य क्षेत्र में भी पेसा कानून लागू है. ग्राम सभा के इस प्रस्ताव के मुताबिक़ कोल ब्लॉक के आवंटन से पर्यावरण प्रभावित होगा, आदिवासी विस्थापित होंगे. यह प्रस्ताव कहता है कि किसी भी खनन परियोजना के आवंटन या नीलामी से पहले ग्राम सभा से पूर्व सहमति प्राप्त करनी जरूरी है. यहां के लोगों का मानना है कि जैव विविधता से समृद्ध इस वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की खनन नहीं होनी चाहिए. हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री, कोयला मंत्री और आदिवासी मामलों के मंत्री को पत्र भी लिखा है. यहां के लोगों की मुख्य चिंता यह है कि अब कोल ब्लॉक के आवंटन और इसके लिए जरूरी जमीन अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी, नये अध्यादेश (कोल माइनिंग/भूमि अधिग्रहण क़ानून में नये अध्यादेश के जरिये किए गए संशोधन) के आने के बाद से नगण्य हो गई है. ■

feedback@chauthiduniya.com

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ

राजनीतिक-सामाजिक संगठन एक साथ

नवीन चौहान

दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में 2 अप्रैल, 2015 को देश के अधिकांश किसान और जन संगठन एकत्रित हुए और मोदी सरकार द्वारा लाए गए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का नये सिरे से विरोध करने के लिए नई नीति तैयार की. इस बैठक के दौरान कांग्रेस, वाम दल, जनता दल(युनाइटेड) और अन्य राजनीतिक दलों के नुमांइदों ने भी शिरकत की. सभी ने संसद से सड़क तक अध्यादेश का एकजुट होकर लड़ाई लड़ने और जीतने तक संघर्ष करने का ऐलान किया. आगे की लड़ाई भूमि अधिकार संघर्ष आंदोलन नाम से एकीकृत तौर पर लड़ी जाएगी. इसके लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कमेटियों का गठन भी किया गया है. चूंकि केंद्र सरकार 3 अप्रैल को दोबारा अध्यादेश ले आई है इसलिए 6 अप्रैल को पूरे देश में नए अध्यादेश की कॉपी जला कर सांकेतिक तौर पर विरोध प्रदर्शन किया गया.

इस विचार–विमर्श में कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय पंचायती राज मंत्री जयराम रमेश, सीपीआई(एम) के सीताराम येचुरी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के डी राजा, जनता दल(युनाइटेड) के केसी त्यागी, ऑल इंडिया फॉर्वर्ड ब्लॉक के देबब्रत बिस्वास, रिवॉल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी के अबानी रॉय, जनता दल(सेकुलर) के दानिश अली, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (एमएल) लिबरेशन की कविता कृष्णन शामिल थीं, सभी ने एक सिरे से इस आंदोलन का समर्थन करने का ऐलान किया. इसके साथ ही राज्यसभा में अध्यादेश का पुरजोर विरोध करने की घोषणा की. इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस आंदोलन में जन संगठन, किसान संगठन, दलित, महिला और खेतीहर मजदूरों के संगठन शामिल हैं.

देश में पहली बार वाम दलों के संगठन एक साथ आए हैं. पहले वाम दलों के संगठन समर्थक की भूमिका में होते थे, लेकिन इस बार वे आंदोलन के आयोजक हैं. डॉ सुनीलम ने कहा कि इतने कम समय में किसी राष्ट्रीय नेता के खिलाफ वातावरण बना है. जमीनी मुद्दा पहली बार राजनीतिक मुद्दा बना है. यह लड़ाई किसानों के अस्तित्व की लड़ाई है. अभी तक ये लड़ाई भूमि अधिग्रहण के खिलाफ थी, लेकिन अब यह भू–अधिकार की लड़ाई बन गई है. मेधा पाटकर ने कहा कि सरकार को अच्छी तरह मालूम है कि उसका संसद से सड़क तक विरोध हो रहा है. सरकार ऐसा इसलिए कर रही है, क्योंकि समस्याओं और चुनावों के बीच का संबंध टूट गया है. प्रदेशों से आए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि राज्यों में काम कर रहे सभी किसान संगठनों को साथ लेकर चलना होगा. ऐसा करने से ही आंदोलन मजबूत होगा.

गौरतलब है कि 1947 से 2004 तक भूमि अधिग्रहण से 6

फोटो–*सुनील मल्होत्रा*

करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं. सरकार प्रतिदिन 2.5 हेक्टेयर जमीन किसानों से छीन रही है. अधिग्रहीत की गई कुल भूमि में से 40 प्रतिशत आदिवासियों की और 20 प्रतिशत दलितों की है. अब तक देश के कुल 50 प्रतिशत लोग भूमिहीन हो चुके हैं. जनता दल (सेकुलर) के दानिश अली ने आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि रायसीना पर बैठकर लोग असली भारत को भूल जाते हैं, जो गांव और देहात में बसता है. उन्होंने बेंगलुरु–मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर का उदाहरण देते हुए कहा कि 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी. इसके लिए एक अमेरिकी कंपनी के साथ एमओयू भी साइन किया गया था. शुरुआत में इसके जरिये विदेशी निवेश आने और लोगों को रोजगार मिलने जैसी बातें हुईं थीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, केवल किसानों की जमीन छीनकर उन्हें बेघर कर दिया गया. राष्ट्रीय सोशलिस्ट पार्टी के अवनि राय ने कहा कि ये लड़ाई किसानों की इज्जत की लड़ाई है. इसके लिए सबको एकजुट होना होगा. एनडीए गठबंधन एनएमडीए (नरेंद्र मोदी एलायंस) हो गया है, जहां लोकतंत्र नहीं बचा है. सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात में विरोध करने वालों पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं. सरकार हाइवे और रेल मार्गों के किनारे एक किलोमीटर तक की जमीन अधिग्रहीत करना चाहती है. अगर ऐसा होगा, तो कुल जमीन का 31.9 प्रतिशत, यानी तकरीबन एक तिहाई जमीन अधिग्रहीत हो जाएगी. जनता दल (युनाइटेड) के के सी त्यागी ने कहा कि देश का किसान रक्षा, सरकारी अस्पताल, नहर, बिजली के प्रोजेक्ट के लिए कभी भी जमीन देने से मना नहीं करता है. हाल ही में राजस्थान के सूरतगढ़ में रक्षा प्रोजेक्ट के लिए 12000 एकड़ जमीन की आवश्यक्ता थी. वहां के किसानों ने सरकार ने जो कीमत तय की, उसी पैसे में सरकार को जमीन दे दी. ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि देश का किसान विकास विरोधी है.

कुल मिलाकर बैठक सफल रही, लेकिन बैठक में कई तरह के विरोधाभास देखने को मिले. भू–अधिकार की मांग और वर्तमान में हुई ओलावृष्टि से किसानों को मुआवजा दिए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया. बैठक का अधिकांश समय इसी विषय पर केंद्रित रहा. भू–अधिकार की मांग करने वाली एकता परिषद का कोई सदस्य बैठक में नज़र नहीं आया. न ही अन्ना हजारे को आंदोलन का चेहरा बनाये रखने की कोई बात हुई. देखना है, यह लड़ाई कितनी दूर तक जाती है और राजनीतिक दलों का सहयोग इस आंदोलन को कितना मिलता है? कांग्रेस भी 19 अप्रैल को अध्यादेश के विरोध में दिल्ली में रैली करने का ऐलान कर चुकी है. ऐसे में इस आंदोलन से ज्यादा कांग्रेस अपनी रैली को सफल बनाने में जुटेगी, जिसमें राहुल गांधी के शामिल होने की बातें हो रही हैं.

अधिग्रहण के मूल सिद्धांतों को बदला गया है : जयराम रमेश

जनसंगठनों के साथ भूमि-अधिग्रहण के मामले में विरोध के लिए विचार-विमर्श करने कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश पहुंचे. उन्होंने बताया कि आखिर क्यों कांग्रेस मोदी सरकार के संशोधनों को समर्थन नहीं दे सकती.

1.सोशल इंपैक्ट असेस्मेंट को कानून से बिल्कुल खत्म कर दिया गया है.

2.पांच साल उपयोग न हो, तो जमीन की वापसी. सरकारें सार्वजनिक उपक्रम के नाम पर भूमि अधिग्रहण करके निजी संस्थानों को दे देती हैं.

3.किसानों की अनुमति के बिना अधिग्रहण नहीं होना चाहिए.

4.इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के किनारे की जमीन नहीं ली जाए. अधिग्रहण कॉरीडोर तक ही सीमित होगा, लेकिन मोदी सरकार ने इसे बदल दिया है.

5.चार गुना मुआवजा मिलने का प्रावधान था, लेकिन वर्तमान सरकार ने धारा 24 को बदल दिया है.

कैसे होगा विरोध

सरकार के इस निर्णय के विरोध में 5 मई, 2015 को भूमि अधिकार संघर्ष रैली का आयोजन किया जाएगा. इसके पहले राज्यों में राज्यस्तरीय सभाओं का आयोजन किया जाएगा. किसानों को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए जन जागरण अभियान जिले से लेकर ग्रामीण स्तर तक चलाया जाएगा. इसके अंतर्गत पदयात्रा, रास्ता रोको, रेल रोको और मानव श्रृंखला बनाने जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके साथ ही अध्यादेश के विरोध में देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा. इसके अंतर्गत पांच करोड़ लोगों का हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके साथ ही जमीन वापसी अभियान चलाने का निर्णय भी लिया गया है. राज्य स्तर पर 9 अप्रैल को विजयवाड़ा, 10 अप्रैल को भुवनेश्वर और 11 अप्रैल को पटना में सभाएं आयोजित करने का फैसला किया गया. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

देश के हर हिस्से का विकास होना चाहिए. प्रधानमंत्री खुद पूर्वोत्तर के विकास की बात कर रहे हैं. कश्मीर की तरह पूर्वोत्तर भी वंचित क्षेत्र रहा है. पूर्वोत्तर में क्या होता है, इससे दिल्ली या मुंबई के लोगों का कोई सरोकार नहीं होता. ऐसा मुझे लगता है. पूर्वोत्तर से कोई ख़बर तभी आती है, जब वहां किसी लाचार लड़की से दुर्व्यवहार हो जाता है. उसके बाद पूर्वोत्तर पर कुछ बड़े लेख छप जाते हैं. लेकिन, वास्तव में पूर्वोत्तर में क्या हो रहा है, क्या वहां के लोगों को मुख्य धारा में शामिल होने का मौक़ा मिल रहा है? ये सारी बातें सार्वजनिक बहस से अलग हो गई हैं. ऐसा क्यों है?

मानवीय मूल्यों का त्याग ठीक नहीं

पिछले साल कश्मीर में भयानक बाढ़ आई थी. श्रीनगर ने इस तरह की त्रासदी पहले कभी नहीं देखी थी. उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे. उन्होंने अपने स्तर पर ठीक काम किया. लोगों की जान बचाने की दिशा में सेना ने बेहतरीन काम किया. एक बार फिर कश्मीर में बाढ़ आई. समाचार-पत्रों की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार त्रासदी टल गई. अब यह कोई मुद्दा नहीं है. बाढ़, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदा देश में कहीं भी आ सकती है और उससे निपटने के लिए देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है. यह सब ठीक है, लेकिन राष्ट्र की संवेदनशीलता का क्या? पहले जब बिहार में भूकंप आता था या बाढ़ आती थी, तो उसके साथ सारा देश खड़ा हो जाता था. सारे देश से पैसा इकट्ठा किया जाता था. ऐसा नहीं है कि पैसा महत्वपूर्ण था, पैसे से ज़्यादा लोगों की भावनाएं महत्वपूर्ण थीं, जो दिखाती हैं कि हम आपके साथ हैं.

अभी देश में जो एक चिंताजनक प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, वह है विकास के लिए, बुनियादी सुविधाओं के लिए, बुलेट ट्रेन के लिए, एअरपोर्ट और सड़क निर्माण के लिए अंधी दौड़ या कहें अंध प्रचार. दरअसल, ये सभी आवश्यक हैं, लेकिन हम अपने इस अंध प्रचार में एक राष्ट्र के रूप में अपनी संवेदनशीलता कहीं न कहीं खो रहे हैं. इसे स्पष्ट करने के लिए दो उदाहरण पर्याप्त हैं. पहला, 80 के दशक में हुए हाशिमपुरा नरसंहार पर आए अदलती फ़ैसले में सभी आरोपी पुलिसकर्मियों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. ठीक है! अदालत एक तकनीकी दृष्टिकोण अपना सकती है, यह एक क़ानूनी प्रक्रिया है, लेकिन हक़ीक़त फिर भी यह है कि लोगों की निर्मम हत्या की गई थी. उत्तर प्रदेश की पीएसी (प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी) इसके लिए ज़िम्मेदार थी. बाकी पुलिस बल को इसकी जानकारी थी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस मामले को मीडिया के साथ मिलकर उजागर किया था. लेकिन यह कितने शर्म का विषय है कि इतने लंबे विलंब के बाद भी ज़िंदा बच गए पीड़ितों को राहत नहीं मिली. कुछ तो अपनी प्राकृतिक मौत मर चुके हैं. लेकिन, जो ज़िंदा हैं, उन्हें यह घटना अंजाम देने वालों को सिर उठाकर शान से जाते हुए देखना पड़ रहा है.

दूसरी बात यह है कि पूरे देश में इस घटना को लेकर कोई हो-हल्ला नहीं हुआ, कोई पोस्टर नहीं दिखा, कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई गई और कोई हाशिमपुरा नहीं गया. 20-30 साल पहले राजनेताओं में (दबाववश) और आम जनता में जो संवेदनशीलता दिखाई देती थी, वह अब नहीं दिखती. यह सब कहीं खो गया लगता है. मुंबई में बैठकर हमें अख़बारों से पता चलता है कि कहां फ्लाईओवर बनाया रहा है, पुल बन रहा है, विकास के किस काम में बदलाव हुआ है, लेकिन हमारे पास यह महसूस करने के लिए समय नहीं है कि हमारे साथी नागरिकों का क्या हाल है या उनके साथ क्या कुछ घटित हो रहा है. पहले पुलिस ने हाशिमपुरा के लोगों के साथ बुरा किया और क़ानूनी प्रक्रिया के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा.

अब कश्मीर पर एक नज़र. पिछले साल कश्मीर में भयानक बाढ़ आई थी. श्रीनगर ने इस तरह की त्रासदी पहले कभी नहीं देखी थी. उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे. उन्होंने अपने स्तर पर ठीक काम किया. लोगों की जान बचाने की दिशा में सेना ने बेहतरीन काम किया. एक बार फिर कश्मीर में बाढ़ आई. समाचार-पत्रों की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार त्रासदी टल गई. अब यह कोई मुद्दा नहीं है. बाढ़, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदा देश में कहीं भी आ सकती है और उससे निपटने के लिए देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है. यह सब ठीक है, लेकिन राष्ट्र की संवेदनशीलता का क्या? पहले जब बिहार में भूकंप आता था या बाढ़ आती थी, तो उसके साथ सारा देश खड़ा हो जाता था. सारे देश से पैसा इकट्ठा किया जाता था. ऐसा नहीं है कि पैसा महत्वपूर्ण था, पैसे से ज़्यादा लोगों की भावनाएं महत्वपूर्ण थीं, जो दिखाती हैं कि हम आपके साथ हैं. मुंबई से इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया अपने पाठकों से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते थे और मदद के लिए भेजते थे. लेकिन, कश्मीर के मामले में ऐसा नहीं दिखा. क्या कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या हम कश्मीर पर पाकिस्तान के उस मत को और मजबूत नहीं बना देते कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? भारतीयों ने वहां के लोगों के प्रति अपनी संवेदनशीलता खो दी है और वे यह मानकर चल रहे हैं कि उन पर पैसा खर्च करना व्यर्थ है. एक राष्ट्र के तौर पर हम क्या हो गए हैं? हमारी आत्मा संवेदनहीन हो गई है. एक देश के लिए इससे अधिक दु:खद और क्या हो सकता है?

इस सबके साथ कोई देश कितना आगे बढ़ सकता है? हम चीन नहीं बन सकते, क्योंकि चीन में लोकतंत्र नहीं है. चीन में नेता प्रोजेक्ट बनाते हैं, वही यह फ़ैसला करते हैं कि किस नदी को जोड़ना है, कहां बांध बनाना है, कहां पुल बनाना है. ये ऐसी चीजें हैं, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते. यह उनके विकास का तरीका है, हमारा तरीका अलग है. देश के हर हिस्से का विकास होना चाहिए. प्रधानमंत्री खुद पूर्वोत्तर के विकास की बात कर रहे हैं. कश्मीर की तरह पूर्वोत्तर भी वंचित क्षेत्र रहा है. पूर्वोत्तर में क्या होता है, इससे दिल्ली या मुंबई के लोगों का कोई सरोकार नहीं होता. ऐसा मुझे लगता है. पूर्वोत्तर से कोई ख़बर तभी आती है, जब वहां किसी लाचार लड़की से दुर्व्यवहार हो जाता है. उसके बाद पूर्वोत्तर पर कुछ बड़े लेख छप जाते हैं. लेकिन, वास्तव में पूर्वोत्तर में क्या हो रहा है, क्या वहां के लोगों को मुख्य धारा में शामिल होने का मौक़ा मिल रहा है? ये सारी बातें सार्वजनिक बहस से अलग हो गई हैं. ऐसा क्यों है?

मुझे लगता है कि सत्ता हो या मीडिया, उनमें संवेदनशीलता ख़त्म हो चुकी है. उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं. वे अंधी दौड़ में शामिल होकर चमकते मल्टीप्लेसेज, फ्लाईओवर और सड़कें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. वे उस चमक में मानो खो गए हैं. हर कोई यहां दिखाने में लगा हुआ है कि देखो, हमने कितनी जल्दी यह पुल बना लिया, कितनी दूरी कम कर दी है. नितिन गडकरी ने देश में ऐसे टोल नाके की खोज की, जहां बहुत ही कम ट्रैफिक है, वहां एक टोल गेट है. लेकिन, जहां पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वहां पर टोल गेट ट्रैफिक को रोके रखता है. प्रगति की बात सही है, लेकिन कहीं पर हमें एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है. भौतिक विकास के लिए मानवीय मूल्यों का त्याग नहीं किया जा सकता. अन्यथा, विकास के नाम पर हम ग़रीबों के साथ नाइंसाफी करते रहेंगे. ग़रीबों को इन सारे विकास का लाभ बमुश्किल मिल पाता है. उन्हें पहले रोटी-कपड़ा-मकान चाहिए. लेकिन, हम इसकी जगह कुछ और ही बातें कर रहे हैं. हमारी असंवेदनशीलता ग़रीबों के लिए घातक है. जितनी जल्दी हम यह सब समझ सकें, उतना ही बेहतर होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

विक्रम मल्लाह और फूलन देवी-6

कौन और कैसे बनाता है डकैत

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

यह बताना नया नहीं होगा कि चंबल क्षेत्र में डाकुओं के बनने, बढ़ने और बने रहने के कारण ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक हैं. प्रशासन का अभाव और सड़कों की कमी इस क्षेत्र को मुक्तांचल बनाए रखने में सहायक है. लेकिन, यह जानकारी बहुतों के लिए नई होगी कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के इस मिले-जुले अंचल में डकैती अब बहुत-से ऐसे लोगों के लिए एक समांतर व्यवसाय हो गई है, जो खुद कभी हथियार नहीं उठाते. इस क्षेत्र में कई बड़े किसानों एवं बनियों का एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है, जो पहले तो किसी युवक को डकैत बनाने में सहयोग देता है, डकैत बनने के बाद उसका माल अपने पास रखता है तथा इस क्रम में डकैत का विश्वासपात्र बन जाता है. वह इस तरह की सूचनाएं भी डकैतों के पास पहुंचाता है कि पुलिस क्या करने जा रही है. लेकिन, माल जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो यही वर्ग पुलिस का मुखबिर बन जाता है. कुछ दिनों तक यह दोहरी मुखबिरी करता है. बाद में यह अवांछित डकैत को मरवा देता है तथा उसका माल हजम कर जाता है. डकैती के व्यवसाय का दूसरा चेहरा यह है. गांवों में डकैतों के पॉकेट्स हैं. प्राय: गांव के पैसे वाले या गांव की एक पार्टी उन्हें शरण देती है. इसके बाद काम का बंटवारा होता है. डकैतों को जेल से छुड़वाया जाता है. जो बाहर आ जाता है, उसके माध्यम से जंगल में रहने वाले डकैतों से रिश्ता जोड़ा जाता है तथा बाद में जेल से बाहर आए डकैत पर दबाव डालकर गिरोह से पैसा खाया जाता है.

जालौन जैसे शहरों में सर्राफ तथा आढ़ती डकैतों के अड्डे हैं. आढ़ती पैसा लगाता है डकैतों की व्यवस्था संभालने में तथा वही डकैतों का माल सर्राफ के यहां गलवाता भी है. नझाई बाज़ार के आढ़ती, मंदिर के आसपास की दुकानें तथा बाज़ार बैठगंज के सर्राफ मुख्य अड्डे हैं. उनके अलावा इस क्षेत्र के गांवों में फैले सुनारों के घर भी डाकुओं के अड्डे हैं. रायपुर गांव के एक सुनार ने औरैय्या में सर्राफे की दुकान खोली है. कहा जाता है कि यह विक्रम गिरोह का खास आदमी है. डकैत विश्वास और घोर अविश्वास के बीच झूलता है तथा बाद में बड़बोला और अहंकारी हो जाता है. फिलहाल अधिकांश डकैत तीस वर्ष से नीचे की उम्र के हैं. इनमें से संतोष दीक्षित तथा अजीज तो एमए बीएड हैं. गिरोह में शामिल अधिकांश डकैत स्वभाव से अपराधी नहीं हैं. सामान्यतया वे अति भावुक हैं तथा दूसरों की सहायता के लिए सब कुछ अर्पित कर देना भी जानते हैं. पर इतना ज़रूर है कि वे स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं. इस पूरे क्षेत्र में पनपा यह नया और चतुर वर्ग उनकी इस भावना का शोषण करता है तथा उन्हें उलझा देने के बाद खुद अलग हो जाता है. जब वे (डकैत) एक बार पुलिस के चंगुल में आ जाते हैं, तो उन्हें हिंसा का बाकायदा प्रशिक्षण मिलने लग जाता है, जिसमें जेल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है.

मानसिंह के बाद डाकुओं के संसार में भी जाति प्रथा पुख्ता होने लगी. अब गिरोह ठाकुर, ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के आधार पर बनने लगे हैं. गिरोह का अगुवा यह ध्यान रखता है कि वह अपनी बिरादरी का बचाव करे और ग़ैर बिरादरी पर हमला करे. हालांकि, दुश्मन या पुलिस का मुखबिर अपनी जाति का हो या भाई ही क्यों न हो, उसे नहीं बख्शा जाता. इस समय के ज़्यादातर गिरोह पिछड़ी जातियों से आए हुए युवकों के हैं. ठाकुर एवं ब्राह्मण गिरोह नहीं के बराबर हैं. पिछड़े वर्ग के नए गिरोहों में सवर्णों एवं हरिजनों के प्रति विद्धेष का भाव है. इसका एक बड़ा कारण मध्य भारत में चल रही जाति की राजनीति है. लोधी, यादव, काछी, गड़रिया, कुर्मी, खंगार तथा मुसलमान जातियां इधर काफी आक्रामक हुई हैं.

डाकुओं के पास सामान्यतया एक बड़ा झोला, थाली-लोटा, बिछाने के लिए कैनवास का कपड़ा, फोम का पतला गद्दा तथा कारतूस होते हैं. दो-चार पुलिस मुठभेड़ों के बाद उनमें द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है, वे आत्मसमर्पण और हिंसा की निरंतरता के बीच झूलते रहते हैं. पुलिस एवं स्वार्थी तत्वों के कारण समर्पण जब संभव नहीं रहता, तब निराशा में उनसे हत्याएं होने लगती हैं. विक्रम मल्लाह एवं फूलन देवी द्वारा की जा रही हत्याएं इसी मानसिकता का परिणाम हैं. हरिजनों को आज भी अछूत माना जाता है, लेकिन उनके लड़के एमए-बीए कर रहे हैं. ऐसे युवकों में उच्च वर्ग के प्रति आक्रामक भाव जागा है. हरिजनों ने इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनाई है, भूमिहीन हरिजनों की संख्या बहुत नगण्य है. दूसरी तरफ़ है क्षत्रियों एवं ब्राह्मणों का स्वाभिमान तथा उनकी आर्थिक स्थिति का गिरना. दोनों के वर्गगत दबाव आमने-सामने खड़े हो जाते हैं.

मानसिंह के बाद डाकुओं के संसार में भी जाति प्रथा पुख्ता होने लगी. अब गिरोह ठाकुर, ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के आधार पर बनने लगे हैं. गिरोह का अगुवा यह ध्यान रखता है कि वह अपनी बिरादरी का बचाव करे और ग़ैर बिरादरी पर हमला करे. हालांकि, दुश्मन या पुलिस का मुखबिर अपनी जाति का हो या भाई ही क्यों न हो, उसे नहीं बख्शा जाता. इस समय के ज़्यादातर गिरोह पिछड़ी जातियों से आए हुए युवकों के हैं. ठाकुर एवं ब्राह्मण गिरोह नहीं के बराबर हैं. पिछड़े वर्ग के नए गिरोहों में सवर्णों एवं हरिजनों के प्रति विद्वेष का भाव है. इसका एक बड़ा कारण मध्य भारत में चल रही जाति की राजनीति है. लोधी, यादव, काछी, गड़रिया, कुर्मी, खंगार तथा मुसलमान जातियां इधर काफी आक्रामक हुई हैं. इनका निशाना सवर्ण जातियां हो रही हैं. सन् 1972 के समर्पण में दस प्रतिशत डकैत ऐसे थे, जिनके सामने यौन तुष्टि की समस्या थी. वे ऐसे नौजवान थे, जिनकी उम्र होते हुए भी शादी नहीं हुई थी, उम्मीद भी नहीं थी. इसलिए गिरोह में शामिल होने के बाद वे यौन अपराध करते रहे या जबरदस्ती पैसा देकर उन्होंने छोटी उम्र की लड़कियों से शादी की. मेव बिरादरी में लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियां कम. इसलिए एक की शादी होती है, बाकी भाई अक्सर ऐसे गिरोहों में शामिल होकर अपनी वासनापूर्ति करते हैं. बहुत-से ऐसे लड़के भी, जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, डाका डालते हैं. कालपी, चर्खी, कुठौंद, माधोगढ़ एवं रामपुरा कदौंरा के पचासों नवयुवक सूचीबद्ध गिरोहों के नाम पर डकैती की वारदातें कर रहे हैं.■

क्रमश:

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

यह भारतीय राजनीति के लिए शुभ संकेत है

भारतीय राजनीति में यह घटना इसलिए छोटी नहीं है, क्योंकि जितने नाम हम दलों के नेताओं के रूप में यहां लिख रहे हैं, ये सब कभी एक थे और वह सन् 89 था. लेकिन उसके बाद विभिन्न कारणों, विभिन्न अंतर्विरोधों और विभिन्न महत्वाकांक्षाओं के चलते ये सब अलग-अलग हो गए और इन्होंने अपनी अलग-अलग पार्टियां बना लीं. कोई कहीं सत्ता में आया, तो कोई कहीं सत्ता में आया और कोई कभी भी सत्ता में नहीं आया. इस स्थिति ने भारतीय राजनीति में एक ऐसा शून्य पैदा किया, जिसने एक तरफ़ धीरे-धीरे कांग्रेस से विश्वास ख़त्म किया और दूसरी तरफ़ भारतीय जनता पार्टी को इतना विश्वास दे दिया कि वह अपराजेय और अजेय लगने लगी. भारतीय जनता पार्टी के लिए यह स्थिति सुखद थी.

जनता परिवार के इकट्ठा होने की घटना कोई सामान्य घटना नहीं है. इस घटना का स्वागत करना चाहिए. जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वे एक नई आशा लेकर आ रहे हैं, भारतीय राजनीति में विपक्ष के नाम के विशाल शून्य को भरने की आशा. यह लोकतंत्र को ज़िंदा रखने वाली आशा है. इस समय कोई भी दल ऐसा नहीं है, जो सरकार के सामने सवाल खड़ा कर सके, उसके द्वारा किए गए कामों का विश्लेषण कर सके और उन सारी बातों का, जिनका हिंदुस्तान की जनता के ऊपर ग़लत असर पड़ सकता है, विरोध कर सके. कांग्रेस को यह काम करना चाहिए था. संसद में वह भले ही विपक्षी दल न हो, लेकिन सबसे ज़्यादा सदस्य लोकसभा में उसी के पास हैं. पर कांग्रेस यह काम नहीं कर रही है. संसद में न सोनिया गांधी का भाषण हो रहा है और न राहुल गांधी का. मल्लिकार्जुन खड़गे को लोग अभी भी एक डमी विपक्षी नेता के रूप में देखते हैं.

जनता परिवार के लोग अगर इकट्ठे होते हैं, तो आने वाले चुनाव में यह दल पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकेगा, ऐसी आशा दिखाई दे रही है और लोकतंत्र में सशक्त माने जाने वाले दल का मुकाबला होना ही चाहिए. आने वाले चुनावों में पंजाब महत्वपूर्ण है, उसके बाद बिहार महत्वपूर्ण है. बल्कि यह कहें कि बिहार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार की जीत और हार का असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ने वाला है. इसलिए जनता परिवार में शामिल नेताओं के सारे अंतर्विरोध देखने के बाद भी यह दल स्वागत योग्य है. इस दल को बनाने में सभी का कुछ न कुछ योगदान है, जिनमें नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, ओमप्रकाश चौटाला और एचडी देवेगौड़ा शामिल हैं. पर सबसे ज़्यादा श्रेय अगर किसी को देना चाहिए, तो वे हैं नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव. श्री ओमप्रकाश चौटाला और एचडी देवेगौड़ा पहले से चाहते थे कि यह दल बने, लेकिन इनमें वह शक्ति नहीं थी कि सबको इकट्ठा कर सकें. नीतीश कुमार ने बार-बार मुलायम सिंह के दरवाजे जाकर न केवल उन्हें तैयार किया, बल्कि लालू प्रसाद के दरवाजे जाकर इस बात की आशा पैदा कर दी कि किसी जमाने में ये तीनों टूटे हुए मित्र आपस में मिलकर एक बड़े दल का आधार बन सकते हैं.

दिल्ली में 27 और 28 मार्च दो ऐसे दिन थे, जिनमें अंतिम रूप से इस दल की नींव पड़ी. सभी चाहते थे, लेकिन जब नीतीश मुख्यमंत्री बनकर दिल्ली आए, तो उन्होंने मुलायम सिंह से साफ़ कहा, लालू यादव से भी साफ़ कहा कि मोर्चा नहीं दल चाहिए. अगर दल नहीं बनता है, तो हम जनता को विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि हम उसके सवालों पर लड़ रहे हैं. मुलायम सिंह जी के यहां कुछ ऊहापोह थी, लेकिन मुलायम सिंह ने आधे घंटे की बातचीत के बाद एकतरफ़ा फ़ैसला लिया कि एक दल बनना ही चाहिए. वहीं पर यह तय हो गया कि दल का नाम, दल का झंडा, दल का चुनाव चिन्ह क्या होगा और एक कागज सामने रखकर शरद यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार और मुलायम सिंह जी ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी.

भारतीय राजनीति में यह घटना इसलिए छोटी नहीं है, क्योंकि जितने नाम हम दलों के नेताओं के रूप में यहां लिख रहे हैं, ये सब कभी एक थे और वह सन् 1989 था. लेकिन उसके बाद विभिन्न कारणों, विभिन्न अंतर्विरोधों और विभिन्न महत्वाकांक्षाओं के चलते ये सब अलग-अलग हो गए और इन्होंने अपनी अलग-अलग पार्टियां बना लीं. कोई कहीं सत्ता में आया, तो कोई कहीं सत्ता में आया और कोई कभी भी सत्ता में नहीं आया. इस स्थिति ने भारतीय राजनीति में एक ऐसा शून्य पैदा किया, जिसने एक तरफ़ धीरे-धीरे कांग्रेस से विश्वास ख़त्म किया और दूसरी तरफ़ भारतीय जनता पार्टी को इतना विश्वास दे दिया कि वह अपराजेय और अजेय लगने लगी. भारतीय जनता पार्टी के लिए यह स्थिति सुखद थी. उसने इन सभी नेताओं के अंतर्विरोधों और कांग्रेस की काहिली का फ़ायदा उठाया तथा सालों बाद केंद्र में एकदलीय बहुमत की सरकार बना ली.

भारतीय जनता पार्टी के पास काम करने के लिए एक बड़ा वक्त था. भारतीय जनता पार्टी यह आभास अभी तक नहीं दे पाई है कि वह इस देश के 80 प्रतिशत लोगों के पक्ष में फ़ैसला ले सकती है. उल्टे उसके क़दम यह बता रहे हैं कि जिन्होंने उसे वोट देकर जिताया, उनके पक्ष में वह फ़ैसला नहीं ले सकती. बल्कि वह उन 20 प्रतिशत लोगों, जिनके पास धन, संपत्ति, गाड़ियां,अट्टालिकाएं हैं, लेकिन जिन्होंने वोट नहीं दिया, के पक्ष में फ़ैसला लेने वाली है और इसका बुनियादी आधार उसने बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था को बनाया है तथा बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पश्चिमी देशों के सर्वशक्तिमान अमेरिका तक पहुंचती है. अमेरिका भारत के वंचितों, ग़रीबों एवं दलितों के पक्ष की योजनाएं हिंदुस्तान में नहीं देखना चाहता. वह उतना ही देखना चाहता है, जब तक इस परिभाषा में आने वाले वर्ग ज़िंदा रहते हैं. उन्हें वह उतना ही दिलवाना चाहता है, जितने से वे ज़िंदा रहें और मशीन-पुर्जे की तरह काम कर सकें.

ऐसे समय में मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, एचडी देवगौड़ा और ओमप्रकाश चौटाला का मिलना सराहनीय माना जाएगा. ये सभी प्रत्यक्ष तौर पर किसानों, मज़दूरों और इस देश के 80 प्रतिशत लोगों के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं. ये लोग बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था का कभी न कभी सैद्धांतिक रूप से विरोध कर चुके हैं. इसलिए इनका खड़ा होना एक तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ एक ताकत का खड़ा होना है. पर सवाल है कि जिन महत्वाकांक्षाओं और अंतर्विरोधों की वजह से ये सारे लोग अलग हुए थे, उन महत्वाकांक्षाओं और अंतर्विरोधों का सामना इन्हें फिर करना पड़ेगा. और ऐसे में, नया जनता परिवार पुरानी जनता पार्टी की तरह व्यवहार करेगा कि वह सिर्फ़ अपने नज़दीकी लोगों को नए बने दल में हर जगह देखना चाहेगा और दूसरे लोगों को दूसरे घटक के रूप में देखेगा. तो फिर यह दल पुरानी जनता पार्टी के रास्ते पर चल निकलेगा. मुझे याद है कि जब जनता पार्टी बनी थी, तब कांग्रेस (ओ) के लोग अपने लोगों का हित देखते थे, समाजवादी लोग अपने लोगों का हित देखते थे, जनसंघ के लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लोगों का हित देखते थे. वह चीज इस नए बनने वाले दल में न आए, यह अति आवश्यक है.

पुरानी जनता पार्टी के, फिर पुराने जनता दल के, पुराने समाजवादी आंदोलन के भीतर निहित अंतर्विरोध इस नए बनने वाले जनता परिवार के सामने आए, तो यह हिंदुस्तान की जनता के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात होगा. और, उसके बाद जनता का विश्वास लोकतंत्र से संभवत: उठ जाएगा. आज जनता के पक्ष में वामपंथी बोलते हैं, लेकिन उनके पास ताकत नहीं है. समाजवादी कहने को समाजवादी हैं, लेकिन उनका एक बड़ा धड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गया है. भारतीय जनता पार्टी बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था के प्रति समर्पित है. कांग्रेस ने बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था को शुरू ही किया और अपने ही सर्वमान्य नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू की वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से वह दूर चली गई. कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर इतिहास यह आरोप लगाएगा कि इन्होंने बिना संविधान को बदले संविधान को बदल दिया. संविधान में लिखी हुई किसी भी धारा का पालन, जिसका जनता से रिश्ता से है, आज नहीं हो रहा है. दोनों ही दल बाज़ार के पक्ष में खड़े हैं.

ऐसे समय में, इन दलों-नेताओं का मिलना इसलिए नहीं आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, बल्कि इसलिए आवश्यक है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र बचा रहे और जनता के सामने सत्ता के मुकाबले विपक्ष के सवाल आगे आते रहें, ताकि आने वाले चुनाव में, चाहे वे राज्य के हों या केंद्र के, लोगों के सामने एक ईमानदार विकल्प मौजूद रहे कि उसे किसे वोट देना है. इसलिए मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, एचडी देवेगौड़ा और ओमप्रकाश चौटाला की यह ज़िम्मेदारी है कि वे हिंदुस्तान की जनता की आशा पर खरे उतरें और इतिहास में अपना नाम अच्छे पृष्ठ पर दर्ज कराएं, न कि ऐसे काम करें, जिनसे इतिहास इन्हें खलनायक के रूप में याद करे. इतिहास से भी बड़ा सवाल लोकतंत्र के भविष्य का है. आशा है, ये सारे नेता लोकतंत्र के भविष्य को मिलकर संवारेंगे, उसके साथ खेल नहीं करेंगे.■

editor@chauthiduniya.com

हिंदू होने का मतलब

हिंदुत्व की विचारधारा का अधिक प्रचार-प्रसार उच्च जाति, खास तौर पर ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है. इस बात पर कोई बहस नहीं होती कि निम्न जाति के लोग पौराणिक कथाओं और ब्राह्मणवादी दर्शनशास्त्र पर क्या सोच रखते हैं. ज्योतिबा फुले पहले आधुनिक लेखक थे, जिन्होंने तीखे ब्राह्मणवाद विरोधी विचार व्यक्त किए. डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर ब्राह्मणवादी आध्यात्मिकता के दिखावे के विरोध में लगातार आलोचनात्मक लेख लिखते रहे. भगवद्गीता पर उनकी आलोचना पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ब्राह्मणवाद के इस महान ग्रंथ को पिछड़ी जाति के लोग कितने अलग तरीके से देखते हैं.

मेघनाद देसाई

हिंदू धर्म सहिष्णु हो सकता है, लेकिन हिंदू समाज असहिष्णु और भेदभावपूर्ण है. अद्वैतवाद की प्रशंसा तो की जा सकती है, लेकिन शूद्र और अति-शूद्र के लिए जो अवमानना का भाव है, उसका सामंजस्य आप एक सार्वभौमिक ब्राह्मण व्यवस्था के साथ कैसे स्थापित करेंगे? हिंदू समाज अपनी बहुसंख्यक आबादी के साथ दुर्व्यवहार करता रहा है. यहां तक कि भगवद्गीता भी इस पूर्वाग्रह को रेखांकित करती है, जहां वह दो उच्च वर्णों की तुलना वैश्य और शूद्र वर्णों के सांसारिक पात्रों से करती है (अध्याय 18, श्लोक 41-48).

ईसाई प्रार्थना की एक पंक्ति है कि जब एक भी पापी या गुनहगार प्रायश्चित करता है, तो स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है. हालांकि, विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) शायद ऐसी संस्था नहीं है, जिसे ईसाई-गुनहगार दायरे में दाखिल किया जा सके, लेकिन अच्छी ख़बर यह है कि वीएचपी ने प्रायश्चित कर लिया है. आख़िरकार उसने पता लगा लिया है कि शायद छुआछूत ही वह वजह थी, जिसके चलते दलितों ने सनातन धर्म छोड़कर अधिक समतावादी धर्म अपना लिए. और, अब भला कोई क्यों घर वापसी करेगा, जबकि उसे पता है कि उस घर में उसके साथ बुरा सुलूक किया जाएगा? इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि बहुत सारे दलितों ने हिंदू धर्म त्याग दिया. दरअसल, हैरानी की बात यह है कि उनकी बड़ी संख्या ने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा. हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थकों की सोच में एक बुनियादी गड़बड़ी है. हमसे बार-बार कहा जाता है कि हिंदू धर्म इतना सहिष्णु है कि धर्मनिरपेक्षता इसकी आत्मा में समाहित है. आपको धर्मनिरपेक्ष भारत और हिंदू भारत में भेद करने की आवश्यकता नहीं है. यह सहिष्णुता एक मिथ्या ज़रूर है, लेकिन हक़ीक़त से बहुत दूर भी नहीं है.

दरअसल, हिंदू धर्म सहिष्णु हो सकता है, लेकिन हिंदू समाज असहिष्णु और भेदभावपूर्ण है. अद्वैतवाद की प्रशंसा तो की जा सकती है, लेकिन शूद्र और अति-शूद्र के लिए जो अवमानना का भाव है, उसका सामंजस्य आप एक सार्वभौमिक ब्राह्मण व्यवस्था के साथ कैसे स्थापित करेंगे? हिंदू समाज अपनी बहुसंख्यक आबादी के साथ दुर्व्यवहार करता रहा है. यहां तक कि भगवद्गीता भी इस पूर्वाग्रह को रेखांकित करती है, जहां वह दो उच्च वर्णों की तुलना वैश्य और शूद्र वर्णों के सांसारिक पात्रों से करती है (अध्याय 18, श्लोक 41-48). वेदों एवं उपनिषदों की तमाम आध्यात्मिकता और महत्व के बावजूद, यह एक अभेद्य तथ्य है कि दलित पुरुषों से साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था. दलित महिलाओं के साथ तो उससे भी बदतर व्यवहार किया जाता था, उन्हें एक वासना की वस्तु समझा जाता था. शूद्र कभी अच्छा कर ही नहीं सकते थे. बहुजन (बहुमत) हिंदू समाज में नुक़सान उठाने वाले लोग थे.हिंदुत्व की विचारधारा का अधिक प्रचार-प्रसार उच्च जाति, खास तौर पर ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है. इस बात पर कोई बहस नहीं होती कि निम्न जाति के लोग पौराणिक कथाओं और ब्राह्मणवादी दर्शनशास्त्र पर क्या सोच रखते हैं. ज्योतिबा फुले पहले आधुनिक लेखक थे, जिन्होंने तीखे ब्राह्मणवाद विरोधी विचार व्यक्त किए. डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर ब्राह्मणवादी आध्यात्मिकता के दिखावे के विरोध में लगातार आलोचनात्मक लेख लिखते रहे. भगवद्गीता पर उनकी आलोचना पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ब्राह्मणवाद के इस महान ग्रंथ को पिछड़ी जाति के लोग कितने अलग तरीके से देखते हैं. अंबेडकर ने जाति और ब्राह्मणवाद के ख़िलाफ़ अनथक लड़ाई लड़ी. जीवन के आख़िरी पड़ाव पर उन्होंने अपने हिंदू साथियों को उनके समाज की खामियां बताना छोड़ दिया और खुद अपने समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया.

महात्मा गांधी ने भी हिंदू समाज को छुआछूत की बुराइयों का एहसास दिलाने का हर संभव प्रयास किया. वह स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू जनसमर्थन का बंटवारा छुआछूत के मुद्दे पर नहीं चाहते थे. जबकि अंबेडकर इसे मुद्दा बनाना चाहते थे. इसके बावजूद वह सवर्णों को छुआछूत ख़त्म करने के लिए राजी नहीं कर पाए. दूसरे लोगों ने हरिजन सेवा के नाम पर केवल दिखावा ही किया, क्योंकि दलितों का शोषण जारी रहा और उनकी अवमानना भी होती रही. स्वतंत्रता के 67 वर्षों बाद भी भारत में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिल रहा है. इसकी वजह यह है कि इस संबंध में हिंदू समाज ने न तो अपने अंदर सुधार किया और न आत्मग्लानि महसूस की. हिंदू समाज इस मामले में सौभाग्यशाली है कि 600 सालों तक के मुस्लिम शासनकाल में जाति व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रही. उन्होंने दलितों का धर्मांतरण करवाया. लेकिन पूरे मुस्लिम शासनकाल के दौरान हिंदू समाज अक्षत बच गया. उसके बाद अंग्रेजों ने वह काम किया, जो धर्मांतरण से भी बदतर था. उन्होंने जाति की परवाह किए बिना सबको आधुनिक शिक्षा में प्रवेश देना शुरू कर दिया.

एक ऐसे समाज में, जहां शिक्षा पर केवल दो ऊंची जातियों का एकाधिकार माना जाता था, वहां यह एक क्रांतिकारी क़दम था. कोई श्याम कृष्ण वर्मा कभी संस्कृत का विद्वान न बन पता और न कोई मोहनदास कर्मचंद गांधी कभी बैरिस्टर बन पाते, अगर अंग्रेज आधुनिक शिक्षा और आधुनिक विचार अपने साथ न लाए होते. दरअसल, शिक्षा ने हिंदू समाज को ईसाइयत से अधिक चुनौती दी. दक्षिण भारतीयों ने इस क्रांति का अधिक लाभ उठाया. जस्टिस पार्टी द्वारा शुरू किए गए ब्राह्मण विरोधी आंदोलन और उसके बाद पेरियार के द्रविड़ आंदोलन ने दक्षिण भारत को उत्तर भारत से बिल्कुल अलग कर दिया. उत्तर के राज्य अभी भी अपने भूत से चिपके हुए हैं. दरअसल, यही वे बीमारू राज्य हैं, जो हिंदुत्व के गढ़ हैं. दक्षिण भारत ने मानव विकास सूचकांक पर उत्तर भारत को पीछे छोड़ दिया है. जाति व्यवस्था हिंदू समाज को बांटती है. विश्व हिंदू परिषद हिंदू राष्ट्र के सपने देख रही है, लेकिन हिंदू होने का मतलब है विभाजित और खंडित होना. और, यही वह चीज़ है, जो भारत को विश्व हिंदू परिषद से बचा लेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

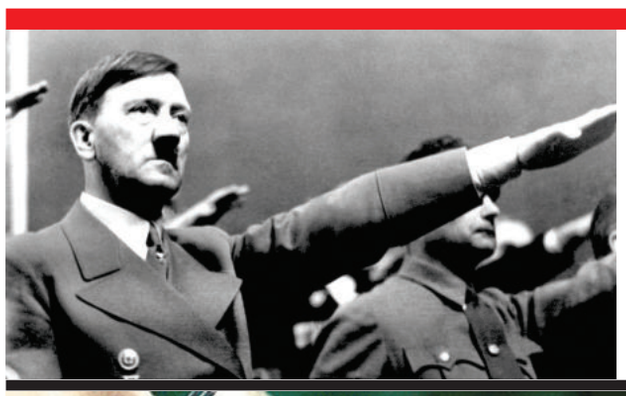

वे जर्मनी के नेशनल समाजवाद की प्रशंसक थीं. इसके अलवा वे एक ईसाई होने के बावजूद हिंदू धर्म की समर्थक थीं. उनका हिटलर में इतना विश्वास था कि वे भगवान विष्णु का अवतार मानती थीं. वो ऐसा मानती थीं कि जर्मनी का तानाशाह हिटलर मानवता के लिए बलिदान कर रहा था और उसके प्रयासों से कलियुग का अंत होगा. वे यहूदियों को शैतानी ताकत मानती थीं और उनके विरोध में किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं. उनके लेखों की वजह से नवनाजीवाद काफी प्रभावित था.

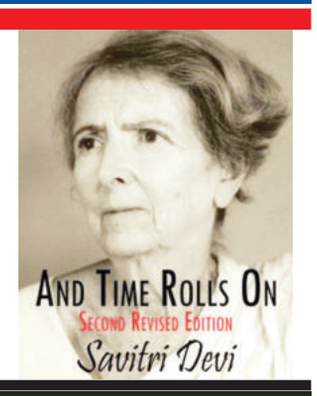

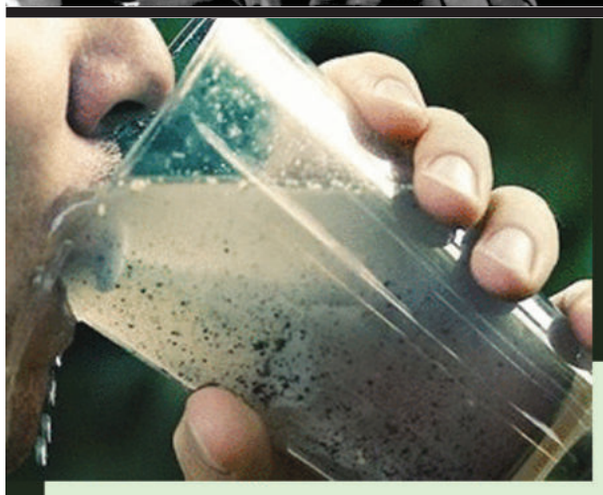

पीलिया

साफ-सफाई का रखें ख्याल

मोनिशा भटनागर

क्या है पीलिया

मौसम बदलने के साथ ही पीलिया (जॉन्डिस) का प्रकोप भी बढ़ जाता है. गर्मियों और बरसात के मौसम में होने वाली सबसे प्रमुख बीमारियों में से एक है पीलिया. मेडिकल की भाषा में वायरल हैपेटाइटिस या जॉन्डिस को लोग आमतौर पर पीलिया के नाम से जानते हैं. यह रोग बहुत ही सूक्ष्म विषाणु से होता है. पीलिया ऐसा रोग है जो एक विशेष प्रकार के वायरस और किसी कारणवश शरीर में पित्त (बिलीरूबिन) की मात्रा बढ़ जाने से होता है. इसमें रोगी के नाखून, त्वचा एवं आखों का सफ़ेद भाग पीला पड़ जाता है. बीमारी की शुरुआत में जब रोग मामूली होता है तब इसके लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, परन्तु जब यह उग्र रूप धारण कर लेता है तो रोगी की आंखे व नाखून पीले दिखाई देने लगते हैं, इसलिये ही लोग इसे पीलिया कहते हैं. पीलिया शरीर के नार्मल मेटाबोलिज्म या बिलुरुबिन (पित्त) के एक्सक्रीशन के सामान्य रूप से काम न करने से होता है. पीलिया आमतौर पर चेहरे पर सबसे पहले दिखाई देता है और फिर जैसे-जैसे बिलुरुबिन का स्तर बढ़ता है छाती, पेट और हाथ- पैर पर भी इसका असर दिखना शुरू हो जाता है.

पीलिया होने का कोई एक कारण नहीं है. यह रोग कई कारणों से हो सकता है जैसे रक्त रोग, आनुवंशिक सिंड्रोम्स, पित्त नलिकाओं की रुकावट, इनफेक्शन, या कुछ दवाई के परिणामस्वरूप. इसके अलावा पीलिया मुख्य तीन प्रकार के वायरस से होता है वायरल हैपेटाइटिस ए, वायरल हैपेटाइटिस बी तथा वायरल हैपेटाइटिस नॉन ए और नॉन बी. हेपेटाइटिस या सिरोसिस जैसी लिवर की बीमारियां पीलिया का एक बड़ा कारण हैं. असल में पीलिया ज़्यादातर किसी अंतर्निहित रोग का एक स्पष्ट संकेत होता है. इसलिए ही इसकी जांच तुरंत डॉक्टर से

करवाना बहुत जरूरी होता ज़रूरी होता है.

लक्षण

पीलिया का सबसे प्रमुख लक्षण है शरीर का पीलापन खासकर नाखून और आखों का सफ़ेद भाग पीला पड़ जाना. गहरा पीला पेशाब आना और पूरी त्वचा पीली पड़ने से भी इस रोग की पहचान होती है. इसके अलावा बेहद कमजोरी, कब्जियत, जी मिचलाना और कभी कभी उल्टियां होना, सिरदर्द और भूख न लगना भी इसके लक्षण हैं. पीलिया का रोगी हर समय थका-थका सा लगता है. ऐसे में भूख तो कम लगती ही है लेकिन चिकनाई वाले खाने से खास अरुचि हो जाती है.

क्या सावधानी बरतें

पीलिया के मरीज़ों को पूरी तरह बेड-रेस्ट करना चाहिए. शरीर को पूरा आराम मिले इसलिए ज़्यादा घूमना-फिरना नहीं चाहिये साथ ही कोई भी ऐसा काम जिससे थकान हो, नहीं करना चाहिए. डॉक्टर से नियमित रूप से जांच कराते रहना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ही कुछ खाने पीने की चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए. भोजन में प्रोटीन और कार्बोज वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिये. चिकनाई युक्त खाने की चीज़ें जैसे घी, तेल, मक्खन, मलाई कम से कम या बिल्कुल प्रयोग में नहीं लाने चाहिए. पीलिया के रोगियों को ऐसा भोजन करना चाहिए जो कि आसानी से पच जाए. जैसे मूंग की खिचड़ी, दलिया, चीकू और

पपीता आदि फल, उबली हुई सब्जियां या कार्बोहाड्रेड वाले पदार्थ खाने चाहिए. पीलिया के रोगियों को मैदा, मिठाइयां, तले हुए पदार्थ, अधिक मिर्च मसाले, उड़द की दाल और खोया से खास तौर पर परहेज़ करना चाहिए.

पीलिया से बचने के लिये कुछ साधारण बातों का ध्यान रखना जरूरी है-

खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले व बाद में और शौच जाने के बाद में हाथ साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए. भोजन हमेशा से ढंक कर रखना चाहिये, ताकि मक्खियों व धूल से बचाया जा सके. गर्मियों में खासकर ताजा खाना ही खाना चाहिए और खुला खाना बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. साथ ही गंदे, सड़े-गले व कटे हुये फल न खायें. धूल पड़ी या मक्खियां बैठी मिठाइयों का सेवन न करें. दूध व पानी का सेवन भी उबाल कर करें. पीने के पानी की शुद्धता का खास ख्याल रखें. इसके अलावा साफ़ सफाई पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, खुला पड़ा कूड़ा कचरा बीमारी का बहुत बड़ा कारण है. स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें और खुले में शौच न जाएं. सफाई और खाने-पीने पर ध्यान के अलावा पहले प्रयोग किये हुए इन्जेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अगर किसी को खून चढाने की आवश्यकता हो तो उस खून को जांच के बाद ही चढ़ाना चाहिए. रक्त देने वाले व्यक्तियों की पूरी तरह जांच करने से भी बी प्रकार के पीलिया रोग के रोगवाहक का पता लग सकता है.

आयुर्वेद में उपचार

आयुर्वेद चिकित्सकों के अनुसार यदि मकोय की पत्तियों को उबाल कर उनका सेवन किया जाए तो पीलिया से जल्द राहत मिलती है. कच्चा पपीता सलाद के रूप में लिया जाए तो भी पीलिया का असर कम होता है. इसके अलावा धनिया के बीज को रातभर पानी में भिगो कर फिर सुबह उसका पानी पीने से भी लाभ होता है.धनिया के बीज वाले पानी को पीने से लीवर से गंदगी साफ होती है. ऐसे ही एक गिलास पानी में एक बड़ा चम्मच पिसा हुआ त्रिफला रात भर के लिए भिगोकर रख दें. सुबह इस पानी को छान कर पी जाएं. नींबू, संतरे तथा गन्ने का रस भी इस रोग में गुणकारी होता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सावित्री देवी

धुरी राष्ट्रों की जासूस

चौथी दुनिया ब्यूरो

सावित्री देवी एक ऐसी जासूस थीं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नाजी सेना और धुरी राष्ट्रों के लिए मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जासूसी की थी. उनका वास्तविक नाम मैक्सिमियानी पोर्तास था. उनका जन्म 30 सितंबर 1905 को हुआ था. वे जानवरों के अधिकारों के लिए भी काम किया करती थीं. उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध बीत जाने के बाद नाजीवाद के पक्ष में मूवमेंट चलाने और उसे आगे बढ़ाने को लेकर काफी काम किया था.

वे जर्मनी के नेशनल समाजवाद की प्रशंसक थीं. इसके अलवा वे एक ईसाई होने के बावजूद हिंदू धर्म की समर्थक थीं. उनका हिटलर में इतना विश्वास था कि वे उसे भगवान विष्णु का अवतार मानती थीं. वो ऐसा मानती थीं कि जर्मनी का तानाशाह हिटलर मानवता के लिए बलिदान कर रहा था और उसके प्रयासों से कलियुग का अंत होगा. वे यहूदियों को शैतानी ताकत मानती थीं और उनके विरोध में किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं. उनके लेखों की वजह से नवनाजीवाद काफी प्रभावित था.

सावित्री यूनानी मूल के फ्रांसीसी नागरिक मैक्सिम पोर्तास और अंग्रेज महिला जूलिया पोर्तास की पुत्री थीं. सावित्री देवी ने बहुत कम उम्र में ही अपना एक राजनीतिक झुकाव निश्चित कर लिया था. उनका शुरुआती राजनीतिक रुझान यूनानी राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ था. सावित्री ने फिलॉसफी और कमेस्ट्री में परास्नातक किया था. उन्होंने फ्रांस के नियोल विश्वविद्यालय से फिलॉसफी विषय में अपने डॉक्टरेट पूरी की थी. इसके बाद से यूनान चली गईं जहां उन्होंने पुरातात्विक इमारतों के बारे में अध्ययन किया और स्वास्तिक के बारे में अध्ययन किया. उनका यह निष्कर्ष था कि प्राचीन समय के यूनानी लोग वास्तविकता आर्य थे.

साल 1928 के आस-पास उन्होंने फ्रेंच नागरिकता छोड़ दी और यूनान की नागरिकता ले ली. साल 1932 में वे आर्यन थ्योरी की तलाश में भारत आईं और हिंदू नाम ग्रहण किया था. वे हिंदू संस्कृति से इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने भारत में यहूदी और ईसाईयों के खिलाफ एक मिशनरी के तौर पर भी काम करना शुरू कर दिया. इस दौरान धुरी राष्ट्रोंके लिए भारत में माहौल बनाने का काम भी किया करती थीं.उन्होंने इस काम को करने के लिए धुरी राष्ट्रों की तरफ से सहयोग भी मिलता था. भारत के भी कई वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनसे संपर्क में रहा करते थे. वे सुभाष चंद्र बोस के भी संपर्क में आईं और अपने संपर्क सूत्रों के जरिये सुभाष चंद्र बोस को जापान के महाराजा से मिलवाने में मदद की.

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सावित्री देवी ने धुरी राष्ट्रों के पक्ष में काम करना शुरू किया. लेकिन उनके इस निर्णय से उनकी मां काफी क्रोधित थीं क्योंकि वे खुद मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर काम कर रही थीं. उनकी मां का मानना था कि धुरी राष्ट्रों ने दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में ढकेलने का काम किया है. 1940 में उन्होंने एक नेशनल सोशलिस्ट असित कृष्ण मुखर्जी से शादी की. असित जर्मनी समर्थक समाचार पत्र न्यू मर्करी के संपादक थे.

सावित्री और असित दोनों ही मित्र राष्ट्रों के अधिकारियों के संपर्क में रहते थे. वे मित्र राष्ट्रों के अधिकारियों से ज्यादा संख्या में परिचय बनाने का प्रयास भी किया करते थे जिससे उनके गोपनीय जानकारियां उगलवाकर वे धुरी राष्ट्रों के देशों तक पहुंचा सकें. वे इन गोपनीय जानकारियों को साधारणतया जापान तक पहुंचाया करते थे और इन्हीं जानकारियों के आधार पर धुरी देश मित्र देशों के एयर और मिलिट्री बेस पर हमले किया करते थे.

सावित्री यूनानी मूल के फ्रांसीसी नागरिक मैक्सिम पोर्तास और अंग्रेज महिला जूलिया पोर्तास की पुत्री थीं. सावित्री देवी ने बहुत कम उम्र में ही अपना एक राजनीतिक रुझान निश्चित कर लिया था. उनका शुरुआती राजनीतिक रुझान यूनानी राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ था. साबित्री ने फिलॉसफी और कमेस्ट्री में परास्नातक किया था.

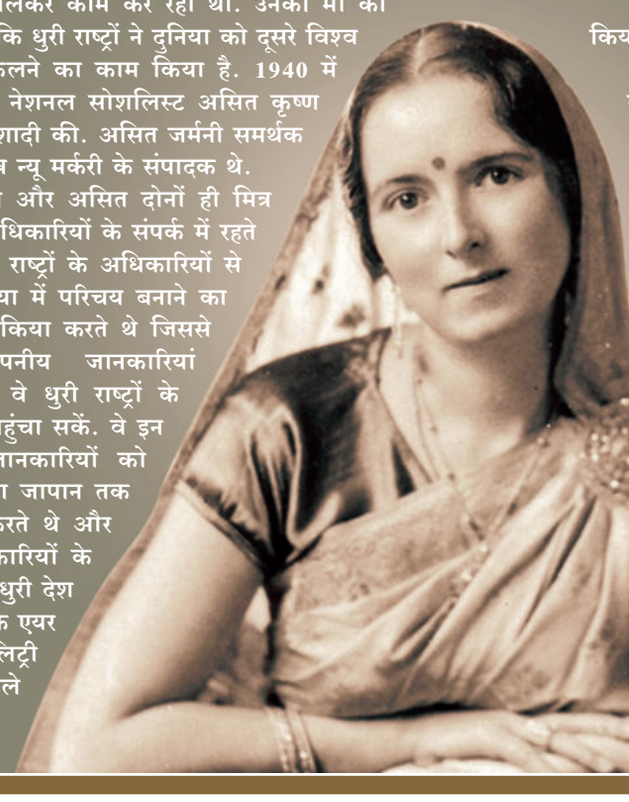

जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई तो सावित्री यूरोप की यात्रा पर गईं. इसके बाद कई देशों की यात्रा कर वे जर्मनी पहुंची जहां पर उन्होंने गोपनीय तरीके से कई हजार पैम्फलेट लिखे और लोगों तक पहुंचाए. उनका मानना था कि नाजी विचारधारा के नेशनल सोशलिजम को देश के लोगों को अपनाना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए.

उनकी इन सब गतिविधियों की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दो साल की सजा सुनाई गई. जेल में रहने के दौरान उन्होंने नाजी कैदियों के साथ मित्रता बना ली थी. जेल से निकलने के बाद उन्हें जर्मनी से निष्काषित कर दिया गया था. इसके कुछ साल बाद वे एक बार फिर किसी तरह से जर्मनी चली गईं और वहां पर आर्यन और हिटलर की नाजी पार्टी को मिलाकर एक किताब लिखी जिसका नाम था पिलग्रिमेज.

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद नाजी विचारधारा को कहीं भी पसंद नहीं किया जा रहा था लेकिन सावित्री उसके प्रचार प्रसार को लेकर गोपनीय रूप से लगातार सक्रिय रहीं. उन्होंने पूरी कोशिश की कि लोग एक बार फिर नाजियों के साथ जुड़ें लेकिन उनकी मुहिम काम न आ सकी. 1970 के दशक के आखिरी में उनकी आंखें कमजोर हो गईं थी. उनकी तबियत लगातार खराब रहने लगी. वे भारत छोड़ कर 1981 में फ्रांस चली गईं जहां अपने आखिरी दिन उन्होंने गुजारे. साल 1982 में उनकी मौत हो गई.

दरअसल सावित्री देवी सिर्फ एक जासूस नहीं थीं बल्कि वह कई क्षेत्रों में काम किया करती थीं. आर्यन थ्योरी को लेकर उन्होंने हिटलर के नाजीवाद का भी समर्थन किया. ■

feedback@chauthiduniya.com

यमन से वापस लाए जा रहे हैं नागरिक

केन्द्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की देखरेख में भारत अपने नागरिकों को यमन छोड़ने की एडवाइजरी जारी करने के बाद भारतीय वायुसेना ने लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए पूरी मुस्तैदी से दो भारी परिवहन विमान तैनात कर दिए. बता दें परिवहन विमानों का इस्तेमाल मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) अभियान में व्यापक तौर पर हो रहा है. भारतीय वायुसेना ने पिछले साल जम्मू-कश्मीर में बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने में अपनी क्षमता साबित करने के बाद एक बार फिर यमन से लोगों को निकालने में सहायता देकर आपदा राहत अभियान में महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा है. यमन में हौती विद्रोहियों की बढ़ती ताकत और देश में बढ़ती हिंसा के बाद भारतीय सरकार ने अपने नागरिकों के लिए यह अलर्ट जारी किया था कि वे जितनी जल्द हो सके, यमन छोड़ दें. लोगों को भारत लेकर वायुसेना का पहला सी-17 विमान कोच्चि हवाई अड्डे पहुंचा. इसमें 168 यात्री सवार थे. दूसरा सी-17 विमान 190 यात्रियों को लेकर मुंबई हवाई अड्डा पहुंचा. भारत के विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह यमन से सुरक्षित निकाले जा रहे भारतीयों की जानकारी के लिए स्वयं दिजीबोती पहुंचे थे. उन्होंने इस दौरान पूरे ऑपरेशन की जानकारी ली.

नया नेता तैयार कर रही पीपीपी

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपना नया नेता तैयार करने के मूड में लग रही है. दरअसल पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो पार्टी संचालन के मुद्दे पर अपने पिता आसिफ अली जरदारी से मतभेदों के बाद रूठकर लंदन में टिके हुए हैं. ऐसे में यह माना जा रहा है कि पार्टी में उनकी जगह बहन बख्तावर भुट्टो लेंगी. पीपीपी के प्रवक्ता शरजील मेमन ने बताया कि नई भूमिका के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं. मेमन ने बिलावल और जरदारी के बीच मतभेदों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की. अफवाहें हैं कि बिलावल पार्टी हाई कमांड में बदलाव करने की इजाजत नहीं मिलने के बाद 2014 में पाकिस्तान से चले गए. बिलावल के पाकिस्तान से इस तरह चले जाने की वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी निराशा देखी जा रही थी. कार्यकर्ता यही मानकर चल रहे थे कि पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बाद बिलावल ही अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे. लेकिन बिलावल इस तरह से ब्रिटेन चले जाने की वजह से कार्यकर्ताओं में काफी निराशा आ गई थी. पार्टी आलाकमान ने इस पर विचार किया कि किसी युवा चेहरे को एक बार फिर पार्टी का नेता बनाया जाए. इस क्रम में बख्तावर को पार्टी कि नए नेता के रूप में पेश करने की तैयारियां जोरों पर हैं. बेनजीर के एक पूर्व सहयोगी नाहीद खान ने कहा कि बिलावल पार्टी के अध्यक्ष हैं लेकिन वे सिंध के मुख्यमंत्री को हटा नहीं सके क्योंकि उनके पिता ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया. बिलावल पार्टी में कुछ बदलाव करना चाहते थे जिसमें उनके पिता के करीबी माने जाने वाले कुछ प्रमुख पदाधिकारियों को हटाना भी शामिल था. बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण वह ऐसा करना चाहते थे. इस मुद्दे पर बिलावल और जरदारी के बीच बहसें हुईं और इस तकरार के बाद बिलावल लंदन चले गए.

पाकिस्तान के दोहरे रवैये से अमेरिका को खतरा

पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी संगठनों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण अमेरिका के दक्षिण एशिया में आतंकवाद का खात्मा करने उद्देश्यों को खतरा पैदा हो गया है. यह मानना है अमेरिका के दो प्रमुख रक्षा विशेषज्ञों का. हेरीटेज फाउंडेशन नामक थिंकटैंक में वरिष्ठ शोधार्थी लीजा कर्टिस और विशेषज्ञ हुमा सत्तार ने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने को लेकर पाकिस्तान का पक्षपातपूर्ण रवैया उस क्षेत्र में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों को कमजोर करता है. उन्होंने एक लेख में कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद का मुकाबला करने को लेकर गंभीर है तो उसे सभी आतंकवादी समूहों को लेकर सख्त होना चाहिए और अफगानिस्तान एवं भारत में अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे आतंकवादियों से सभी तरह के संपर्क खत्म करने चाहिए. दोनों विशेषज्ञों ने साल 2008 के मुंबई हमले के मामले में इस्लामाबाद स्थित आतंकवाद विरोधी अदालत द्वारा जकीउर रहमान लखवी को जमानत दिए जाने का हवाला दिया. लीजा और हुमा ने कहा कि बीते दिसंबर में पेशावर स्थित स्कूल पर तालिबान के जघन्य हमले के दो दिन बाद पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने लखवी को जमानत दे दी. यह चौंकाने वाला घटनाक्रम इसका संकेत हो सकता है कि पाकिस्तानी सेना का भारत को संकेत है कि वह लश्कर-ए-तैयबा को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती रहेगी.

मोदी दुनिया के ताकतवार नेताओं में : जान मैक्केन

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा मानने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है. अमेरिका के एक प्रभावशाली सीनेटर का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनके जीवनकाल के संभवत: सबसे मजबूत भारतीय नेता के रूप में उभरे हैं. उन्होंने साथ ही कहा कि अमेरिका को भारत के साथ और सहयोग बढ़ाने की जरूरत है. सीनेटर जान मैक्केन वर्ष 2008 के राष्ट्रपति पद के चुनावों के उम्मीदवार रह चुके हैं. सीनेटर जान मैक्केन ने कहा कि मैं वास्तव में भारत के नए नेता से बहुत अधिक प्रभावित हुआ हूं. प्रधानमंत्री मोदी संभवत: पहले ऐसे हिंदुस्तानी मजबूत नेता हैं जिसे मैंने अपने अब तक के जीवन काल में भारत में उभरते हुए देखा है. वर्ष 2008 के राष्ट्रपति पद के चुनावों के उम्मीदवार रहे जान मैक्केन ने सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के समक्ष कहा कि अमेरिका को भारत के साथ और अधिक सहयोग बढ़ाने की जरूरत है. अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर ने कहा कि मेरा यह मानना है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव को बनाए रखना हमारे लिए एक बड़ी दीर्घकालिक चुनौती है और हमें ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जैसे कि भारत के साथ अधिक सहयोग बढ़ाना.उल्लेखनीय है 26 जनवरी को जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे तभी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की काफी तारीफ की थी. वे मोदी को मैन विद एक्शन सहित कई उपमाएं दे चुके है. भारत और अमेरिका की इस नयी जुगलबंदी पर पूरे विश्व समुदाय की नजरें टिकी हैं. भारत के लिए यह महत्वपूर्ण हैं कि ,वहां की दोनों प्रमुख पार्टियों डेमोक्रेटिक व रिपब्लिकन एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी दमदार उपस्थिति के लिए भारत से बेहतर संबंध पर जोर देती हैं.

इसमें कोई संदेह नहीं है कि नेतान्याहू चुनाव तो जीत गए हैं लेकिन चुनाव जीतने में उनके द्वारा प्रयोग में लाए गए तरीकों की हर तरफ आलोचना हो रही है. दिक्कत यह है कि जिन भाषणों और वक्तव्यों की बदौलत नेतान्याहू जीते हैं, उन्हें अगर वे भविष्य में भी कायम रखने की कोशिश करेंगे तो फिलिस्तीन के लिए दिक्कत की बात होगी. इसलिए उन पर यह वैश्विक दबाव तो बनता ही जा रहा है कि फिलिस्तीनी राष्ट्र के निर्माण को लेकर संजीदगी दिखाएं. वहीं अमेरिका को भी दबाव के साथ इजरायल को इस बात के लिए राजी करना चाहिए.

नेतान्याहू फिलिस्तीन नहीं बनने देंगे

अरुण तिवारी

बेंजामिन नेतान्याहू एक बार फिर इजरायल के प्रधानमंत्री बन गए हैं. ऐसा माना जा रहा था कि इस बार उनकी लिकुड पार्टी को चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ सकता है लेकिन आश्चर्यजनक चुनाव परिणाम आए और नेतान्याहू फिर चुने गए. चुनाव प्रचार के दौरान नेतान्याहू ने मतदाताओं के बीच यह बयान दिया था कि वे अपने जिंदा रहते कभी फिलस्तीन राज्य का निर्माण नहीं होने देंगे. ऐसे में यह सवाल उठना लाज़िमी हो गया है कि पहले से इजरायली सरकार की वजह से मुसीबतें झेल रही फिलस्तीनी जनता की परेशानियां कब कम होंगी? क्या फिलस्तीनी राष्ट्र के निर्माण को युनाइटेड नेशंस में स्वीकृति मिल पाएगी? आखिर कब तक फिलस्तीन को लेकर जंग चलती रहेगी?

इस बार जब इजरायल में आम चुनावों का बिगुल बजा था तो लग रहा था कि वहां की राष्ट्रवादी लिकुड पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा. राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात के कयास लगा रहे थे कि आम जनता के बीच मुख्य विपक्षी जियोनिस्ट पार्टी को लेकर ज्यादा रुझान है और जीत वो ही हासिल करेगी. आश्यर्चजनक रूप से चुनावी नतीजे कुछ और निकले और बेंजामिन नेतान्याहू एक बार फिर सत्ता पर अपनी दावेदारी बचाने में कामयाब हो गए. चुनाव के कुछ ही दिनों पहले देश के तेल अवीव शहर में नेतान्याहू के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त प्रदर्शन हुए थे. इस प्रदर्शन के दौरान कई गैर सरकारी संगठनों के साथ कुछ विपक्षी पार्टी के नेताओं ने फिलस्तीन के मुद्दे पर नेतान्याहू की आलोचना की थी. प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि नेतान्याहू फिलस्तीन के मुद्दे को वीभत्स रूप देकर मामले को जिंदा रखना चाहते हैं.

दरअसल चुनावों के कुछ दिन पहले ही नेतान्याहू को यह लगने लगा था कि वे चुनाव हार सकते हैं. इसी वजह से ठीक चुनावों के पहले उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि वे कसम खा रहे हैं, फिलस्तीन राष्ट्र का निर्माण नहीं होने देंगे. लोगों के बीच उन्होंने अतिराष्ट्रवादी प्रचार अभियान शुरू कर दिया. इसके अलावा चुनाव के दिन भी उन्होंने विपक्षी पार्टियों, अरब मूल के लोगों और गैर सरकारी संगठनों को भी यह कहते हुए आड़े हाथों लिया था कि ये सभी ट्रकों में भर कर मतदाताओं को लेकर बूथों पर उनके ख़िलाफ़ वोट डलवा रहे हैं. बेंजामिन के ये सारे तरीके काम कर गए और नतीजे वह आए जिसकी चुनाव के पहले किसी ने उम्मीद नहीं की थी. हालांकि चुनाव जीतने के बाद नेतान्याहू ने अरब मूल के लोगों से इस बात के लिए माफी मांगी है.

दरअसल चुनावों के कुछ दिन पहले ही नेतान्याहू को यह लगने लगा था कि वे चुनाव हार सकते हैं. इसी वजह से ठीक चुनावों के पहले उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि वे कसम खा रहे हैं, फिलस्तीन राष्ट्र का निर्माण नहीं होने देंगे. लोगों के बीच उन्होंने अतिराष्ट्रवादी प्रचार अभियान शुरू कर दिया. इसके अलावा चुनाव के दिन भी उन्होंने विपक्षी पार्टियों, अरब मूल के लोगों और गैर सरकारी संगठनों को भी यह कहते हुए आड़े हाथों लिया था कि ये सभी ट्रकों में भर कर मतदाताओं को लेकर बूथों पर उनके ख़िलाफ़ वोट डलवा रहे हैं. बेंजामिन के ये सारे तरीके काम कर गए और नतीजे वह आए जिसकी चुनाव के पहले किसी ने उम्मीद नहीं की थी.

नेतान्याहू के प्रधानमंत्री बनने के बाद फिलिस्तीन राष्ट्र के निर्माण में और देर होने की आशंकाओं ने एक बार फिर जन्म ले लिया है. फिलिस्तीन राष्ट्र के निर्माण को लेकर पूर्व में इजरायल बहुत ही क्रूरता के साथ पेश होता आया है. जैसे नेतान्याहू के प्रधानमंत्री चुनाव में जीतने की खबरें आने के साथ ही फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने वेस्ट बैंक में विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए थे. नेतान्याहू के चुनाव प्रचार के तरीकों को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेतान्याहू के बयान की आलोचना की थी और यह भी माना था फिलिस्तीन के मुद्दे पर उनमें और इजरायली प्रधानमंत्री में मतभेद हैं. इसके अलावा इजरायली राष्ट्रपति रिउवेन रिवलिन ने भी नेतान्याहू के बयान की आलोचना करते हुए कहा था कि वे देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए. इजरायली राष्ट्रपति ने नेतान्याहू को अगली सरकार के गठन का काम सौंपने से पहले अरब-इजरायली मतदाताओं के संबंध में उनकी विवादपूर्ण टिप्पणी की आलोचना की थी. उन्होंने कहा, चुनाव हमारे लोकतंत्र का एकमात्र जनमत संग्रह है. हमें शर्म आनी चाहिए अगर हम मतदान के लोकतांत्रिक कर्तव्य को निभाने को एक अभिशाप या किसी ऐसी चीज की तरह देखें, जिसके ख़िलाफ़ चेतावनी दी जानी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी, जो मतों से डरते हैं, उनका अंत सड़कों पर पथराव में होगा. इजरायली राष्ट्रपति ने कहा, हर ओर से, ऐसी चीजें कही गईं, जो कि एक यहूदी और लोकतांत्रिक देश में कही नहीं जानी चाहिए. आग की लपटों को हवा देने से किसी का भला नहीं होता. आग सिर्फ गर्मी ही नहीं देती, बल्कि लपटों का रूप धारण करने का खतरा भी है. आज उन जख्मों को भरने की शुरुआत करने का समय आ गया है.

हालांकि नेतान्याहू ने खुद को सभी इजरायली नागरिकों का प्रधानमंत्री घोषित करते हुए नुकसान की भरपाई की कोशिश की. उन्होंने कहा कि मैं खुद को आप में से हर एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री के रूप में देखता हूं, फिर चाहे आपने मुझे चुना हो या नहीं. चुनाव के दौरान समाज के विभिन्न धड़ों में जो तनाव पैदा हो गए हैं, मैं उसे हटाने के प्रयास करूंगा. नेतान्याहू ने कहा, मुझे अगली गठित सरकार में इस मार्ग पर डटे रहना है. अगली सरकार एक यहूदी और लोकतांत्रिक देश की सरकार होगी, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देगी, फिर चाहे उनके धर्म, नस्ल या लिंग कोई भी हो. ऐसा हमेशा होता रहा है और यह हमेशा होता रहेगा.

इसमें कोई संदेह नहीं है कि नेतान्याहू चुनाव तो जीत गए हैं लेकिन चुनाव जीतने में उनके द्वारा प्रयोग में लाए गए तरीकों की हर तरफ आलोचना हो रही है. दिक्कत यह है कि जिन भाषणों और वक्तव्यों की बदौलत नेतान्याहू जीते हैं, उन्हें अगर वे भविष्य में भी कायम रखने की कोशिश करेंगे तो फिलिस्तीन के लिए दिक्कत की बात होगी. इसलिए उन पर यह वैश्विक दबाव तो बनता ही जा रहा है कि फिलिस्तीनी राष्ट्र के निर्माण को लेकर संजीदगी दिखाएं. वहीं अमेरिका को भी सिर्फ मुंहजुबानी वायदे करने से बाज़ आना चाहिए और उसे पूरे दबाव के साथ इजरायल को इस बात के लिए राजी करना चाहिए कि फिलिस्तीन का निर्माण हो व वहां के लोगों को भी वह सभी सुविधाएं मिलें जो दुनिया में किसी भी देश के आम नागरिक के लिए जरूरी होती हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
CHAUTHI DUNIYA
چوتھی دنیا
First International Urdu Weekly

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें
CHAUTHI DUNIYA APP

कछुआ बेचारा यह सुनकर निराश हो गया, लेकिन उसकी आसमान देखने की इच्छा बढ़ती ही गई और वह एक दिन फिर अपने मित्रों से बोला,मित्रों! जैसे सारस कई दिन तक सोचते रहे कि कछुए को आसमान में कैसे ले जाया जाएं. अंत में उन्हें एक उपाय सूझा. वे बड़े प्रसन्न हुए और कछुए से तुरन्त आकर बोले, आज हमने तुम्हें आसमान की सैर कराने का उपाय सोच लिया. अब तुम जिस दिन चाहो, हम तुम्हें आसमान की सैर करा सकते हैं. हम दोनों एक लकड़ी को अपनी चोंच में दबा लेंगे और तुम उस लकड़ी को अपने मुंह में दबाकर लटक जाना.

आशा और विश्वास जगाते हैं साई बाबा

चौथी दुनिया ब्यूरो

जो भक्त साई बाबा को केवल भक्तिपूर्वक एक पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है, तो साई बाबा उस शुद्ध अन्त:करण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं. बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते और उनकी समस्त इच्छाओं तथा समाचारों को पहले से ही जान लेते थे.

माधवराव देशपांडे के द्वारा बाबा का हाथ जल जाने का समाचार पाकर श्रीनानासाहेव चांदोरकर, बम्बई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाईयां, लेप तथा पट्टियां आदि साथ लेकर शीघ्रता से शिरडी को आये. उन्होंने बाबा से डॉक्टर को परमानन्द को हाथ की परीक्षा करने और जले हुए स्थान में दवा लगाने की अनुमति मांगी. यह प्रार्थना अस्वीकृत हो गई. हाथ जल जाने के पश्चात एक कुष्ठ–पीड़ित भक्त भागोजी सिंधिया उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे. उनका कार्य था प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना और उसके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से उसे पुन: पूर्ववत कस कर बांध देना. घाव शीघ्र भर जाये, इसके लिये नानासाहेब चांदोरकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानन्द से जांच व चिकित्सा कराने का बाबा से बारंबार अनुरोध किया. यहां तक कि डॉ. परमानन्द ने भी अनेक बार प्रर्थना की, परन्तु बाबा ने यह कहते हुए टाल दिया कि केवल भगवान ही मेरा डॉक्टर है. उन्होंने हाथ की परीक्षा करवाना अस्वीकार कर दिया. डॉ. परमानन्द की दवाइयां शिरडी के वायुमंडल में न घुल सकीं और न उनका उपयोग ही हो सका. फिर भी डॉक्टर साहब की अनुमति मिल गई. कुछ दिनों के उपरांत जब घाव भर गया, तब सब भक्त प्रसन्न हो गये, लेकिन यह किसी को भी ज्ञात न हो सका कि कुछ पीड़ा अवशेष रही थी या नहीं. प्रतिदिन प्रात:काल वही क्रम–घृत से हाथ का मर्दन और पुन: कस कर पट्टी बांधना साई बाबा की समाधि पर्यन्त यह कार्य इसी प्रकार चलता रहा. साई बाबा को इस चिकित्सा की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, परन्तु भक्तों के प्रेमवश, उन्होंने भागोजी की यह सेवा स्वीकार की.

बाबा भक्तों के सभी इच्छाओं को जान जाते हैं और सभी समस्ता इच्छाएं पूर्ण करते हैं इसी पर आधारित है नीचे दी गई कथा.

एक बार गोवा के एक मामलतदार ने, जिनका नाम राले था, लगभग 300आमों का एक पार्सल शामा के नाम शिरडी भेजा. पार्सल खोलने पर प्राय: सभी आम अच्छे निकले. भक्तों में इनके वितरण का कार्य शामा को सौंपा गया. उनमें से बाबा ने चार आम दामू अण्णा के लिये पहले निकाल कर रख लिये.

दामू अण्णा की तीन स्त्रियां थीं. परन्तु अपने दिये हुये वक्तव्य में उन्होंने बतलाया था कि उनकी केवल दो ही स्त्रियां थीं. वे सन्तानहीन थे, इस कारण उन्होंने अनेक ज्योतिषियों से इसका समाधान कराया और स्वयं भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा सा अध्ययन कर ज्ञात कर लिया कि जन्म कुण्डली में एक पापग्रह के स्थित होने के कारण इस जीवन में उन्हें सन्तान का मुख देखने का कोई योग नहीं है . परन्तु बाबा के प्रति तो उनकी अटल श्रद्धा थी. पार्सल मिलने के दो घण्टे पश्चात ही वे पूजनार्थ मस्जिद में आये. उन्हें देख कर बाबा कहने लगे कि लोग आमों के लिये चक्कर काट रहे हैं, परन्तु ये तो दामू के हैं. जिसके हैं, उन्हीं को खाने और मरने दो. इन शब्दों को सुन दामूअण्णा के हृदय पर वज्राघात सा हुआ, परन्तु म्हालसापति (शिरडी के एक भक्त) ने उन्हें समझाया कि इस मृत्यु श्ब्द का अर्थ अहंकार के विनाश से है और बाबा के चरणों की कृपा से तो वह आशीर्वाद स्वरुप है, तब वे आम खाने को तैयार हो गये. इस पर बाबा ने कहा कि वे तुम न खाओ, उन्हें अपनी छोटी स्त्री को खाने दो.

एक बार गोवा के एक मामलतदार ने, जिनका नाम राले था, लगभग 300आमों का एक पार्सल शामा के नाम शिरडी भेजा. पार्सल खोलने पर प्रायः सभी आम अच्छे निकले. भक्तों में इनके वितरण का कार्य शामा को सौंपा गया. उनमें से बाबा ने चार आम दामू अण्णा के लिये पहले निकाल कर रख लिये. दामू अण्णा की तीन स्त्रियां थीं.

इन आमों के प्रभाव से उसे चार पुत्र और चार पुत्रियां उत्पन्न होंगी. यह आज्ञा शिरोधार्य कर उन्होंने वे आम ले जाकर अपनी छोटी स्त्री को दिये. धन्य है साईबाबा की लीला, जिन्होंने भाग्य–विधान पलट कर उन्हें सन्तान–सुख दिया. बाबा की स्वेच्छा से दिये वचन सत्य हुये, ज्योतिषियों के नहीं. बाबा के जीवन काल में उनके शब्दों ने लोगों में अधिक विश्वास और महिमा स्थापित की, परन्तु महान आश्चर्य है कि उनके समाधिस्थ होने कि उपरान्त भी उनका प्रभाव पूर्ववत ही है. बाबा ने कहा कि मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो. यद्यपि मैं देहत्याग भी कर दूंगा, परन्तु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी. केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी, फिरेगी और उन्हें आशा का सन्देश पहुंचाती रहेगी, जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे. निराश न होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा. तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थ ही चिंतित पाओगे. यदि मेरा निरन्तर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा और तुम सदा प्रसन्न रहोगे.

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दु:ख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

स्टिंग ऑपरेशन में केजरीवाल की इरादे

आम आदमी पार्टी में मचा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. अभी तक सुचिता की राजनीति करने वाली और बाकी पार्टियों से अलग राजनीति करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी अब खुद आरोपों के घेरे में है. ऐसे में एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन में हो रहे खुलासों से अरविन्द केजरीवाल के इरादे स्पष्ट नजर आने लगे हैं. प्रशांत भूषण और योगेन्द्र यादव को आम आदमी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का हवाला देकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया दिया गया. लेकिन आप एक और नए विवाद में फंसते हुए नजर आ रही है. केजरीवाल कल तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को स्टिंग करने का प्रवचन देते थे. वह और उनके सहयोगी उन्हीं के पार्टी के बागी नेताओं द्वारा किए स्टिंग का शिकार हो गए. कल तक जो केजरीवाल अपनी पार्टी को इमानदार बतात फिर रहे थे, लेकिन अब आप की सच्चाई देश की जनता के सामने आ चुकी है. जिस उम्मीद पर दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, अब आप की सच्चाई सामने आने के बाद उसकी वो उम्मीद टूट चुकी हैं. अब उस पार्टी की सरकार से कैसी उम्मीद लगाई जा सकती है कि वह जनता की सेवा करेगी, खुद जिस पार्टी में सत्ता के लिए सिर फुट्टवल हो रहा हो.

–मोहित सिन्हा , बेगुसराय, बिहार.

मरता किसान मस्त सरकार

आलेख–किसानों को निराशा हाथ लगी(16 मार्च–22 मार्च 2015) पढ़ा. काफी विचारोत्तेजक आलेख है. यह बिल्कुल सही है कि बजट में किसानों के हाथ निराश लगी है. किसानों को न सस्ते दर पर ब्याज और न ही फसल नुकसान होने पर उनके कर्ज को माफ किया गया. किसानों की आत्महत्या की खबरें प्रतिदिन देश के विभिन्न हिस्सों से आ रही है. यह देश के अन्नदाता(किसानों) के साथ अन्याय है. राज्य सरकारे हों या केन्द्र सरकार सभी किसानों के प्रति उदासीन हैं. केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को किसानों के आत्महत्या को रोकने के लिए जल्द–जल्द से कदम उठाने चाहिए.

–मनोज यादव, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

सबसे ज्यादा लोकप्रिय भारतीय टीम

2011 में भारतीय टीम अपनी जमीन पर विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बनी. भारत ने तब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए फाइनल में श्रीलंका को हराया था. उस विश्व कप के सह–मेजबान श्रीलंका और बांग्लादेश भी थे. ऐसे में सह–मेजबान के तौर पर खिताब जीतने वाला भारत दूसरा देश बना. श्रीलंका ने तब लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी. चार बार की चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया ने 1992 में अपनी धरती पर खिताब न जीत पाने के मलाल को खत्म करते हुए रविवार को मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर हुए आईसीसी विश्व कप–2015 के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को सात विकेट से मात देकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए पांचवीं बार विश्व चैम्पियन बना. आस्ट्रेलिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर अपने घरेलू मैदान पर वर्ल्ड कप–2015 जीतने वाली दुनिया की दूसरी टीम बन गई. साथ ही सह–मेजबान के तौर पर खिताब पर कब्जा जमाने वाली यह तीसरी टीम रही. ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को सात विकेट से हराया. और इसके साथ क्रिकेट का महाकुंभ विश्व कप समाप्त हो गया और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पांचवी बार विश्वकप जीत कर रिकॉर्ड बनाई है. विश्व कप के समापन के साथ ही आइसीसी ने अपनी नई वर्ल्ड टीम का भी ऐलान कर दिया जिसमें दुनिया के गिने–चुने दिग्गजों को ही जगह दी जाती है और हैरानी की बात यह है कि इस बार इस टीम में किसी भी भारतीय को जगह नहीं मिली है.

व्यापम घोटाले की निष्पक्ष जांच हो

मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला चर्चा का विषय बना हुआ है. प्रदेश में इस स्तर का घोटाला वाकई चिंताजनक है. युवाओं के भविष्य को लेकर मुख्यमंत्री की जवाबदेही तो बनती है. मुख्यमंत्री की इस तरह की चुप्पी विपक्ष के स्वर को तेज करती रहेगी. वास्तव में उनके इतने लम्बे कार्यकाल के दौरान यह घोटाला दुर्भाग्यपूर्ण है. ऐसे में सरकार द्वारा स्थिति को देखते हुए कड़े कदम उठाना आवश्यक है. इस घोटाले की सही जांच करायी जाये. अगर शिवराज किसी भी प्रकार से इसमें शामिल नहीं है तो इसकी न्यायिक जांच कराकर, अपनी पारदर्शिता सुनिश्चित करें. व मुख्यमंत्री द्वारा हजारों अपात्र लोगो को नौकरियां मिल जाने की स्वीकारोक्ति के बाद यह चुप्पी चिंताजनक है.

–कार्तिकेय शुक्ला, कानपुर, उत्तर प्रदेश.

निष्पक्ष समाचार पत्र

मैं चौथी दुनिया साप्ताहिक समाचार पत्र का नियमित पाठक हूं. इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी खबरें प्रभावित करने वाली होती हैं. संतोष भारतीय का जब तोप मुकाबिल हो संपादकीय पढ़कर काफी खुशी होती है कि वह हमेशा नए विषयों पर अपने विचार रखते हैं. चौथी दुनिया में प्रकाशित सभी खबरें तथ्यों पर आधारित होती हैं और चौथी दुनिया समाचार पत्र जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठाता है. यह समाचार पत्र सरकारों द्वारा किए गए कई घोटालों को उजागर किया है और इस समाचार पत्र ने फिर एक बार एनटीपीसी के घोटालों को उजागर किया है. आशा है कि चौथी दुनिया समाचार पत्र आगे भी ऐसे ही हिम्मत के साथ लिखता रहेगा.

–पशुपति नाथ तिवारी, बक्सर, बिहार.

लघु कथा

आसमान की सैर

एक तालाब में सारसों का एक जोडा रहता था. धीर–धीरे उनसे उसी तालाब के एक कछुए की दोस्ती हो गयी. कछुए को उनका आसमान में उड़ना बहुत अच्छा लगता था. उनको आसमान में उड़ते देखकर कछुए के मन में भी एक बार आसमान तक पहुंचने की इच्छा हुई. एक दिन कछुए से न रहा गया और उसने अपनी यह इच्छा सारसों को बताई. सारसों ने कहा, दोस्त! आसमान में वही उड़ सकते हैं जिनके पंख होते हैं. तुम्हारे तो पंख हैं नहीं, तुम आसमान में कैसे उड़ सकते हो? कछुआ बेचारा यह सुनकर निराश हो गया, लेकिन उसकी आसमान देखने की इच्छा बढ़ती ही गई और वह एक दिन फिर अपने मित्रों से बोला,मित्रो! जैसे सारस कई दिन तक सोचते रहे कि कछुए को आसमान में कैसे ले जाया जाएं. अंत में उन्हें एक उपाय सूझा. वे बड़े प्रसन्न हुए और कछुए से तुरन्त आकर बोले, आज हमने तुम्हें आसमान की सैर कराने का उपाय सोच लिया. अब तुम जिस दिन चाहो, हम तुम्हें आसमान की सैर करा सकते हैं. हम दोनों एक लकड़ी को अपनी चोंच में दबा लेंगे और तुम उस लकड़ी को अपने मुंह में दबाकर लटक जाना. इस तरह हम तुम्हें लेकर आसमान में उड़ जाएंगे. कछुआ मारे खुशी के उछल पड़ा. अब उसके लिए एक मिनट की देरी असहाय हो रही थी. तुरन्त एक मजबूत लकड़ी ढूंढकर लाई गई और कछुए को लेकर दोनों सारस आसमान में उड़ गए. कछुआ अपने साथ के दूसरे कछुओं की ओर घमंड से देखता हुआ आसमान की सैर करने लगा.

सारस ऊंचे–ऊंचे पेड़ों, नदियों, टीलों के ऊपर उड़ते हुए कछुए को आसमान की सैर कराते रहे. कछुआ अपने भाग्य पर फूला नहीं समा रहा था. उसे आसमान में घूमना बहुत अच्छा लग रहा था. उसकी और ऊपर उड़ने की इच्छा हुई.

सारस ऊंचे–ऊंचे पेड़ों, नदियों, टीलों के ऊपर उड़ते हुए कछुए को आसमान की सैर कराते रहे. कछुआ अपने भाग्य पर फूला नहीं समा रहा था. उसे आसमान में घूमना बहुत अच्छा लग रहा था. उसकी और ऊपर उड़ने की इच्छा हुई. उसने यह कहने के लिए ज्यों ही अपना मुंह खोला कि लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर आ गिरा. जमीन पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए.

इसीलिए हमारे बड़े लोग हमें सदा यह समझाते है कि देखा–देखी करने की इच्छा न करो जो कि तुम्हारी शक्ति से बाहर हो.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर–11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन–201301

बिहार में सरकारी पुरस्कारों का खेल

अनंत विजय

हिंदी में पुरस्कारों की हालत बेहद विवादित रही है. खासकर सरकारी साहित्यिक पुरस्कारों की हालत तो और भी बदतर है. पिछले दिनों बिहार सरकार के राजभाषा पुरस्कारों के ऐलान पर भारी विवाद हुआ है. निर्णायक मंडल की एक सदस्य ने आरोप लगाया है कि एक अफसर ने सूची बनाई और उस पर दस्तखत करने का दबाव डाला गया. निर्णायक मंडल के अध्यक्ष प्रोफेसर नामवर सिंह का एक बयान अख़बारों में छपा है कि उन्होंने तो पुरस्कारों की सूची भी नहीं देखी है. इन विवादों के बीच राजभाषा विभाग के निदेशक का भी एक बयान आया है, जो काफी आपत्तिजनक और हिंदी साहित्य को अपमानित करने वाला है. बिहार राजभाषा विभाग के निदेशक रामविलास पासवान ने कहा है कि हम सभी चयनित लोगों को पत्र भेजेंगे, जिन्हें पुरस्कार लेना होगा, वे लेंगे और जो नहीं लेंगे, उनके लिए हम क्या करें? पुरस्कार नहीं लेंगे, तो पैसा बचेगा ही और वह पैसा जनहित के काम आएगा. अब इस तरह के ग़ैर ज़िम्मेदाराना बयान से राजभाषा विभाग के निदेशक की साहित्य को लेकर समझ को तो समझा ही जा सकता है, साथ ही इससे सरकार की संवेदहीनता भी उजागर होती है. अगर जनहित के काम में ही पैसा लगाना था, तो पुरस्कारों का ऐलान क्यों किया गया?

सबसे बड़ी बात यह है कि राम निरंजन परिमलेंदु को बिहार सरकार के राजभाषा विभाग का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी डॉ. राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान देने का ऐलान हुआ और समाजवादी चिंतक डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे छोटा सम्मान यानी फादर कामिल बुल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई. राम निरंजन परिमलेंदु के साहित्यिक योगदान के बारे में वृहत्तर हिंदी समाज को जानना अभी शेष है, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा को देश ही नहीं, विदेश में भी लोग उनके विचारों की वजह से जानते हैं. पुरस्कार के लिए चयनित सच्चिदानंद सिन्हा ने अपने नाम का ऐलान होने पर आश्चर्य जताते हुए उसे लेने से मना कर दिया. उनका कहना है कि वह साहित्यकार हैं ही नहीं, लिहाजा वह यह पुरस्कार नहीं लेंगे. उधर आलोचक कर्मेंदु शिशिर ने भी पुरस्कार लेने से मना कर बिहार सरकार की सूची संदिग्ध बना दी है. पिछले कुछ सालों से बिहार सरकार ने साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में कई बेहतर काम किए थे. कविता समारोह से लेकर कई अन्य महत्वपूर्ण पहल हुई थीं. हालांकि, यह संस्कृति विभाग की पहल थी. अब जिस तरह से राजभाषा विभाग ने पुरस्कारों का चयन किया, उनका ऐलान किया और उसके बाद सवाल उठने पर निदेशक ने जिस तरह का बयान दिया है, उससे साफ़ जाहिर होता है कि साहित्य बिहार सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, वह तो बस इसे रूटीन सरकारी काम की तरह निबटाना चाहती है.

बिहार सरकार के राजभाषा विभाग के पुरस्कारों और उन पर उठे विवाद को देखेंगे, तो मामला छोटा लग सकता है, लेकिन अगर हम वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में इसका विश्लेषण करें, तो यह कई बड़े सवाल खड़े करता है. बिहार का राजभाषा विभाग मुख्यमंत्री के अधीन आता है. साहित्य एवं संस्कृति को लेकर नीतीश कुमार की छवि एक संजीदा राजनेता की रही है. उनके कार्यकाल या उनके मातहत विभाग में इस तरह का वाकया होना हैरान करने वाली घटना है. कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाने की मजबूरियों के लिए लालू यादव से हाथ मिला लिया, उसी तरह से वह साहित्य एवं संस्कृति को भी चलाना चाह रहे हैं. अगर ऐसा होता है, तो यह नीतीश कुमार की छवि पर विपरीत असर डालेगा ही, सूबे की समृद्ध साहित्यिक विरासत को चोट भी पहुंचाएगा. दरअसल, सत्तर के दशक के बाद से ही सरकारी पुरस्कारों की हालत बद से बदतर होती जा रही है. थोक के भाव से बांटे जाने वाले इन पुरस्कारों का चयन अफसरों की मर्जी से होता है. उन अफसरों की मर्जी से, जिनका साहित्य से कोई लेना-देना नहीं है. कम से कम बिहार राजभाषा विभाग के निदेशक रामविलास पासवान के बयान से तो यही झलकता है. कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी साहित्य एवं संस्कृति के लिए थोक के भाव से पुरस्कार बांटे. इतने लोगों को पुरस्कृत कर दिया गया कि लगा कि जो भी रचेगा, वह पुरस्कृत होने से नहीं बचेगा. बिहार में पचास हज़ार से लेकर तीन लाख रुपये तक की रेवड़ी बंटने का ऐलान हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में पांच लाख से लेकर चालीस-पचास हज़ार रुपये तक के पुरस्कार बंटे.

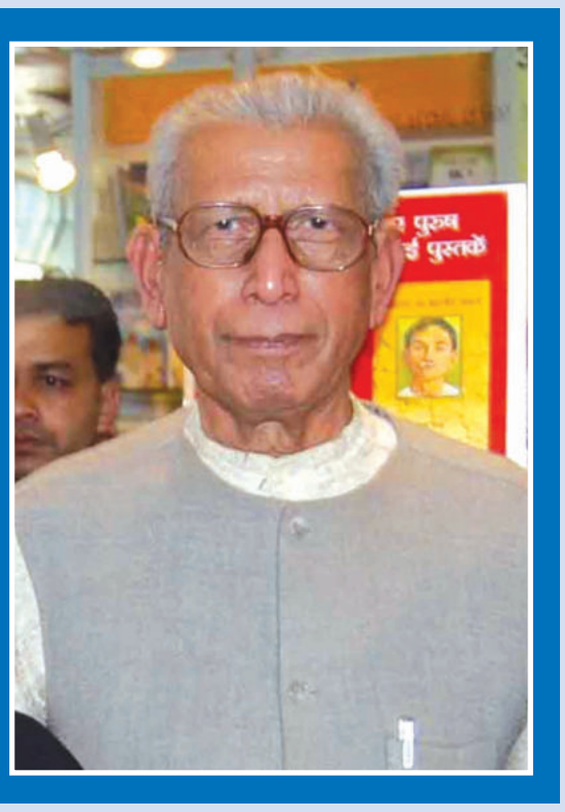

हिंदी में पुरस्कारों को लेकर बहुधा विवाद होते रहे हैं. हिंदी में पुरस्कार पिपासु लेखकों की एक पूरी पौध है. तभी तो हिंदी साहित्य में पुरस्कार देने का खेल लगातार फल-फूल रहा है. पुरस्कारों के इस खेल से निजी संस्थान भी अछूते नहीं रहे हैं. अभी हाल में राजकमल प्रकाशन ने दो पुरस्कार दिए. अगर उनके ही पहले के पुरस्कारों पर नज़र डालेंगे, तो इस बार का चयन संदिग्ध हो जाता है. चूंकि यह निजी संस्थान का पुरस्कार है, लिहाजा इसके कर्ताधर्ताओं पर निर्भर करता है कि वे किसे पुरस्कृत करें. लेकिन, इन वजहों से ही हिंदी में पुरस्कारों की साख नहीं बन पाती है, जबकि पुरस्कार की धनराशि अच्छी-खासी होती है.

सरकारी पुरस्कारों की जुगाड़ सूची में कुछ लेखकों का नाम बार-बार आता है. पुरस्कार लेने का यह कौशल हिंदी की कुछ लेखिकाओं ने भी विकसित किया है. एक अनुमान के मुताबिक, इस वक्त हिंदी में सरकारी पुरस्कारों के अलावा छोटे-बड़े मिलाकर कुल तीन से चार सौ पुरस्कार तो दिए ही जा रहे होंगे. हर राज्य सरकारों के पुरस्कार, फिर वहां की अलग-अलग अकादमियों के पुरस्कार, उसके बाद साहित्यिक संगठनों के पुरस्कार और फिर सबसे अंत में व्यक्तिगत पुरस्कार. इन सबको मिलाकर अगर देखें, तो हिंदी के लेखकों पर पुरस्कारों की बरसात हो रही है. इन पुरस्कारों के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि ये कृतियों पर ही दिए जाएं. कृति है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक. आपके साहित्यिक अवदान पर आपको पुरस्कृत कर दिया जाएगा. हिंदी के वरिष्ठ लेखक हृषिकेश सुलभ ने एक बार साहित्यिक पुरस्कारों के संदर्भ में कुछ बातें कहीं थीं. उनका कहना था कि पुरस्कार देने वाले की मंशा लेखन को सम्मानित करने की हो, तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मंशा पुरस्कार के बहाने खुद यानी आयोजकों का स्वीकृत होना है, तो यह सम्मान के साथ छल है. उन्होंने ऐसा कहकर इशारा किया था कि हिंदी में यह प्रवृत्ति भी इन दिनों जोरों पर है. बड़े लेखकों को सम्मानित करके कुछ संगठन अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की फिराक में लगे रहते हैं. यह स्थिति साहित्य के लिए बेहद चिंताजनक है. उससे भी अधिक चिंताजनक है, वरिष्ठ साहित्यकारों का इस पर खामोश रहना. वरिष्ठ लेखकों की खामोशी से इस तरह के आयोजकों का हौसला बढ़ता है.

हिंदी में पुरस्कारों को लेकर बहुधा विवाद होते रहे हैं. हिंदी में पुरस्कार पिपासु लेखकों की एक पूरी पौध है. तभी तो हिंदी साहित्य में पुरस्कार देने का खेल लगातार फल-फूल रहा है. पुरस्कारों के इस खेल से निजी संस्थान भी अछूते नहीं रहे हैं. अभी हाल में राजकमल प्रकाशन ने दो पुरस्कार दिए. अगर उनके ही पहले के पुरस्कारों पर नज़र डालेंगे, तो इस बार का चयन संदिग्ध हो जाता है. चूंकि यह निजी संस्थान का पुरस्कार है, लिहाजा इसके कर्ताधर्ताओं पर निर्भर करता है कि वे किसे पुरस्कृत करें. लेकिन, इन वजहों से ही हिंदी में पुरस्कारों की साख नहीं बन पाती है, जबकि पुरस्कार की धनराशि अच्छी-खासी होती है. हिंदी में पांच से दस हज़ार रुपये तक के कई पुरस्कार हैं, जो लेखक-लेखिकाओं को अपनी ओर लुभाते हैं. पुरस्कारों के पीछे कई तरह के खेल खेले जाते हैं, जिनसे हिंदी साहित्य जगत बखूबी परिचित है, लेकिन वे खेल खुलकर सामने नहीं आ पाते हैं. कभी-कभार तो यह देखकर बहुत कोफ्त होती है कि हिंदी के लेखक हज़ार-दो हज़ार रुपये के पुरस्कार के लिए तमाम तरह के दंद-फंद करते हैं. हिंदी में पुरस्कारों के कारोबारी इस दंद-फंद का अपने तरीके से फ़ायदा उठाते हैं. यह कहना ग़लत नहीं होगा कि इन्हीं वजहों से पुरस्कारों की महत्ता और प्रतिष्ठा लगातार कम होती जा रही है. हिंदी के कुछ नए लेखकों में पुरस्कृत होने की होड़ भी दिखाई देती है, जो साहित्य के अच्छे भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है.

हिंदी में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार साहित्य अकादमी सम्मान को माना जाता था, लेकिन पिछले एक दशक से जिस तरह से साहित्य अकादमी पुरस्कारों की बंदरबांट हुई है, उससे अकादमी पुरस्कारों की साख पर बट्टा लगा. पिछले एक-दो सालों से इस पुरस्कार की साख वापस लाने की कोशिश हो रही है. वर्ना जब तक साहित्य अकादमी पर विचारधारा विशेष के लोगों का कब्जा था, तब तक वहां जमकर रेवड़ियां बांटी गईं. उसके बाद जब गोपीचंद नारंग अकादमी के अध्यक्ष बने, तब भी हिंदी के पुरस्कारों की सौदेबाजी की बातें सामने आई थीं. वहां तब भी आधार सूची वगैरह बनाने का ड्रामा होता रहा, लेकिन पूरे साहित्य जगत को मालूम हो जाता था कि अमुक वर्ष में किसे पुरस्कार मिलने वाला है. तक़रीबन दो साल पहले लमही सम्मान को लेकर भी शर्मनाक विवाद उठा था. विवाद इतना बढ़ा था कि पुरस्कृत लेखिका ने सम्मान लेने से मना कर दिया था. हिंदी में पुरस्कारों की बहुतायत पर मशहूर कवयित्री कात्यायनी की एक कविता याद आ रही है:-

दो कवि थे/बचे हुए अंत तक/वे भी पुरस्कृत हो गए/इस वर्ष/इस तरह जितने कवि थे/सभी पुरस्कृत हुए/और कविता ने खो दिया/सबका विश्वास.

और, आज चुनौती इसी विश्वास को बचाने की है.■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

विसंगतियों पर प्रहार करता हास्य

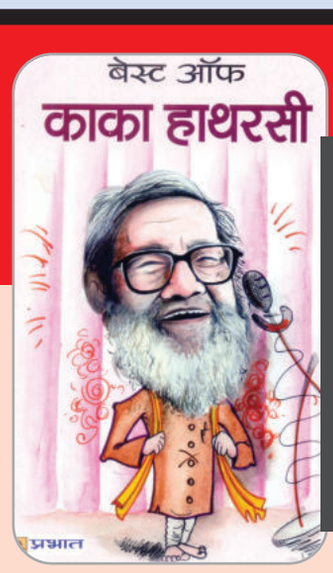

समीक्ष्य कृति
बेस्ट ऑफ काका हाथरसी
रचयिता
काका हाथरसी
प्रकाशक
प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली
मूल्य
150 रुपये

महेंद्र अवधेश

यह सवाल अक्सर उठता रहा है कि व्यंग्य क्या है, हास्य क्या है? व्यंग्य अथवा हास्य की असल परिभाषा क्या है, इसका असल उद्देश्य क्या है? आज से एक साल पहले यानी मार्च, 2014 के अंक में पत्रिका नवनीत ने अपनी आवरण कथा का विषय बनाया था, व्यंग्य इसलिए... इसके अंतर्गत कई जाने-माने व्यंग्यकारों ने अपना दृष्टिकोण पाठकों के सामने रखा था. उन्होंने न केवल हास्य और व्यंग्य का फ़र्क़ बताया, बल्कि यह भी समझाया कि इसका उद्देश्य क्या है, यह कब जन्मता है और इसे लिखने का अधिकार किसे है? वरिष्ठ व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी के शब्दों में, वह दौर कब का जा चुका, जब इस बात का स्यापा पीटा जाता था कि हास्य अथवा व्यंग्य स्पिरिट मात्र है और लोग इसे फालतू ही विधा मनवाने पर आमादा हैं. जैसे कोई आपसे यह पूछ रहा हो कि यार, तू यहां किसलिए? यह जो कविता, कहानी, आलोचना के बामनों की पंगत चल रही थी और बढ़िया ही चल रही थी, सो तू इस पंगत में यहां कैसे? आभिजात्य के ठसकों से भरे विद्वतजनों की इस महफिल में, जहां जीवन के गूढ़ रहस्यों पर गहन विचार-विमर्श हो रहे थे, वहां तू समकालीन समाज की विसंगतियों के कीचड़ में लिथड़े पांव लेकर कहां घुस आया? तू जो अप्रिय प्रश्नों को सीधे पूछने की हिमाकत करता है और जीवन के गूढ़ार्थों में भी सीधे ही घुसता है, तू है कौन?

हास्य अथवा व्यंग्य को लिख कौन सकता है यानी यह अधिकार किसे है? इस महत्वपूर्ण बिंदु पर वरिष्ठ व्यंग्यकार गौतम सान्याल ने बेबाक टिप्पणी की कि जो दलाल हैं, समझौतापरस्त हैं, पराधीन हैं, छलिया हैं, भयग्रस्त हैं तथा व्यवस्था व सत्ता के पिछले दरवाजे के टोहिया हैं, वे इसके हक़दार नहीं हैं. जो विध्वंस में निर्माण नहीं कर सकते, वे व्यंग्यकार नहीं हो सकते. इस विधा पर कलम चलाने का हक़ वे रखते हैं, जिनके हाथ पत्थरों के नीचे दबे होते हैं, जो अपना घर जलाकर मुहल्ले में रोशनी करना चाहते हैं. दुनिया भर के लिए दुआ मांगने वाले, चील जैसी दृष्टि और नीलकंठ जैसी सहनशीलता रखने वाले इसे लिख सकते हैं. और वे लिख सकते हैं, जो सच को सच की तरह देख पाते हों, सुन पाते हों, बोल पाते हों. बकौल गौतम सान्याल, राज्याश्रय हो या धर्माश्रय, हास्य-व्यंग्य आश्रय में कभी नहीं पलता है, वह सत्ता की छांह में कभी नहीं फलता, क्योंकि फल ही नहीं सकता. पिजड़े का पंछी कभी अंडे नहीं देता. अंडों के लिए उन्मुक्त उड़ान और एक घोंसला चाहिए. खुला हुआ आकाश, निर्बाध प्रकृति और बेशुमार आज़ादी चाहिए.

बेस्ट ऑफ काका हाथरसी पर कुछ लिखने से पहले नवनीत की इस आवरण कथा का जिक्र ज़रूरी था, क्योंकि प्रभुलाल गर्ग उर्फ काका हाथरसी ने हास्य को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, हास्य को जन-साधारण की दिक्कतों पर रोशनी डालने का हथियार बनाने के लिए आभिजात्य विद्वतजनों की महफिल से उठने वाली चुनौतियां स्वीकार कीं और उनका मुकाबला किया. काका हाथरसी ने हिंदी कवि सम्मेलन के मंच पर हास्य को स्थापित किया, बल्कि उसे महत्वपूर्ण स्थान भी दिलाया. काका ने तुकांत एवं अतुकांत कविताओं के माध्यम से अपने हास्य में जीवन की व्यापक विसंगतियों को समेटा. उन्होंने नारी को गरिमा प्रदान की. नाम बड़े और दर्शन छोटे, लिंग भेद जैसी कविताएं उनकी गहरी निरीक्षण क्षमता और खोजपूर्ण दृष्टि की परिचायक हैं. प्रस्तुत संकलन में उनकी वे कविताएं हैं, जो काव्य प्रेमियों के हृदय-पटल पर राज करती आई हैं और हमें बताती हैं कि निर्मल हास्य द्वारा समाज में कैसे सुधार किया जा सकता है. देश को आज़ादी तो मिली, लेकिन अव्यवस्था-मनमानी ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा. देखिए यह रचना:-

सच्चे स्वतंत्रता सेनानी ताम्रपत्र को चाट रहे हैं,
जाली सर्टिफिकेट बनाकर चमचे चांदी काट रहे हैं.
डनलप के गद्दों पर कोई फुटपाथों पर सोरिया,
गणपति बप्पा मोरिया...

राजनीति का चेहरा विकृत हो चुका है, नेताओं का आचरण देखकर काका हाथरसी का कवि मन कह उठता है:-

दर्पण रखकर सामने अपना रूप निहार,
होकर खड़े चुनाव में, करो देश उद्धार.
करो देश उद्धार, जोड़ गुंडों से नाता,
जिनकी सूरत देख कांप जाए मतदाता.
कह काका कविराय जो निंदा करते नहीं अघाएं,
वही विरोधी तुम्हें वोट देने को आएं.

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की हालत पर भी काका के कवि मन ने अपने हास्य की तलवार कुछ इस तरह चलाई:-

न्याय प्राप्त करने गए न्यायालय के द्वार,
इसी जगह सबसे अधिक पाया भ्रष्टाचार.
पाया भ्रष्टाचार, मिसल को मसल रहे हैं,
ईंट-ईंट से रिश्वत के स्वर निकल रहे हैं.
कह काका, जब पेशकार जी घर को आए,
तनुखा से भी तिगुने नोट दबाकर लाए.

****

फ्लीडर, मुंशी, मुहर्रिर सब निचोड़ लें अर्क,
सायल को घायल करे, फाइल वाला क्लर्क.
फाइल वाला क्लर्क, अगर कुछ बच जाएगा,
वह चपरासी के इनाम में पच जाएगा.
कह काका, जो जीत गया सो हारा समझो,
हार गया, सो पत्थर से दे मारा समझो.

दरअसल, किसी भी रचना की सार्थकता यही है कि वह असल बात को धारदार तरीके से सबके सामने रखे. काका हाथरसी ने अपनी हर रचना को देश और समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए आकार दिया. दुलत्ती, काका के कारतूस, काका के प्रहसन, काकदूत, काका की फुलझड़ियां, काका के कहकहे, महामूर्ख सम्मेलन, काका की काकटेल, चकल्लस, काकाकोला, हंसगुल्ले, काका के धड़ाके, कह काका कविराय, फिल्मी सरकार, जय बोलो बेईमान की, नोकझोंक काका-काकी की, काका-काकी के लवलैटर्स, हसंत-बसंत, योगा एंड भोगा, काका की चौपाल, यार सप्तक, काका का दरबार, काका तरंग, काका शतक, मेरा जीवन: ए-वन, मीठी-मीठी हंसाइयां एवं खिलखिलाहट आदि काका हाथरसी के रचना संसार की वे अमर कृतियां हैं, जो हिंदी के पाठकों को निरंतर ऊर्जा देती रहेंगी. नया संकलन बेस्ट ऑफ काका हाथरसी को भी हास्य के प्रेमी हाथोंहाथ लेंगे, ऐसी आशा है.■

mahendra.awdhesh@gmail.com

माइक्रोसॉफ्ट के कॉरपोरेट वाइस प्रेसीडेंट कर्क कोनिसबॉउर ने कहा कि 10 इंच से बड़े आकार के टैबलेट प्रोफेशन टैबलेट नहीं होते. माइक्रोसॉफ्ट 10.1 इंच या उससे कम आकार के उपकरण को असली मोबाइल उपकरण मानता है. उसके लिए ही कंपनी ऑफिस मुफ्त देगी. उसके ऊपर के उपकरणों के लिए पैसे देने होंगे.

सबसे सस्ता डुअल सिम लुमिया स्मार्टफोन

माइक्रोसॉफ्ट एक नया स्मार्टफोन लुमिया 430 लॉन्च करेगी. यह लुमिया सीरीज का सबसे सस्ता डुअल सिम स्मार्टफोन होगा. यह कंपनी द्वारा पिछले साल पेश किए गए लुमिया 435 से भी सस्ता होगा. इस फोन का डिजाइन पहले वाले लुमिया फोन से थोड़ा अलग है लेकिन इसके अन्य फीचर्स पहले वालों जैसे ही हैं. यह विंडोज 8.1 आधारित फोन है और इसे विंडोज 10 में अपग्रेड किया जा सकता है. इसमें 2एमपी का फिक्स्ड कैमरा है लेकिन इसमें फ्लैश नहीं है. इस फोन की स्क्रीन 4 इंच का एलसीडी डिस्पले है जो 800 गुणा 480 पिक्सल का रेजोल्यूशन देती है. इसका प्रोसेसर 1.2 गीगाहर्ट्ज डुअल कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 200 प्रोसेसर है. इसमें 1 जीबी रैम है. माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 8जीबी इंटरनल मेमोरी बढ़ा सकते हैं. अन्य फीचर्स: 3जी, वाई-फाई 802.11, ब्लूटुथ 4.0, जीपीएस, जैसी सुविधाएं इसमें उपलब्ध है. इसकी बटरी 1500 एमएएच की है. इसकी कीमत 4,380 रुपये है. ■

हुआवेई का होनर 6 प्लस और होनर 4एक्स

हुआवेई ने आधिकारिक तौर पर दो नए आकर्षक 4जी स्मार्टफोन-होनर6प्लस और होनर 4एक्स पेश करने का एलान किया है. इसे ऑनलाइन पार्टनर फ्लिपकार्ट डॉट कॉम के जरिए खासतौर से बेचा जाएगा. होनर स्मार्ट फोन का लोकार्पण युवाओं में लोकप्रिय अर्जन कपूर ने किया. इस मौके पर होनर के प्रेसिडेंट श्री जॉर्ज झाओ और हुआवेई इंडिया के प्रेसिडेंट, कंज्यूमर बिजनेस ग्रुप श्री ऐलेन वैंग भी मौजूद थे. होनर 6प्लस बायोनिक समानांतर दोहरे लेंस वाला भारत का पहला स्मार्टफोन होगा, इसमें 3 जीबी रैम के साथ 1.8गीगाहर्ट्ज ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और यह अपनी 3600 एमएएच बैट्री से 2.81 दिन बैट्री स्टैंडबाई देता है. होनर 4 एक्स में एकक्वाल कॉमस्नैप ड्रैगन 410 एमएसएम 8916 1.2 गीगाहर्ट्ज क्वैडकोर प्रोसेसर है और अपनी 3000 एमएएच बैट्री से 72 घंटे के बैट्री बैकअप देता है. ■

बजाज की नई पल्सर आरएस200

बजाज ने अपनी बहुप्रतीक्षित बाइक पल्सर आरएस 200 भारत में लॉन्च किया है. पल्सर आरएस 200 की कीमत 1.18 लाख रुपये तय की गई है. पल्सर आरएस200 एबीएस और नॉन एबीएस दो वेरिएंट में उपलब्ध होगी. एबीएस (anti-lock braking system) वेरिएंट की कीमत 1.30 लाख रुपये है. कंपनी ने कहा कि उसकी योजना प्रतिमाह पल्सर आरएस-200 की 2,500 इकाइयां बेचने की है. बजाज की इस पहली फुल फेयर्ड बाइक में पल्सर 200 एनएस वाला 199.5 सीसी. 4वॉल्व, 6स्पीड ट्रांसमिशन वाला इंजन दिया जा रहा है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन और ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो 23.52पीएस पावर और 18.6 एनएम टार्क जनरेट करता है. नई बजाज पल्सर आरएस 200 में पल्सर 220 की तरह ही फ्रंट काउल पर रियर व्यू मिरर दिए गए हैं. इसके अलावा स्पिलिट सीट, 10 स्पॉक अलॉय व्हील, मस्क्युलिन फ्यूल टैंक दिया गया है. एंट्री लेवल फेयर्ड बाइक में बजाज पल्सर 200एसएस का मुकाबला यामाहा आर15, हीरो करिज्मा जेडएमआर और केटीएम आरसी 200 जैसी बाइक से होगा. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

एलजी का नया बजट स्मार्टफोन

एलजी का एक नया स्मार्टफोन स्पिरिट पेश किया है. जो लोग 15 हजार रुपये से कम कीमत का फोन लेना चाहते हैं, यह उन लोगों को पसंद आएगा. यह स्मार्टफोन 4.7 इंच का है, जो 1280 गुणा 720 पिक्सल का रेजोल्यूशन देता है और इसमें इन सेल टच डिस्पले है. इसका प्रोसेसर 1.3 जीएचेजड क्वॉड कोर प्रोसेसर है और इसका रियर कैमरा 8 एमपी का है, जबकि फ्रंट 1एमपी का है. यह फोन एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप पर आधारित है. यह कर्व डिजाइन का फोन है. रैम की बात करें तो इसमें 1जीबी रैम है और 8जीबी तक इंटरनल स्टोरेज तक बढ़ाया जा सकता है. इसमें अन्य फीचर 3जी, वाईफाई 802.11, ब्लूटुथ 4.0, जीपीएस की सुविधा उपलब्ध है. इसमें 2100 एमएएच की बैटरी है. इस फोन की कीमत 14,250 रुपये है. ■

माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मुफ्त मिलेगा

माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस लोगों को अब मुफ्त मिलेगा. कंपनी ने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 इंच आकार से छोटे उपकरणों के लिए मुफ्त में मिलेगा. इसका मतलब हुआ कि तमाम तरह के मोबाइल फोन, टैबलेट और छोटे स्क्रीन वाले कंप्यूटरों के लिए यह मुफ्त होगा. माइक्रोसॉफ्ट के कॉरपोरेट वाइस प्रेसीडेंट कर्क कोनिसबॉउर ने कहा कि 10 इंच से बड़े आकार के टैबलेट प्रोफेशन टैबलेट नहीं होते. माइक्रोसॉफ्ट 10.1 इंच या उससे कम आकार के उपकरण को असली मोबाइल उपकरण मानता है. उसके लिए ही कंपनी ऑफिस मुफ्त देगी. उसके ऊपर के उपकरणों के लिए पैसे देने होंगे. माइक्रोसॉफ्ट के इस ऑफिस से यूजर नए डाक्यूमेंट बना सकता है, एडिट कर सकता है और उन्हें देख भी सकता है. इसके साथ वह और भी कई तरह के काम कर सकता है. ■

बीएमडब्ल्यू ने भारत में उतारी मिनी कूपर एस

बीएमडब्ल्यू ने अपनी मिनी ब्रांड की नई कार मिनी कूपर एस को भारतीय कार बाजार में लॉन्च किया है. मिनी कूपर का यह नया वेरिएंट काफी पावरफुल है और केवल 3 डोर लाइनअप के साथ उपलब्ध है. यह कार देश में सीबीयू (कम्प्लीट्ली बिल्ड यूनिट) के जरिए आएगी. गौरतलब है कि पिछले साल मिनी कूपर को डीजल इंजन के साथ तीन और पांच डोर में पहले ही उतार चुकी है. मिनी कूपर एस पूरी तरह बीएमडब्ल्यू के यूकेएल फ्रंट व्हील-ड्राइव प्लेटफोर्म पर बेस्ड है. इस कार में स्टैंडर्ड स्टाइलिश 16 इंच विक्ट्री स्पोक सिल्वर तथा ब्लैक अलॉय व्हील और बड़ा ब्लैक सनरूफ दिया गया है, साथ ही ऑप्शनल फीचर में 17 इंच कोसमो स्पोक लाइटवेट अलॉय व्हील भी मौजूद हैं.

इंजन की बात करें तो कूपर एस में 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर, ट्विनटर्बो पेट्रोल इंजन लगा है जो 189बीएचपी का पावर और 280एनएम टॉर्क जेनरेट करता है. इसका ट्विनटर्बो इंजन 6 स्पीड ऑटोमेटिक स्टेपट्रॉनिक गियरबॉक्स के साथ है जो फ्रंट व्हील पर पावर डिलीवर करते हैं. कार की टॉप स्पीड 233 किमी प्रति घंटा है और यह 0-100 किमी की स्पीड तक केवल 6.7 सेकेंड में पहुंच सकती है. सेफ्टी फीचर्स में ड्राइवर और को-पेसेंजर एयरबैग, ब्रेक असिस्ट, क्रेश सेंसर्स और ब्रेक कंट्रोल शामिल किए गए हैं. इसकी कीमत 34.65 लाख रुपये है. ■

पोर्टेबल वायरलेस फोन, देगा वाई-फाई हॉटस्पॉट

अगर आप अभी भी ऑफिस और घर के लिए लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करते हैं तो टाटा डोकोमो ने एक नया वायरलेस पोर्टेबल लैंडलाइन फोन लाया है. ये पोर्टेबल डिवाइस टाटा फोटोन वॉकी के नाम से लॉन्च किया गया है. इस लैंडलाइन पोर्टेबल डिवाइस की सबसे खास बात ये है कि इसमें पोर्टेबल वाई-फाई हॉटस्पॉट दिया गया है. फोटोन वॉकी की मदद से और 5 डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है. आसान शब्दों में कहें तो ये लैंडलाइन फोन आपके इंटरनेट कनेक्टर या मॉडम की तरह काम करेगा. टाटा फोटोन वॉकी एक अच्छा डिवाइस है जो लैंडलाइन कॉल्स को अटेंड करने के साथ-साथ इंटरनेट सर्फ करने और बाकी डिवाइसेस को वाई-फाई हॉटस्पॉट देने का काम करता है.

हॉटस्पॉट क्या होता है -

वाई-फाई हॉटस्पॉट एक ऐसा फीचर होता है जिसके जरिए एक डिवाइस अपने इंटरनेट कनेक्शन को बाकी डिवाइसेस में वाई-फाई सिग्नल की मदद से भेज सकता है. ऐसे में अगर किसी एक डिवाइस में इंटरनेट है तो एक या एक से ज्यादा डिवाइसेस उससे कनेक्ट हो सकेंगे. लुक्स और डिजाइन के हिसाब से टाटा फोटोन वाकी किसी भी हॉल या कॉन्फ्रेंस रूम में लैंडलाइन और वाई-फाई सर्विसेज देने के लिए एक अच्छा डिवाइस लगता है. अलग-अलग डिवाइसेस में नेट पैक डलवाने से अच्छा एक ऐसा डिवाइस जिससे एक कनेक्शन पर सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें बहुत अच्छा और किफायती साबित हो सकता है. टाटा फोटोन वाकी की कीमत 2099 रुपये है. इसके साथ टाटा का मंथली टैरिफ प्लान 499 रुपये में आएगा जिसमें 3जीबी डाटा और 300 लोकल और एसटीडी मिनट मिलेंगे. इसके अलावा, एक प्लान 999 रुपये का भी है जिसमें 8जीबी डाटा और 1000 एसटीडी मिनट्स पोस्ट पेड यूजर्स को फ्री मिलेंगे. इसके अलावा, भी कई प्लान हैं जिन्हें यूजर्स अपने हिसाब से ले सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया

क्रिकेट का चक्रवर्ती सम्राट

विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जहां ऑस्ट्रेलिया ने अपना विययी परचम न लहराया हो. एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका से होते हुए उनका विजय रथ अपने ही वतन पर आ पहुंचा है. ऑस्ट्रेलियाई टीम क्रिकेट में सफलता का पर्याय बन गई है. मेन इन यलो का विश्व खिताब से ऐसा लगाव है कि वे इस खिताब से बहुत दिनों तक दूर नहीं रह सकते. यह बात इससे साबित होती है कि साल 1996 से 2015 के दरम्यान खेले गए छह विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया पांच बार फाइनल में पहुंचा और चार बार विश्व चैंपियन बना. जिस तरह टेनिस में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करना एक उपलब्धि होती है उसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया के सभी महाद्धीपों में विजय ध्वज फहराकर एक नया इतिहास रचकर क्रिकेट का चक्रवर्ती सम्राट बन गया है.

नवीन चौहान

जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने ऐतिहासिक एमसीजी मैदान पर विजयी चौका लगाया. वैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने पांचवीं बार विश्वकप पर कब्जा कर लिया. सातवीं बार विश्वकप के फाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलियाई टीम पांचवीं बार विश्व विजेता बनी और पांचों महाद्वीप में विजयी परचम लहराने का अनोखा कारनामा कर दिखाया है. छह बार विश्वकप के सेमीफाइनल में पहुंची कीवी टीम सफलता की उड़ान नहीं भर सकी और एकतरफा फाइनल मुक़ाबले में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के सामने धराशायी हो गई और ऑस्ट्रेलिया सात विकेट से जीत हासिल की. जिस आक्रामक अंदाज में न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को मात दी थी. उसी वजह से खिताबी भिड़ंत के रोचक होने के कयास लगाये जा रहे थे. ऐसा इसलिए भी था क्योंकि लीग चरण में दोनों टीमों के बीच भिड़ंत हुई थी. वह मुकाबला बेहद रोमांचक रहा था. उस मैच में न्यूजीलैंड को एक विकेट से जीत हासिल हुई थी. लेकिन दोनों टीमों के बीच हुई खिताबी भिडंत पूरी एक तरफा रही. ऑस्ट्रेलिया ने पूरे मैच में कीवी टीम को उबरने का कोई मौका नहीं दिया.

ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिताबी जीत से एक बात तो साफ हो गई है कि अगले चार पांच साल क्रिकेट के मैदान में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बना रहेगा. इस युवा ऑस्ट्रेलियाई टीम की आक्रमण पंक्ति में से मिशेल जॉनसन को छोड़ दें तो बाकी गेंदबाजों की उम्र पच्चीस साल से कम है. मिचेल स्टार्क(25), जोश हेजलवुड(24), जेम्स फॉक्नर(24), पेट कमिन्स(21) और जेम्स पेटिंनसन(24) स्टीव स्मिथ(25) साल के हैं वहीं डेविड वॉनर(28), एरोन फिंच(28), ग्लैन मैक्सवेल(26) जैसे बल्लेबाजों के अंतरराष्ट्रीय करियर का प्रारंभिक दौर है. करियर के शुरुआती दौर में ही विश्व चैंपियन बनने से उनके प्रदर्शन में निश्चित तौर सुधार आएगा और ये सभी मिलकर टीम के प्रदर्शन और ऊंचाई पर ले जायेंगे. इस युवा टीम ने जिस तरह की क्रिकेट विश्व कप में खेली, वह ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट खेलने का पारंपरिक तरीका है. मैदान पर हर चुनौती का मुस्तैदी से सामना करना स्टीव सहित टीम के सभी युवा खिलाड़ियों में भी नज़र आता है. स्टीव उसी आक्रामक एटीट्यूड का प्रतिनिधित्व करते हैं.

माइकल क्लार्क के एकदिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ के हांथों में सौंपे जाने की पूरी संभावना है. पिछले कुछ समय में उन्होंने जिस तरह बल्लेबाजी संभाली है, और टीम की रीढ़ बनकर उभरे हैं. ऐसे में आने वाले समय में उनका सितारा बुलंदियों पर नजर आएगा. स्टीव विश्वकप सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप टेन बल्लेबाजों सूची में जगह पाने वाले वह अकेले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं. अगले चार–पांच सालों में वह दुनिया के सबसे उम्दा बल्लेबाज के रूप में उभरकर सामने आयेंगे.

विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की जीत की इबारत उनके बायें हाथ के तेज गेंदबाजों की तिगड़ी जानसन (3/30), फॉकनर (3/36) और स्टार्क (2/20) ने लिखी. फाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 45 ओवर में मजह 183 रन बनाकर पवेलियन लौट गई. कीवी टीम ने आखिरी सात विकेट 33 रन पर गंवा दिये. न्यूजीलैंड के लिये सेमीफाइनल के हीरो रहे ग्रांट एलियट ने 82 गेंदों पर 83 रन की पारी खेली लेकिन अपनी टीम को सम्मान जनक स्कोर तक नहीं पहुंचा सके. ऑस्ट्रेलिया ने विजयी लक्ष्य 16 ओवर शेष रहते तीन विकेट के नुक्सान पर हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया के पास एक बार फिर विश्व विजेता बनने के लिए बड़ा लक्ष्य नहीं था. हालांकि उसकी शुरुआत भी अच्छी नहीं रही, फिंच बहुत जल्दी आउट हो गए. बावजूद इसके ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी दबाव में नहीं आये. करियर का आखिरी एकदिवसीय मैच खेल रहे कप्तान माइकल क्लार्क ने 74 और युवा बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने नाबाद 56 रनों की नाबाद पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को पांचवीं बार विश्व क्रिकेट के शिखर पर पहुंचा दिया. क्लार्क और स्मिथ ने तीसरे विकेट के लिये 112 रन की साझेदारी की और ऑस्ट्रेलिया की जीत सुनिश्चित कर दी.

भले ही ऑस्ट्रेलिया ने विश्वकप जीत लिया हो लेकिन न्यूजीलैंड का विश्व कप कई मायनों में जरूरी था. तकरीबन 40 लाख की आबादी वाले इस देश में क्रिकेट की पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही है. वहां लोग रग्बी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं और युवा पीढ़ी भी रग्बी की ओर रुख कर रही है. ब्रैंडन मैक्लम ने विश्व कप में जिस तरह टीम की कमान संभाली और टीम को एक भी मैच गंवाए बगैर फाइनल तक पहुंचाया वह काबिले तारीफ था. उन्होंने सामने से टीम को लीड किया, इस वजह से न्यूजीलैंड ने बहुत आक्रामक क्रिकेट खेली. सेमी–फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को जिस अंदाज में मात थी वह काबिले तारीफ था. सारा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था. ऐसे नज़ारे का इंतजार न्यूजीलैंड के लोग लंबे समय से कर रहे थे. लोग चाहते थे कि विश्व चैंपियन का ताज कीवी टीम सिर पर सजे. लेकिन कुछ चीजें न्यूजीलैंड के खिलाफ चली गईं. पहली यह कि न्यूजीलैंड ने फाइनल से पहले सभी मैच अपनी धरती पर खेले. यह उनके लिए भारी पड़ गया. एक तरफ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैदानों के आकार में फर्क था वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों में गेंदबाजी के लिए परिस्थितियां अलग थीं. एक तरफ जहां न्यूजीलैंड में सीमिंग कंडीशन और विकेट थे. इसी वजह से पूरे विश्व कप के दौरान कहर बरपाने वाले कीवी गेंदबाज फाइनल मुकाबले में बेअसर हो गए और उसी पिच पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड पर कहर ढा दिया. पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई. कीवी टीम को संभलने का एक मौका मिला लेकिन फॉक्नर ने उन्हें ऐसे झटके दिये कि कीवी बल्लेबाज दोबारा उबर नहीं पाए.

विश्वकप इतिहास में यह तीसरा मौका है जब विश्वकप के फाइनल में कोई टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए विश्व विजेता बनी है. सबसे पहले वर्ष 1996 में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह कारनामा किया था. पिछले विश्वकप में भी भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ लक्ष्य पीछा करके विश्व चैंपियन बनी थी. लेकिन पांचवी बार विश्व चैंपियन बन चुकी ऑस्ट्रेलियाई लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी बार विश्व विजेता बनी है. इसके साथ ही अपनी ही सरजमीं पर विश्व विजेता बनने का कारनामा दूसरी बार हुआ है. भारत 2011 में अपनी सरजमीं पर विश्व कप जीतने वाला पहला देश बना था. ऑस्ट्रेलिया को चमचमाती ट्रॉफी के अलावा 39 लाख 75 हजार डॉलर का राशि पुरस्कार स्वरूप मिली जबकि उपविजेता न्यूजीलैंड को 17 लाख 50 हजार डॉलर की राशि से संतोष करना पड़ा.

1983 के विश्वकप में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 183 रन के स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव करके विश्व चैंपियन बनी थी लेकिन न्यूजीलैंड इस इतिहास को दोहरा नहीं पाई. भले ही न्यूजीलैंड की टीम विश्वविजेता बनने में नाकामयाब रही हो. लेकिन कीवी टीम ने जो एग्रेसिव एप्रोच दिखाई, उसके बल पर वह अपनी अमिट छाप छोड़ने में कामयाब रही. इसी राह पर चलकर न्यूजीलैंड क्रिकेट एक बार फिर धमाकेदार वापसी करने में कामयाब होगी.■

navinonline2003@gmail.com

सभी महाद्धीपों में विश्वकप जीतने का अनोखा रिकॉर्ड

इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया सभी महाद्धीपों में विश्वकप जीतने वाला पहला देश भी बन गया. 1987 में ऑस्ट्रेलिया ने एशिया(भारत–पाकिस्तान), 1999 में यूरोप(इंग्लैंड), 2003 में आफ्रीका(दक्षिण अफ्रीका), 2007 में वेस्टइंडीज(अमेरिका) की धरती पर विश्व विजेता बन चुका है. यह अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है. पिछले पांच विश्वकप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने जगह बनाई और चार बार वह विजेता बनी. 2011 के विश्व कप के दौरान वह क्वार्टर फाइनल तक पहुंच चुकी. ग्लैन मैग्रा, शेन वार्न, मैथ्यू हेडेन जैसे खिलाड़ियों के संन्यास लेने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम उनके उत्तराधिकारियों की तलाश में जुटी थी. परिवर्तन के इस दौर में भी ऑस्ट्रेलिया ने बेहतर प्रदर्शन किया और एक बार फिर विश्व खिताब पर कब्जा कर लिया.

आईसीसी विश्व कप–2015 टीम

आईसीसी की ड्रीम टीम में इस बार किसी भी भारतीय खिलाड़ी को जगह नहीं मिली. टीम में न्यूजीलैंड के पांच, ऑस्ट्रेलिया के चार, दक्षिण अफ्रीका के दो ,श्रीलंका, जिंबाब्वे के एक-एक खिलाड़ी को जगह दी गई है. न्यूजीलैंड के ब्रैंडन मैक्कलम को टीम का कप्तान घोषित किया गया है.

मार्टिन गप्टिल (न्यूजीलैंड)
ब्रैंडन मैक्कलम (न्यूजीलैंड) (कप्तान)
कुमार संगाकार (श्रीलंका) (विकेटकीपर)
स्टीवन स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)
एबी डिवीलियर्स (साउथ अफ्रीका)
ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया)
कोरी एंडरसन (न्यूजीलैंड)
डेनियल विटोरी (न्यूजीलैंड)
मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)
ट्रेंट बोल्ट (न्यूजीलैंड)
मोर्ने मॉर्कल (दक्षिण अफ्रीका)
ब्रैंडन टेलर (जिम्बाब्वे) (12वां खिलाड़ी)

मिशेल स्टार्क बने मैन ऑफ द सीरीज

बल्लेबाजी के नए–नए कीर्तिमान इस विश्वकप में बने लेकिन विश्वकप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एक गेंदबाज बना है. ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को आठ मैचों में 22 विकेट लेने के लिए आईसीसी क्रिकेट विश्वकप का प्लेयर ऑफ द टूर्नमेंट घोषित किया गया. कॉमेंट्रेटर्स के पैनल ने एक मत से 25 वर्षीय स्टार्क को इस पुरस्कार के लिए चुना. पूरे विश्व कप में उनकी शानदार गेंदबाजी की वजह से ऑस्ट्रेलिया पांचवीं बार विश्व चैंपियन बनने में सफल रहा. बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 10.18 की औसत से 22 विकेट लिए. उनका इकॉनमी रेट 3.50 रन रहा. प्रतियोगिता में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में किया था, उन्होंने उस लो स्कोरिंग मैच में 28 रन देकर छह विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया को जीत के मुहाने तक ले गए थे. कीवी तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने भी नौ मैचों में 22 विकेट लिए. इस पुरस्कार की दौड़ में न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मैक्कलम, ट्रेंट बोल्ट,मार्टिन गुप्टिल और श्रीलंका के कुमार संगकारा भी शामिल थे. लेकिन चयन समिति ने स्टार्क को सबसे बेहतर पाया. विश्वकप के ब्रांड ऐंबेस्डर सचिन तेंदुलकर ने उन्हें मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार से नवाजा. वर्ष 1992 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुए विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार की शुरुआत की गई थी.

विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज बनने वाले खिलाड़ी

1992	–	मार्टीन क्रो(न्यूजीलैंड)
1996	–	सनथ जयसूर्या(श्रीलंका)
1999	–	लांस क्लूजनर(दक्षिण अफ्रीका)
2003	–	सचिन तेंदुलकर(भारत)
2007	–	ग्लैन मैग्रा(ऑस्ट्रेलिया)
2011	–	युवराज सिंह(भारत)
2015	–	मिचेल स्टार्क(ऑस्ट्रेलिया)

मैन ऑफ द मैच

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जेम्स फॉकनर ने मैच में 36 रन देकर तीन विकेट लेकर न्यूजीलैंड के मध्यम क्रम को धराशायी कर दिया. 150 रनों पर तीन विकेट पर पहुंची कीवी टीम को लगातार दो झटके दिये और उनकी कमर तोड़ दी. इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम वापसी नहीं कर सकी और 183 रनों पर ढेर हो गई. यदि रॉस टेलर और ग्रांट एलिएट के बीच हुई साझेदारी को सही समय पर नहीं तोड़ते तो मैच का परिणाम कुछ और होता.

1975	क्लाइव लॉयड (वेस्टइंडीज)
1979	विवियन रिचर्डस (वेस्टइंडीज)
1983	मोहिंदर अमरनाथ (भारत)
1987	डेविड बून(ऑस्ट्रेलिया)
1992	वसीम अकरम (पाकिस्तान)
1996	अरविंद डिसिलवा(श्रीलंका)
1999	शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया)
2003	रिकी पॉन्टिंग (ऑस्ट्रेलिया)
2007	एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया)
2011	महेंद्र सिंह धोनी(भारत)
2015	जेम्स फॉक्नर (ऑस्ट्रेलिया)

विश्वकप के टॉप फाइव बल्लेबाज

खिलाड़ी	रन
मार्टीन गप्टिल	547
कुमार संगकार	541
एबी डिविलिर्स	482
ब्रेंडन टेलर	433
शिखर धनवन	412

विश्वकप के टॉप फाइव गेंदबाज

मिचेल स्टार्क	22
ट्रेंट बोल्ट	22
उमेश यादव	18
मोर्नी मोर्कल	17
मोहम्मद शमी	17
जेरोम टेलर	17

...क्या है दीपिका की मर्जी?

मेरा शरीर, मेरा दिमाग, मेरी पसंद. मैं वही कपड़े पहनती हूं जो पहनना चाहती हूं, लेकिन मेरी आत्मा पर कपड़ों की कोई बंदिश नहीं है. ये मेरी मर्जी है कि मैं साइज जीरो रहूं या साइज फिफ्टीन. उनके पास मेरी आत्मा का कोई आकार नहीं है और कभी होगा भी नहीं. मेरी आत्मा को बांधकर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ब्रम्हांड का विस्तार रोक सकते हो या सूरज की रोशनी को अपनी हथेलियों में कैद कर सकते हो. तुम्हारा मन कैद में है उसे मुक्त करो, मेरा शरीर नहीं.

दीपिका पादुकोण एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इसका कारण वोग मैग्जीन द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गई एक शॉर्ट फिल्म है. यह फिल्म सोशल मीडिया में वायरल हो रही है. पहले तीन दिन में यू-ट्यूब पर इस वीडियो को 35 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा था. इस फिल्म का निर्देशन कॉकेटेल और फाइंडिंग फेनी जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले होमी अदजानिया ने किया है. अमिताभ बच्चन से लेकर आलिया भट्ट तक बॉलीवुड की जानी-मानी हस्तियों ने इस पहल का स्वागत किया है और इसकी जमकर तारीफ की है. इस फिल्म में एक नारी की आजादी की कहानी, उसकी ख्वाहिशें, उसकी इच्छाएं, उसकी शर्तों को दीपिका दुनिया के सामने एक और अलग रंग में लेकर आई हैं. इस फिल्म को ब्लैक और व्हाइट टोन में इसलिए शूट किया गया है क्योंकि बंदिशों भरी जिंदगी में कोई रंग नहीं होते हैं. 99 महिलाओं को लेकर इस फिल्म को शूट किया गया है और यह संदेश देने की कोशिश की गई है महिलाओं की भी अपनी जिंदगी है और उसे अपनी शर्तों पर जीना उनका हक है. दरअसल इस वीडियो में 99 अलग अलग लड़कियों और महिलाओं की जिंदगी के कई पहलुओं को दिखाया गया है. इस फिल्म में दीपिका के अलावा जोया अख्तर, निमरत कौर, अधुना अख्तर और निर्देशक होमी अदजानिया की पत्नि अनाइता श्रॉफ अदजानिया भी हैं. इस वीडियो ने महिलाओं की आजादी के विषय को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है इस वीडियो में दीपिका कहती हैं कि

मेरा शरीर, मेरा दिमाग, मेरी पसंद. मैं वही कपड़े पहनती हूं जो पहनना चाहती हूं, लेकिन मेरी आत्मा पर कपड़ों की कोई बंदिश नहीं है. ये मेरी मर्जी है कि मैं साइज जीरो रहूं या साइज फिफ्टीन. उनके पास मेरी आत्मा का कोई आकार नहीं है और कभी होगा भी नहीं. मेरी आत्मा को बांधकर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ब्रम्हांड का विस्तार रोक सकते हो या सूरज की रोशनी को अपनी हथेलियों में कैद कर सकते हो. तुम्हारा मन कैद में है उसे मुक्त करो, मेरा शरीर नहीं. उसे आजाद रहने दो. मेरी मर्जी है कि मैं शादी करूं या नहीं, शादी के पहले सेक्स करूं या शादी के बाद. सेक्स करूं या नहीं. ये मेरी मर्जी है कि मैं किसी से कुछ पल के लिए प्यार करूं या हमेशा वासना में रहूं. ये मेरी मर्जी है कि मैं किसी आदमी से प्यार करूं या औरत से या फिर दोनों से. याद रखो तुम मेरी पसंद हो मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूं. मेरे माथे की बिंदी, मेरी उंगली की अंगूठी, मेरे अपने नाम के साथ तुम्हारा सरनेम जोड़ना, ये सब सजावटी चीजें हैं, इन्हें बदला जा सकता है लेकिन तुम्हारे लिये मेरे प्यार को नहीं, इसे सहेजो. मैंने ऐसा करना पसंद किया क्योंकि इससे मैं जुड़ाव महसूस करती थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी धारणा इससे अलग हो. ये मेरी मर्जी है मैं जब चाहूं घर लौटूं. परेशान मत होना यदि मैं सुबह चार बजे घर लौटकर आऊं. अगर मैं शाम को छह बजे घर आ जाऊं तो ज्यादा खुश भी मत होना. ये मेरी मर्जी है.

मेरी मर्जी है कि मैं तुम्हार बच्चा पैदा करूंया नहीं. सात अरब लोगों में से तुम्हें चुनूं या नहीं. इसलिए फंसना नहीं. मेरी खुशी तुम्हारे लिए दर्द हो सकती है. मेरा गाना तुम्हारे लिए शोर हो सकता है. मेरा ढंग तुम्हें अराजकता लग सकता है, तुम्हारे पाप मुझे पुण्य लग सकते हैं. मेरी पसंद मेरी उंगलियों के निशान की तरह हैं जो मुझे दुनिया में अलग पहचान दिलाती है. मैं जंगल की तराई हूं. मैं बर्फ का टुकड़ा हूं बर्फबरी नहीं. जागो पुराने रिवाजों से बाहर निकलो, मुझे लोगों जैसा बनने को कहा गया लेकिन मैंने अलग बनना पसंद किया. मैं ब्रम्हांड हूं, हर दिशा में अनंत हूं. यह मेरी पसंद है.

इस वीडियो को देखकर आलिया भट्ट ने ट्वीट किया कि, अब इस मुद्दे को लोगों को सच में गंभीरता से लेना शुरू कर देना चाहिए. वहीं महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर कहा कि होमी अदजानिया ने 2 मिनट की मुद्दे से जुड़ी फिल्म बनाई है. विमन इंपावरमेंट..!! वहीं निर्माता निर्देशक करण जौहर ने कहा कि प्रेरणा देने लायक, असरदार और उपयुक्त. वेल डन गर्ल गैंग!!!

दीपिका को पहले ही बिंदास अभिनेत्रियों में शुमार किया जाता है वह महिलाओं के मुद्दे पर बेवाक राय देने से नहीं चूकती हैं. वह क्लीवेज विवाद पर भी बड़ी सख्ती से पेश आई थीं. उस समय भी उन्हें बॉलीवुड सहित हर वर्ग का साथ मिला था. इस बार भी लोगों को वीडियो पर आपत्ति है लेकिन समाज का यह कटु सत्य है. जिस पर खुलकर बात की जानी चाहिए.■

शाहिद की मीरा!

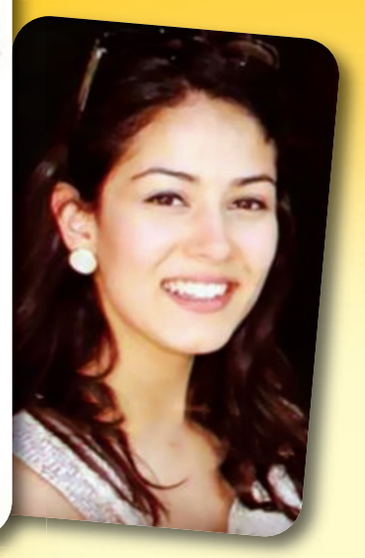

शाहिद ने कहा था कि वह एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जिसका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से ना हो. शाहिद ने ऐसा ही किया और गुपचुप तरीके से दिल्ली की कुड़ी मीरा से सगाई कर ली.

बॉलीवुड के चॉकलेटी और रोमांटिक-एक्शन हीरो शाहिद कपूर इस साल शादी के बंधन में बंध जाएंगे. जी, हां खबर है कि शाहिद कपूर दिल्ली की कुड़ी मीरा राजपूत से दिसंबर से शादी करेंगे. खबर आई है कि शाहिद और मीरा की सगाई मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को हुई थी. शाहिद कपूर के अपने कई को-स्टार के साथ अफेयर की खबरें आती रही हैं, समय-समय पर उनके रिश्ते के किस्से चर्चा में आते रहे तो उनमें प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, विद्या बालन, अमृता राव और सोनाक्षी सिन्हा के नाम शामिल हैं. लेकिन अपनी शादी की खबरों पर कुछ दिनों पहले शाहिद ने कहा था कि वह एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जिसका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से ना हो. शाहिद ने ऐसा ही किया और गुपचुप तरीके से दिल्ली की कुड़ी मीरा से सगाई कर ली. शाहिद का कहना है फिल्म जगत से बाहर की लड़की से शादी करके वह जिंदगी को एक नए नजरिए से देख पाएंगे. मीरा दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स कर रही हैं. शाहिद की मंगेतर मीरा इस खबर के मीडिया में आने के बाद अपनी प्राइवेसी का ख्याल रख रही हैं. मीरा ने अपनी सगाई की खबर सिर्फ कुछ करीबी दोस्तों को दी थी और उसके बाद से ही ये खबर बन गई. मीरा का बॉलीवुड से कोई कनेक्शन नहीं है इसलिए उन्होंने अपने करीबियों से शादी को लेकर चुप रहने के लिए कहा है. शाहिद के मुताबिक दिसंबर में उनकी शादी होने वाली है. मीरा ने अपनी स्कूलिंग बसंत वैली स्कूल से की है. माना जा रहा है कि शाहिद और मीरा धार्मिक संगठन राधा स्वामी सत्संग व्यास के जरिए मिले थे. शाहिद कपूर और उनके पिता पंकज कपूर राधा स्वामी सत्संग को बहुत मानते हैं.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

खतरा मोल ले रहे हैं आमिर!

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी फिल्मों के कैरेक्टर में ढल जाने के लिए जाने जाते हैं. अपनी आगामी फिल्म दंगल के उनके किरदार में ढलने की एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि इस फिल्म में अपने किरदार को एक भारी भरकम लुक देने के लिए आमिर अपनी हेल्थ को खतरे में डाल रहे हैं. आमिर इस फिल्म में 55 साल के रेसलर की भूमिका निभाने जा रहे हैं और इसके लिए वे कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं. एक फिल्मी वेबसाइट में हेल्थ एक्सपर्ट अर्नव सरकार ने कहा है कि वजन कम या ज्यादा होने के लिए बॉडी को ढलने में थोड़ा वक्त लगता है, ऐसे में आमिर अपनी हेल्थ के साथ बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं. वजन बढ़ाने के लिए उनकी यह जल्दबाजी उनके स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर डाल सकती है. उन्होंने कहा कि कम समय में 3 से 4 किलो तक वजन का बढ़ना बिना स्टेरॉइड के भी संभव है, लेकिन इससे ज्यादा वजन जैसे 10 किलो या इससे भी ज्यादा इतनी जल्दी बढ़े तो यह स्टेरॉइड के इस्तेमाल की ओर साफ-साफ इशारा करती है. एक्सपर्ट की मानें तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल स्किन प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं के साथ-साथ मौत को भी आमंत्रण दे सकता है. लेकिन, आमिर हर बार की तरह अपने को किरदार के तराशने के लिए जी जान से लगे हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें इसके लिए अपनी हेल्थ की भी परवाह नहीं है.■

हरफनमौला पूनम

कहते हैं अगर आप में टैलेंट है तो सफलता आप तक खुद चलकर आती है. अभिनेत्री पूनम पांडे पर यह बात पूरी तरह सच साबित होती है. फिल्म ट्रिप टू भानगढ़ से शुरू हुआ उनका फ़िल्मी सफ़र जहां फिल्म युवा की रिलीज से रफ़्तार पकड़ेगा, वहीं कलर्स चैनल के लोकप्रिय शो मेरी आशिकी तुम से ही में भी उन्हें देखा जा सकता है. आज की तारीख में टीवी और फिल्मों का कद लगभग एक सा हो गया है. टीवी पर बिग बी अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार और सलमान खान तक सभी काम कर रहे हैं. लिहाजा इसे पूनम का हुनर ही कहा जायगा कि वह एक टीवी और फिल्म दोनों में काम कर रही हैं. पिछले दिनों उनकी सलमान खान के साथ सोशल साइट पर शेयर की गयी तस्वीर काफी लोकप्रिय हुई थी जो बजरंगी भाइ जान के सेट पर खींची गई थी. हरफनमौला पूनम के टैलेंट को देखकर लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब वह सलमान खान जैसे सितारे के साथ नजर आयेंगी. कीप इट अप पूनम.■

एनएच-10 का बाद एनएच-12

नवदीप सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म एनएच 10 की सफलता के बाद इसके निर्माता रोड जॉनर को भुनाने की सोच रहे हैं. वे एनएच को रोड सीरीज के तौर पर विकसित करना चाहते हैं. इसी सीरीज की अगली फिल्म एनएच-12 होगी. फिल्म की निर्माता कंपनी फैंटम फिल्म्स के मधु मंटेना ने कहा है, हम फिल्म को मिली प्रतिक्रिया से बेहद उत्साहित हैं और अब इसे आगे ले जाने को तैयार हैं. हमारी रोड फिल्मों की सीरीज की दूसरी फिल्म एनएच- 12 होगी. यह फिल्म अगले कुछ वर्षों में प्रदर्शित होगी. एनएच-10 की तरह यह फिल्म भी एक नई डार्क थीम पर आधारित होगी. एनएच-10 ऑनर किलिंग पर थी. अगली फिल्म का विषय क्या होगा इसका निर्णय नहीं हुआ है. अब तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि अनुष्का इस फिल्म में अभिनय करेंगी या नहीं? भारत में इससे पहले रोड फिल्मों की फ्रैंचाइज स्थापित नहीं हुई है. ऐसा हॉलीवुड में होता रहा है.■

मोम की कैटरीना

बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री कैटरीना कैफ का मोम का पुतला लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में स्थापित किया गया है. गैलरी में दुनिया की जानी मानी हस्तियों के साथ शामिल होने वाली कैटरीना बॉलीवुड की सातवीं शख्सियत हैं जिनकी मोम की प्रतिमा यहां लगाई गई है. इससे पहले अमिताभ बच्चन(2000), ऐश्वर्या रॉय(2004), शाहरुख खान(2007), सलमान खान(2008), रितिक रोशन(2011), माधुरी दीक्षित(2012) की मूर्ति इस म्यूजियम में रखी जा चुकी है. कैटरीना की इस खूबसूरत मूर्ति को 20 शिल्पियों की एक टीम ने चार महीने की मेहनत से गढ़ा है. इस मोम के बुत को बनाने में डेढ़ लाख पाउंड का खर्च आया है. कैटरीना ने स्वयं इस पुतले का अनावरण किया. कैफ ने अपने पुतले को देखकर कहा कि यह वाकई में अद्भुत है. यह बिलकुल मेरी तरह दिखती है. इसकी खूबसूरती को देखकर और लोग भी हैरत में पड़ गए और कहा कि यह कला का बेहतरीन नमूना है. कैटरीना, मैडम तुसाद के कलाकारों के साथ लगातार जुड़ी हुई थीं. उनकी इच्छा थी कि पुतले में किसी तरह की कमी न रह जाए. सोनाक्षी ने कटरीना को इसके लिए बधाई दी और कहा कि वे आशा करती हैं कि भविष्य में उनकी मूर्ति भी वहां होगी. सोनाक्षी ने कहा कि मुझे कटरीना का स्टेच्यू बेहद आकर्षक लगा. यह किसी भी उस कलाकार के लिए बड़ी बात है, जो कई साल से इंडस्ट्री में टिका हुआ है. लंबे समय तक काम करने के बाद ही ऐसे मौके आते हैं. मैं कटरीना के लिए खुश हूं कि उनका पुतला वहां पहुंचा और मैं उम्मीद करती हूं कि मेरा भी स्टेच्यू एक दिन वहां जरूर होगा.■

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

13 अप्रैल –19 अप्रैल 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

महाविलय से डरी भाजपा

अब तक बिहार की लड़ाई को आसान समझ रही भाजपा के लिए प्रस्तावित महाविलय एक भारी संकट लेकर आने वाला है. इसलिए भाजपा अभी से ही जुट गई है कि कैसे इस संकट से निपटा जाए. कहीं भाजपा इस संभावित संकट से निपटने के लिए अपने मौजूदा सहयोगी लोजपा और रालोसपा का कद छोटा न कर दे.

सरोज सिंह

जनता परिवार के प्रस्तावित महाविलय को लेकर बिहार की राजनीति में भारी उथल-पुथल मची हुई है. भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल कुछ दिनों पहले तक यह मान कर चल रहे थे कि किसी भी कीमत पर जनता परिवार का महाविलय नहीं होगा. लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की पार्टियों का एक-दूसरे में विलय होगा, इस बात पर एनडीए के नेताओं की लगभग यही राय थी कि किसी हाल में ऐसा होना संभव नहीं है. लोजपा नेता रामविलास पासवान ऐसी राय तो कई मंचों पर जता चुके हैं कि मर्जर नहीं होगा बल्कि इसमें जुड़ी पार्टियां जर्जर हो जाएंगी. लेकिन हाल के दिनों में महाविलय को लेकर हालात बदले हैं. विशेषकर नीतीश कुमार के सत्ता में वापस आने के बाद सूबे में सुशासन की गाड़ी एक बार फिर पटरी पर दिखनी शुरू हो गई है. नौकरशाहों को साफ संदेश दे दिया गया है कि सुस्ती छोड़कर काम को समयसीमा के अंदर पूरा करने का काम करें.

नीतीश कुमार के इन कदमों से सरकार और पार्टी दोनों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है. इधर चौथी दुनिया के चुनावी सर्वे के बाद तो राजनीतिक गलियारे में हड़कंप ही मच गया. नीतीश कुमार की भारी बढ़त देखकर न केवल राजद के लोग बल्कि भाजपा और उसके सहयोगी दल के नेता सकते में हैं. बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद के एप्रोच में आए बदलाव को इस सर्वे ने काफी प्रभावित किया है. महाविलय की गाड़ी अगर इतनी तेजी से बढ़ी है तो इसमें सर्वे ने बहुत ही महती भूमिका निभाई है. राजद खेमे को लग रहा है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता और लालू प्रसाद का मजबूत वोट बैंक बिहार में नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने में कामयाब होगा. महाविलय की औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है और लगता है इस माह किसी भी दिन जनता परिवार के महाविलय का ऐलान हो सकता है. राजद के वैसे नेता जो अब तक महाविलय की संभावनाओं को खारिज कर रहे थे, वैसे नेता अब इसे समय की सबसे बड़ी मांग बता रहे हैं. जानकार बताते हैं कि महाविलय से जुड़ी सभी बाधाओं को दूर कर दिया गया है और जल्द ही इसके संबंध में महाऐलान होगा. उधर इस संभावित राजनीतिक महाविलय की संभावना ने भाजपा और उसके सहयोगी दलों की नींद उड़ा दी है. एनडीए के रणनीतिकार यह अच्छी तरह समझ रहे हैं कि लालू और नीतीश की मिली-जुली ताकत चुनावी लिहाज से एक बड़ी चुनौती है. अगर महाविलय के बाद कांग्रेस ने भी तालमेल कर साथ दिया तो फिर इस गठबंधन की ताकत और भी कई गुना बढ़ जाएगी क्योंकि ऐसे में मुस्लिम वोटों का बिखराव पूरी तरह खत्म हो जाएगा और इसका पूरा फायदा महागठबंधन को मिलेगा. गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों के बिखराव का फायदा एनडीए गठबंधन को मिला था क्योंकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा राजद, जदयू और कांग्रेस के बीच हो गया था. इसके अलावा पिछड़ा और अतिपिछड़ा वोटों में भी सेंधमारी हो गई थी जिसका लाभ भाजपा को मिला. लेकिन महाविलय और कांग्रेस के साथ तालमेल के हालात में राजनीतिक तस्वीर विधानसभा चुनावों में कुछ और ही होगी. भाजपा के रणनीतिकार इस राजनीतिक सच्चाई को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं. इसलिए इस संभावित महाविलय को लेकर बेहद परेशान हैं. भाजपा के थिंकटैंक अभी तक यह मान कर चल रहे थे कि लोकसभा चुनाव की तरह ही वोटों के बिखराव का लाभ वह उठा लेंगे. भाजपा इस बात को लेकर भी इत्मिनान में थी कि जदयू और राजद का विलय होते ही यादव वोट का एक बड़ा हिस्सा लालू के ख़िलाफ हो जाएगा क्योंकि यादव बिरादरी नीतीश कुमार के नाम पर अपना वोट देने को तैयार नहीं होगी. अगर यह हुआ तो यादव वोटों का बिखराव भाजपा के लिए अमृत का काम करेगा और भाजपा बिहार का चुनावी महासंग्राम आसानी से जीत लेगी. इसके अलावा नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और लालू प्रसाद की नकारात्मक छवि का लाभ एनडीए को मिल जाएगा. लेकिन सूबे के बदलते घटनाक्रम ने भाजपा को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है. कल तक जीतनरा मांझी से परदे के पीछे गोल मोल बात करने वाली भाजपा अब खुले मंच से कह रही है कि वह जीतनराम के साथ तालमेल को तैयार है. जानकार बताते हैं कि भाजपा नेताओं की राय पहले यह थी कि जीतनराम के अलग लड़ने से ही भाजपा को फायदा होगा क्योंकि वह जदयू का वोट ही काटेंगे लेकिन जीतनराम की प्रमंडलीय रैली ने भाजपा के कान खड़े कर दिए. जीतनराम की उस रैली में महादलितों के अलावा अन्य जातियों के भी लोग शामिल हुए थे. जीतनराम की रैलियों को मिल रहे रिस्पांस को देखते हुए भाजपा ने अपनी रणनीति बदलने की सोची है. भाजपा के रणनीतिकारों ने जो हिसाब लगाया जिसका नतीजा यह निकला कि जीतनराम अगर अलग चुनाव लड़ते हैं तो वह जदयू को कम और भाजपा को कहीं ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा दें. भाजपा नेताओं के लिए इस समय एक भ्रम की स्थिति यह बन गई है कि वे लगातार इस बात को मान रहे हैं कि जीतनराम के पास वोटरों का एक बड़ा तबका जा रहा है. लेकिन सच्चाई इससे उलट है. दरअसल जीतनराम कुछ भी हो हल्ला मचाकर भले कुछ भीड़ इकट्ठा कर पाने में कामयाब हो जा रहे हों लेकिन इस भीड़ को वोट में तब्दील कर पाना उनके लिए दूर की कौड़ी साबित हो सकता है. इसका कारण यह है कि कुछ दिनों पहले चौथी दुनिया के ही सर्वे में यह बात निकलकर आई थी कि वोटरों का एक बड़ा तबका नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होते देखना चाहता है. दरअसल जीतनराम के लगातार उल-जुलूल बयान देते रहने से भी लोग उन्हें सुनने जाते हैं. एक और महत्वपूर्ण बात चौथी दुनिया के उस सर्वे में सामने आई थी कि मांझी सरकार के कार्यकाल को 24 लोग ही ठीक मानते हैं जबकि 58 प्रतिशत का मानना था कि उनका कार्यकाल बुरा था. लेकिन भाजपा इसे जीतनराम की बढ़ती हुई लोकप्रियता मान रही है और इसे कैश कराने के चक्कर में लगी हुई है. ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और राजीव रंजन इस प्रकिया में सेतु का काम कर रहे हैं. मांझी खेमा भी इस बदली हुई परिस्थति का पूरा फायदा उठाना चाह रहा है. जीतनराम मांझी साफ साफ कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी से चुनाव से पहले कोई तालमेल नहीं होगा. लेकिन मांझी गुट के जानकार सूत्र बताते हैं कि अभी उनका पूरा ध्यान 20 अप्रैल की गांधी मैदान की रैली पर है. अगर रैली सफल रही तो इसी हैसियत के साथ भाजपा के साथ सीटों के तालमेल पर विचार किया जाएगा. हो सकता है कि प्रस्ताव 80 से 90 सीटों का हो. लेकिन अगर रैली औसत रही तो फिर 30 से 40 सीटों के बीच भी भाजपा के साथ तालमेल किया जा सकता है. भाजपा की ओर से तालमेल के प्रस्ताव को मांझी गुट ने अपनी पहली सफलता माना है. यह गुट महसूस कर रहा है कि अगर एकजुट होकर राजनीतिक कार्यक्रम जारी रखा जाए तो चुनावी फायदा मिलना तय है. फिलहाल सारी ताकत गांधी मैदान की रैली के लिए लगाई जा रही है क्योंकि इस रैली पर भाजपा सहित दूसरे सभी दलों की नज़र है.

भाजपा भले ही जीतनराम के साथ तालमेल करना चाहती है लेकिन वह अभी सीटों के बंटवारे को लेकर संशय में है. अब तक बिहार की लड़ाई को आसान समझ रही भाजपा के लिए प्रस्तावित महाविलय एक भारी संकट लेकर आने वाला है. इसलिए भाजपा अभी से ही लगी है कि कैसे इस संकट से निपटा जाए. कहीं भाजपा इस संभावित संकट के निपटने के लिए अपने मौजूदा सहयोगी लोजपा और रालोसपा का कद छोटा न कर दे. इसी भ्रम की स्थिति में वह मांझी का कद भी जनता के बीच ज्यादा आंक रही है और यह सोच रही है कि जीतनराम के सहारे चुनाव जीता जा सकता है.■

नीतीश कुमार की भारी बढ़त देखकर न केवल राजद के लोग बल्कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेता सकते में हैं. बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद के एप्रोच में आए बदलाव को इस सर्वे ने काफी प्रभावित किया है. महाविलय की गाड़ी अगर इतनी तेजी से बढ़ी है तो इसमें सर्वे ने बहुत ही महती भूमिका निभाई है.राजद खेमे को लग रहा है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता और लालू प्रसाद का मजबूत वोट बैंक बिहार में नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने में कामयाब होगा.

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

एक नज़र

सम्राट अशोक जयंती मनी

सम्राट अशोक फाउंडेशन के तत्वावधान में महासम्राट अशोक की 2359 वीं जयंती पटना के गौतमबुद्ध बिहार दारोगा राय पथ में मनाई गई. जयंती समारोह की अध्यक्षता सम्राट अशोक फाउंडेशन के निदेशक निरंजन कुशवाहा पप्पू ने की. जबकि मंच संचालन नागमणि कुशवाहा ने किया. जयंती समारोह का उद्घाटन माननीय मंत्री अवधेश कुशवाहा नगर विकास एवं निबंधन विभाग ने किया. उन्होंने सम्राट अशोक के जीवन से प्रेरणा लेकर बौद्ध धर्म को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया. मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद कुशवाहा ने सभा को संबोधित किया. सभा को पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा, पूर्व मंत्री बसावन प्रसाद भगत, पूर्व मंत्री देवनाथ प्रसाद कुशवाहा, किसान आयोग के अध्यक्ष सी.पी.सिन्हा, आचार्य मुन्ना प्रसाद, मुकेश कुमार, उमेद सिंह गौतम, चन्द्रिका सिंह, अजित कुमार ललन, प्रज्ञा दीप, प्रेम शंकर पासवान, ब्रज किशोर सिंह कुशवाहा, जेप दोहरे सेवा निवृ डीजीपी डीएन सिंह आजाद, कैलाश पासवान, रोहनभगत, नीरज सिंह कुशवाहा के अलावा कई अन्य गणमान्य लोगों ने संबोधित किया. समारोह में अशोक सम्राट के नाम पर कई प्रस्ताव पारित हुए.

शिक्षकों की आवाज हुई बुलंद

पटना के आर. ब्लॉक चौराहे पर बिहार पंचायत-नगर पंचायत शिक्षक संघ के तत्वावधान में चल रहे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन-सह-धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वामी सहजानन्द सरस्वती सामाजिक न्याय मंच के अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार को समान काम के लिए समान वेतन (वेतनमान) नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानान्तरण, स्नातक पास सभा नियोजित शिक्षकों का स्नातक ग्रेड में समायोजन तथा आन्दोलन के दौरान शिक्षकों पर दर्ज सभी मुकदमों को सरकार वापस लेना चाहिए. बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. जिस तरह शिक्षकों के आन्दोलन के कारण जदयू सरकार को पूर्व में नुकसान हुआ है, उसी प्रकार आगे भी नुकसान हो सकता है. सरकार को चाहिए कि वह शिक्षकों का ख्याल करे. आमरण अनुशन सह धरना कार्यक्रम में शिक्षक संघ के अध्यक्ष पूरण कुमार एवं महासचिव केशव कुमार भी उपस्थित रहे और अध्यक्ष रोहित कुमर से बात की. मंच के तरफ से प्रभात बटालियन,मंजीत पासवान, रविन्द्र यादव भी उपस्थित रहे.■

– 'भारती'

मसूढ़ो का ध्यान रखना जरूरी
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
डॉ कुमार दीपक
दंत चिकित्सक,गोगरी खगड़िया
दांतों का ध्यान देना जरूरी है लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है दांतो को मजबूती देने वाले मसूढ़ों का ध्यान रखना क्योंकि यही वजह जिससे आज के दौर में जेंजेवाइटिस (पायरिया) के मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती जा रही है। इन बातों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाया खगड़िया गोगरी जमालपुर के अनुभवी दन्त चिकित्सक डॉ. कुमार दीपक ने। पायरिया के लक्षणों में मसूढ़ों से खून आना मूंह से बदबू का आना तथा दांतों का खराब होना शामिल है। इससे बचने के लिए डॉक्टर साहब का सलाह है कि – छः महीने में एक बार अपने दांतों के चिकित्सक से सफाई कराया करें तथा दांतों का इस्तेमाल करें अर्थात खूब चबायें और खायें-खाना तो है ही साथ ही गाजर, सेब, मूली, गन्ना, आदि। बच्चों के लिए उन्होंने बताया कि बच्चों को दो बार ब्रशिंग जरूर करायें। तथा उन्हें चॉकलेट, बिस्कूट, पाव रोट आदि खिलाने के बाद कुल्ला या ब्रशिंग अवश्य करायें। चूंकि इसे अनुवांशिक रोग भी माना जाता है इसलिए जिनको यह है वह अपने बच्चों का ख्याल ज्यादा रखें। पीजा, बर्गर आदि कम खिलायें तथा फल फ्रुट अधिक दें। डॉ. कुमार ने पायरिया मरीजों के लिए नुस्खा भी बताया –उन्हें ऑयल की कूल्ली करायें जैसे नारियल तेल, तिल का तेल, जैतून के तेल को मुंह में पांच मिनट रख कर ऑयल मुंह के चारो ओर घुमाएं तथा कुल्ला करें, दिन में तीन बार करें, काफी फायदा दिखेगा। साथ ही मसूढ़ों और दांतों की समस्या को इग्नोर न करते हुए डॉक्टर से अवश्य मिलें। ■ चित्रा भारती
AROFIT Protin Powder
Protein granules enriched with Vitamn, Minerals & Carbohydrates
Levokon Tab
Levofloxacin 500 mg
The powerfull quinolone with superior efficacy
ARILINE Cap.
Acebrophylline 100 mg
MUSTAL Tab.
Montelukast Sodium 10 mg+ Levocetirizine HCL 5 mg
ONDANOK DROP
Ondanesetron 2 mg
NOKSIRA
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE MOULDED FURNITURE
WINNER OF NATIONAL AWARD
1 YEAR GUARANTY
Contact : 9386595926, 9334115955

पूर्णिया

कैसे हो महिलाओं का विकास

नीरज सिंह

जहां केन्द्र से लेकर राज्य की सरकारों द्वारा सरकारी नौकरियों एवं राजनीति में महिला आरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है वहीं पूर्णिया में महिलाओं को छोटे मोटे कारोबार करने छोटे-छोटे कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए अपेक्षित सहयोग और साथ नहीं मिल रहा है. वहीं यहां की महिलाएं निजी नॉन बैंकिंग कंपनी, चिटफंड कम्पनियों आदि से लोन लेकर छोटे-मोटे कारोबार के द्वारा अपने और अपने परिवार का गुजर बसर कर रही हैं. मालूम हो कि उद्योग विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बूटीक सिलाई-कढ़ाई, पापड़, मसाला उद्योग, फिनायल, गुलाब जल तैयार करन राइस मिल, मूढ़ी मिल समेत छोटे मोटे अनेकों उद्योग लगाने के लिए बैंक के माध्यम से 50 हजार रुपये से लेकर 25 लाख तक सब्सिडी युक्त लोन देने की व्यवस्था की गई है. यह सब्सिडी जहां नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए 25 प्रतिशत है वहीं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए 35 प्रतिशत की व्यवस्था सरकार के तरफ से की गई है. लेकिन पूर्णिया की वर्तमान हालत यह है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उद्योग विभाग की तरफ से समुचित लाभ नहीं मिल पा रही है.

इस संबंध में नॉन बैंकिग कम्पनी द्वारा पूर्णिया सिटी में आयोजित सप्ताहिक मीटिंग के दौरान दर्जनों महिलाओं ने जो जानकारी दी वह सरकार की इस योजना का पोल खोलने के लिए काफी है. यहां उपस्थित महिला उद्यमी सह समाजसेवी नीलम जयसवाल का कहना था कि विगत 8 साल से मैं नॉन बैंकिंग कम्पनी से महंगे ब्याज दर पर लोन लेकर फिनायल, गुलाबजल क्लीनर तैयार करने का धंधा कर रही हूं और अपने 10 सदस्यों के परिवार का पेट भर रही हूं लेकिन पूंजी के अभाव में मेरा यह कारोबार दम तोड़ रहा है जबकि पति भी मेरे साथ इसी काम में लगे रहते हैं. आज तक मुझे सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक ने कोई मदद नहीं की है और ना ही उद्योग विभाग की तरफ से कोई सरकारी योजना का लाभ मिला है जबकि मदद का गुहार लेकर उद्योग विभाग का भी दरवाजा खटकखटा चुकी हूं. बूटीक की कारोबार करने वाली पिंकी कश्यप का कहना था कि निजी नॉन बैंकिंग कम्पनी से ऋण लेकर ब्यूटी पार्लर का कारोबार शुरू किया लेकिन महंगे ब्याज दर के कारण कमाई का आधा से अधिक हिस्सा ब्याज चुकाने में ही चला जाता है. मुझे ना तो उद्योग विभाग की मदद मिली न तो बैंक ऋण देने के लिए तैयार है. मंजू केडिया का कहना था कि मुझे परचून की दुकान के लिए नॉन बैंकिग कम्पनी से ऋण लेनी पड़ी है महंगे ब्याज दर के चलते मानसिक तनाव में रहती हू. बैंक से और ना ही उद्योग विभाग की तरफ से कोई मदद मिल रही है. मंजू देवी का कहना था कि सिलाई-कढ़ाई के कारोबार को लेकर नॉन बैंकिंग कम्पनी से मदद लेनी पड़ी.

जानकारी के अनुसार पूर्णिया सिटी की लगभग सैकड़ों महिलाएं प्रत्येक सोमवार को नॉन बैंकिंग कम्पनी के बैनर तले साप्ताहिक मीटिंग करती है और कम्पनी को ब्याज आदि की राशि चुकाती है. जब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और महिलाओं की समस्याओं को लेकर पूर्णिया स्थित उद्योग विभाग से सम्पर्क किया गया तो यहां के उद्योग विस्तार पदाधिकारी गयाचन्द सिंह ने जो जानकारी दी इसके अनुसार केन्द्र सरकार की तरफ से प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी युक्त लोन मिलती है जिसके अन्तर्गत सिलाई, पापड़, बूटीक, राइस मिल, चूड़ा मिल, मूढ़ी मिल, पैकेज ड्रिकींग वाटर जैसे अनेकों कारोबार के लिए सब्सिडी युक्त लोन मिलता है. सब्सिडी युक्त लोन के अन्तर्गत 50 हजार से 25 लाख रुपये तक की राशि दी जाती है. उद्योग विभाग खासकर महिला उद्यमियों को मदद करने के लिए तत्पर रहती है. अभी हाल ही में उद्योग विभाग ने धमदाहा की पूनम जायसवाल को लावर मिल के लिए 25 लाख की सब्सिडी लोन दी है. पूर्णिया में महिलाओं को कारोबार का प्रशिक्षण सह सब्सिडी युक्त लोन की व्यवस्था की जा रही है जिसके तहत भारतीय स्टेट बैंक के आंचलिक कार्यालय परिसर में यहां की तीन महिलाएं रोजगार का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है. उद्योग विभाग से अगर कोई महिला उद्यमी संपर्क करती है तो उद्योग विभाग महिला उद्यमी को हर संभव मदद करने को तत्पर है.■

feedback@chauthiduniya.com

अन्य ख़बरें

युवा संसद कार्यक्रम आयोजित

मोतिहारी, नेहरू युवा केन्द्र मोतिहारी के तत्वावधान में घोड़ासहन प्रखंड के समनपुर पंचायत भवन में प्रखंड स्तरीय राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम योजना के तहत पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया.कार्यक्रम का उद्घाटन एड्स काउन्सलर उमेश कुमार सिंह ने दीप प्रज्जवलित कर किया.इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि इस तरह के आयोजन से युवाओं के बीच इच्छा शक्ति बढ़ती है और इनके अन्दर दबी प्रतिभाएं बाहर आती हैं. मौके पर डॉ. रामनरेश प्रसाद, दीपक सिंह कश्यप, मुखिया रामजन्म पासवान, महिला पर्यवेक्षिका बबिता कुमारी आदि इपस्थित थे. कार्यक्रम का संचालन अरुण कुमार आर्य ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन धीरेन्द्र कुमार ने किया.

सर्वांगीण विकास हमारी प्राथमिकता

देवघर नगर निगम में शामिल 44 गांवों वाले क्षेत्र का सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है, कारण कि नगर निगम के गठन में नगरपालिका क्षेत्र के अलावा चारों ओर के 44 गांवों को जोड़ा गया था. देवघर नगर निगम के बनने से पूर्व इन 44 गांवों में टैक्स के अलावा बिजली बिल ग्रामीण दर पर निवासियों को उपलब्ध था, परन्तु नगर निगम बनने के बाद सभी प्रकार के टैक्स एवं बिजली बिल आदि शहरी शुल्क के समतुल्य लागू हो गया जिसके कारण इन गांवों वाले क्षेत्र के निवासियों पर अतिरिक्त आर्थिक भार के बोझ से निम्नतर आय वाले लोगों का कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है. वार्ड पार्षद सह भाजपा नेत्री रीता चौरसिया के अनुसार देवघर नगर निगम बनने से विकास हुआ है परन्तु समय की कमी से काफी काम अधूरा रह गया है जिसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना है. श्रीमति चौरसिया ने कहा कि नगर निगम बोर्ड की बैठकों में कई अच्छे सुझाव एवं प्रस्ताव आए परन्तु इन पर सार्थक पहल नहीं हो पाई. उन्होंने देवघर का ज्वलंत रहा पेयजल समस्या पर भी चिंता प्रकट करते हुए कही कि पेयजल आपूर्ति पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है. श्रीमति चौरसिया के अनुसार विकास की रोशनी को जन जन तक पहुंचाना ही आगामी लक्ष्य है.

बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता आयोजित

देवघर के नगर भवन में संथाल परगना बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई. कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय विधायक नारायण दास, जरमंडी विधायक बादल पत्रलेख ने दीप प्रज्वलन कर किया, जिसमें जामताड़ा के देवोजीत कुमार को प्रथम, धनबाद के समीर टुडु को द्वितीय तथा गिरीडीह के अभिषेक पाल को तृतीय स्थान का पुरस्कार प्रदान किया गया. विशिष्ट अतिथियों में देवघर अनुमंडलाधिकारी जय ज्योति सामंता, एसडीपीओ दीपक पांडेय सहित संस्था के अध्यक्ष डा संजय कुमार, उपाध्यक्ष शाह अब्दुल कादिर इकबाल एवं सचिव मनीष चंद्रवंशी, समाजसेवी रीता चौरसिया, सेंट माईकल ऐंग्लो विद्यालय के निदेशक जे सी राज कार्यक्रम में उपस्थित होकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया. विजयी प्रतियोगी को नकद राशि के साथ प्रशस्ति पत्र व मेडल भी प्रदान किया गया. कार्यक्रम के सफल संचालन में फारूख अंजुम जो अल्जीरिया से विशेष आमंत्रण पर आए थे एवं फैजल इकबाल, आसिफ इकबाल की विशेष भूमिका रही.

नियमित टीकाकरण अभियान

भारत सरकार ने इन बच्चों को जो टीकाकरण से अबतक वंचित हैं, नियमित टीकाकरण अभियान के तहत 10 जानलेवा बिमारियों से बचाव के लिए मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम आगामी विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर प्रारंभ करने जा रही है. मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत् इन बच्चों को गला घोंटू, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाईटिस बी, न्यूमोनिया, जापानी इंसेफलाइटिस और मेनिनजाईटिस की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा. भारत सरकार झारखंड राज्य के 6 जिलों में 7 अप्रैल से अभियान चलाकर टीकाकरण का लक्ष्य लगभग 90 प्रतिशत तक करने की योजना है. प्रथम चरण का अभियान 7 अप्रैल से जुलाई तक एवं द्वितीय चरण सितंबर से प्रारंभ होकर दिसंबर तक चलेगा. युनिसेफ के पदाधिकारी ने बताया है कि जागरूकता की कमी, टीकाकरण के दुष्प्रभाव का डर, टीकाकरण की कमी के कारण संपूर्ण टीकाकरण नहीं हो पा रहा है जिसे मिशन इंद्रधनुश से पूरा करने की कोशिश होगी. खासकर गंगा नदी के दियरा क्षेत्र, वन व दुर्गम क्षेत्र, खानाबदोश आबादी, अन्य प्रवासी बस्तियों पर विशेष नजर रहेगी.

– रणजीत झा

शिक्षक संघ का धरना

गोगरी अनुमंडल मुख्यालनय में प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वाहन पर अपनी मांगों को लेकर प्रखंड शिक्षक संघ द्वारा प्रखंड कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया. मौके पर एक सभा का भी आयोजन किया गया. सभा की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष व राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक दूनबहादुर दास ने किया. प्रखंड उपाध्यक्ष अमरेन्द्र दास व सचिव मनोरंजन प्रसाद ने नियोजित शिक्षकों की मांग जायज बताया. शिक्षक संघ के विधिक सलाहकार सुनील कुमार मिश्र ने कहा कि संघ ने समर्थन देकर मनोबल व ताकत को बढ़ाया है. मौके पर प्रखंड के डीडीओ प्रभाकर ठाकुर, बीआरपी वकील ठाकुर, वेदानंद प्रसाद, सुनील कुमार सुमन, चन्द्रशेखर यादव, रवि आनंद, अवधेश कुमार, मनोज कुमार, बिहारी मंजू कुमारी, रवि आनंद, मृत्युंजय मिश्रा, चन्द्रभूषण भारती, पप्पू कुमार पासवान, भीखो मंडल सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित थे.

लावारिस शव का वारिस त्यागी भाई

गोगरी में जिस लावारिस शव का कोई दावेदार नहीं होता, उसके वारिस होते हैं नागेन्द्र सिह त्यागी. जी, हां जिस शव का कोई दावेदार नहीं होता हैं उसके दाह संस्कार को लेकर नागेन्द्र सिंह त्यागी आगे आ जाते हैं. पुलिस भी लावारिस शव को लेकर तनाव मुक्त रहती है. बीते दिनों साईराम नामक एक युवक की मौत जेएनकेटी स्टेडियम में हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. अस्पताल में एक लावारिस शव होने की खबर पा कर युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष नागेन्द्र सिंह त्यागी तथा युवा शक्ति के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंच गये और शव को दाह संस्कार के लिए चचरी बनाने लगे तो कोई जलावन की व्यवस्था में लग गये. इस दौरान संगन के कई लोगग उनकी मदद कर रहे थे. जिनमें प्रदेश महासचिव दीपक चन्द्रवंशी, जिला अध्यक्ष चंदन सिंह, अंटू सिंह, देवीलाल, राजीव प्रकाश, रणवीर कुमार सोनू, बालेश्वर साह आदि शामिल थे. सभी नागेंद्र की प्रशंसा करते हैं और इस सामाजिक कार्य को लेकर उनका हौसला भी बढ़ाते हैं.

शान से मना बिहार दिवस

गोगरी अनुमंडल में बिहार के 103वें स्थापना दिवस के मौके पर अनुमंडल कार्यालय प्रांगण में प्रशासनिक स्तर पर समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीओ संतोष कुमार ने 103 मोमबती जलाकर किया. मौके पर एसडीपीओ संजय कुमार झा, बीडीओ रंजीत कुमार सिंह,गोगरी प्रखंड प्रमुख रिमा देवी यादव, सीओ सुनील कुमार सिंह,कार्यपालक पदाधिकारी सुनील कुमार, चिकित्सा प्रभारी अरुण कुमार सिंह, बीसीओ किसलय कृष्ण, जेई सत्येन्द्र सिंह, थानाध्यक्ष संतोष शर्मा, प्रमुख प्रतिनिधि संजय यादव उपस्थित थे. एसडीपीओ संजय कुमार झा, डीसीएलआर संजय कुमार,बीडीओ रंजीत कुमार सिंह आदि ने भी बिहार के गौरवशाली इतिहास की चर्चा की और बिहारी होने के गर्व का एहसास दिलाया. इस मौके पर मुखिया धीरेन्द्र सिंह, शिक्षक रूस्तम अली, कवि व शायर अशोक अभिनवी, प्रभाकर ठाकुर, दिनेश पासवान, संजय कुमार यादव, पूर्व नगर भाजपा अध्यक्ष रौशन गुप्ता एवं एलएस लक्ष्मी कुमारी व पूर्व वार्ड पार्षद नरेश सुमन सहित स्कूल के बच्चे उपस्थित थे. सम्मानित भी किया गया.

शुटर गुड्डू गिरफ्तार

गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के जमालपुर बाजार में दिन दहाड़े छोटी पसराहा पंचायत के उपमुखिया शंभू सिह की हत्या करने वाले कुख्यात अपराधी गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया गया है. कुख्यात अपराधी गुड्डू पर 18 से भी ज्यादा हत्या, लूट और आपराधिक केस दर्ज हैं. उपमुखिया की हत्या के बाद पुलिस के लिए उसकी गिरफतारी एक सिर दर्द बन गई था. एसडीपीओ संजय कुमार झा ने प्रेसकांफ्रेस कर बताया कि पसराहा निवासी गुड्डू सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड काफी बड़ा है. जानकारी हो कि युवा इपमुखिया के हत्या के बाद एसपी ने गोगरी थानाध्यक्ष रंजीत सिंह को तत्काल निलंबित कर दिया गया था. वहीं गुड्डू सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण पसराहा थाना अध्यक्ष राजेश कुमार को भी स्थानांतरित कर दिया गया. वहीं गुड्डू के गिरफ्तार किए जाने के बाद लोगों ने एसपी को बधाई दी है. ज्ञात हो कि मृतक शंभू को एक साल की बेटी है जो बच्ची अपने पिता को सही ढंग से देख व समझ भी नहीं पायी.■

– गीता कुमार

सीतामढ़ी

गन्ना किसानों की कोई नहीं सुन रहा

भारत-नेपाल सीमा पर अवस्थित सीतामढ़ी व शिवहर जिलों में किसानों की समस्या का निदान होना मुश्किल बना है. संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. आनंद किशोर की मानें तो रीगा चीनी मिल से जुड़े तकरीबन 44 हजार गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं मिला है. जबकि पिछले पराई सत्र का करीब 20 करोड़ रुपये का भुगतान अब तक लंबित है. पेराई सत्र 2014-15 का गन्ना मूल्य लगभग सवा अरब के भुगतान को लेकर गन्ना किसान आंदोलन तेज करने का संकल्प व्यक्त करने लगे है...

वाल्मीकि कुमार

उत्तर बिहार के सीतामढ़ी-शिवहर जिले में एक मात्र औद्योगिक इकाई रीगा चीनी मिल मौजूद है. जहां हर साल हजारों की संख्या में गन्ना उत्पादक किसान बकाया राशि का भुगतान को लेकर मिल प्रबंधन के दरवाजे तक दौड़ लगाने को विवश होते हैं. परंतु दोनों ही जिलों में किसानों की समस्या का निदान कराने का दंभ भरने वाले कोई भी जनप्रतिनिधि अब तक इस दिशा में कारगर पहल नहीं कर सके हैं. आलम है कि अब गन्ना किसान अपनी समस्या का निदान के लिए खुद ही सड़क पर उतरने को बाध्य हो गये हैं. गन्ना किसानों की समस्या को लेकर संघर्ष करने वाला संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा अब आर-पार की लडाई करने की ठानी है पिछले 20 मार्च को मोर्चा के बैनर तले गन्ना किसानों ने रीगा चीनी मिल का एक दिवसीय घेराव कर रोष का इज़हार किया. आक्रोशित किसानों ने मिल प्रबंधन के साथ ही राज्य सरकार के प्रति भी जमकर भड़ास निकाली. किसानों का आरोप था कि गन्ना मूल्य का भुगतान में मिल प्रबंधन लापरवाही बरत रही है, परंतु सरकार व सरकार का प्रशासनिक तंत्र चैन की नींद सो रही है. हालांकी चुनावी साल में स्थानीय भाजपा विधायक मोतिलाल प्रसाद ने गन्ना किसानों की मांग को जायज करार देते हुए किसानों के सवाल पर सदन से सड़क तक संघर्ष करने की मंशा व्यक्त की. कहा कि गन्ना मूल्य का भुगतान का सवाल इनकी पहली प्राथमिकता में है. अब सवाल यह उठता है कि आखिर चुनावी साल में ही विधायक को प्राथमिकता सूची की याद आयी कैसे? बीते चार साल तक आखिर कौन सी समस्या का जंग छुड़ाने में विधायक जी व्यस्त रहे? खैर, इनकी मंशा चाहे जो भी हो, लेकिन गन्ना किसान को अब किसी पर भी तनिक भरोसा नहीं रह गया है. वैसे फिलहाल किसानों को उनके सहयोग की दरकार है.

घेराव कार्यक्रम में सीतामढ़ी जिले के रीगा, मेजरगंज, सुप्पी, डुमरा, बथनाहा, बाजपट्टी, रुन्नीसैदपुर एवं शिवहर के शिवहर व पुरनहिया प्रखंड से सैकड़ों किसानो ने भागीदारी दी. इस दौरान किसानों ने मिल प्रबंधन मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद... जैसे नारे लगा कर अपनी भड़ास निकाली. कार्यक्रम में किसानों ने रीगा डिस्टीलरी के प्रदूषित पानी से मनुष्यमारा की धार को जहरीला होने, गन्ना कृषि रोड मैप में किसानों की राशि का विगत तीन सालों की उच्चस्तरीय जांच कराने, छोटे किसानों का भुगतान काउंटर से एक सप्ताह में कराने समेत अन्य मांगों पर चर्चा की. नये सत्र में किसानों ने गन्ने की नयी खेती बंद करने की मोर्चा की अपील का समर्थन किया. किसानों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर मिल प्रबंधन द्वारा भुगतान के सवाल पर रवैया सुधार नहीं किये जाने पर अगले सत्र से गन्ना खेती बंद करने का निर्णय लिया गया. साथ ही गन्ना के वैकल्पिक खेती पर विचार करने की मंशा व्यक्त की. किसानों ने राज्य सरकार से मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक पहल की अपील की. साथ ही दोनों जिले के जनप्रतिनिधियों से चुप्पी तोड़ने का आग्रह किया. मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. आनंद किशोर ने कहा कि नये सत्र में 44 हजार किसानों को गन्ना मूल्य का एक रुपया नहीं मिला है. विगत पेराई सत्र का भी करीब 20 करोड़ भुगतान लंबित है. मिल प्रबंधन 48 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई कर भुगतान करने से कतरा रही है.

कार्यक्रम में मोर्चा के जिलाध्यक्ष राम तपन सिंह, मेजरगंज से ओमप्रकाश कुशवाहा, करूण कुमार, पुरनहिया शिवहर से विनय कुमार सिंह, शिवहर से मंसूर अहमद खान, रून्नीसैदपुर से जीवनाथ साफी, डुमरा से जलंधर यदुवंशी, हरिओम शरण नारायण, भोला बिहारी, सुप्पी से राम शोभित सिंह, शिवेंद्र सिंह, परसौनी से धीरज कुमार, बाजपट्टी से नंदकिशोर मंडल, बथनाहा से सुरेंद्र प्रसाद सिंह, दिग्विजय सिंह, मोर्चा नेता पारसनाथ सिह, प्रो त्रिपुरारी मोहन शर्मा, रमेश प्रसाद सिंह, राम जनम गिरी, मोहन राम, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बिजेंद्र ठाकुर, जिला कार्यसमिति सदस्य आफताब अंजुम बिहारी, अतुल कुमार सिंह, धीरेंद्र किशोर सिंह, महासचिव सर्वजीत यादव, कुलदीप यादव व रवींद्र सिंह समेत अन्य शामिल थे.■

feedback@chauthiduniya.com

विधान परिषद चुनाव : भटक रहे वोटों के सौदागर

वाल्मीकि कुमार

feedback@chauthiduniya.com

राजनीति के क्षेत्र में लगातार हो रहा बदलाव से एक बात साफ हो गई है कि अब लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमान ईमानदार हाथों में नहीं हो सकती है. कारण कि बेईमानी व लूट खसोट से कमाई दौलत ही राजनीति के शिखर पर किसी को भी काबिज कर सकता है. चाहे वह व्यक्ति अंगूठा छाप और मवाली ही क्यों नहीं हो. हाल के दशक में भारत निर्वाचन आयोग की सख्ती पर बाह्य स्तर पर चुनावों में फिजूल खर्ची पर रोक जरूर लगी है, लेकिन पर्दे के पीछे जारी धन वर्षा पर अब भी अंकुश नही लग सका है. नतीजा है कि सभी राजनीतिक दलों में अलग-अलग क्षेत्रों से दर्जनों ऐसे चेहरे विलायती पकवान की तरह जनता बीच सजने लगे है जिनकी हाल के दशक में पहचान ही बन सकी है. यह अलग बात है कि वैसे लोग भी खुद को जेपी, लोहिया व जननायक का अनुयायी कहने से पहेज नही कर रहे हैं. दूसरी ओर जागरूकता के बाद भी आम जनता अपनी गलती में सुधार करने को तैयार नही है. चुनाव के समय चंद जाति व पार्टी गत दलालों की बातो में आकर मतदाता अपने अधिकार को गिरवी रख लेता है और चुनाव बाद सिर धुनता है. जाहिर सी बात है जब कोई करोड़ों खर्च कर चुनाव लड़ता है तो मंशा कई गुना अधिक कमाने की होती है. सेवा व समर्पण के साथ क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कराने की बात चुनावी सभाओं के दौरान मंच पर ही रह जाया करता है. ऐसी स्थिति में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आम मतदाताओं को इन पहलुओं पर बारिकी से गौर जरूर करना चाहिए. वैसे तो बिहार में विधान परिषद व विधानसभा दोनों का चुनाव इस साल ही होना है. परंतु पहले विधान परिषद चुनाव को लेकर चल रही बयानबाजी पर चर्चा आवश्यक है.

सीतामढ़ी-शिवहर क्षेत्र से विधान परिषद के स्थानीय निकाय से वर्तमान में भाजपा के बैद्यनाथ प्रसाद बतौर सदस्य हैं. 2015 में संभावित चुनाव को लेकर अब चुनावी चर्चा गरमाने लगी है. चर्चा है कि अबकी बार भाजपा व जदयू अलग – अलग चुनावी समर में अपने समर्थित प्रत्याशी को लाने की तैयारी में है. जबकि पिछले चुनाव में दोनों दल गठबंधन के तहत जीत हासिल की थी.

अजय विद्रोही | आशा प्रभात | डॉ. अमरनाथ गुप्ता | डॉ. आनंद किशोर | नवल किशोर शाही

भाजपा समर्थित वर्तमान पार्षद को चुनावी समर में मात देने को लेकर पुराने राजनीतिक मित्र रुन्नीसैदपुर की जदयू विधायक गुड्डी देवी के पति सह जनता दल यू के वरीय नेता राजेश चौधरी पूरी तैयारी में लगे है. जबकि भाजपा से ही प्रदेश कार्यसमिति सदस्य विश्वजीत पाठक भी चुनावी समर में ताल ठोंकने को तैयार है. राजद से प्रदेश युवा उपाध्यक्ष दिलीप राय भी जी तोड़ प्रयास में लगे है. इसी दल से लालबाबू राय ने भी चुनावी अभियान को गति देना शुरू कर दिया है. इनके अलावा अमिताभ गुंजन समेत अन्य भी परिषद चुनाव में अपना भाग्य आजमाने की फिराक में है. चर्चा है कि चुनावी अभियान के साथ ही कुछ संभावित प्रत्याशियों ने पंचायत प्रतिनिधियों की बोली भी लगाने का काम शुरू कर दिया है. जबकि दलगत समर्थन वाले संभावित प्रत्याशी चुनाव में पंचायत प्रतिनिधियों का ईमानदार समर्थन मिलने की उम्मीद लगाये है. सवाल उठता है कि परिषद चुनाव के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग ईमानदारी के साथ करेंगे अथवा वोटो के सौदागर के हाथों अपने मताधिकार को गिरवी रख देंगे ?

अब चुनावी मौसम में उभरने वाले धनकुबेरो को लेकर चल रही चर्चाओं पर गौर करे तो खासकर समाज के प्रबुद्ध वर्ग विशेष तौर से परेशानी महसूस कर रहे है. सिटीजन फोरम के महासचिव अजय विद्रोही का कहना है कि वर्तमान में चुनाव पैसा पर ही निर्भर हो गया है. पंचायत प्रतिनिधियों को अर्थलाभ की खातिर नैतिकता को ताक पर नहीं रखना चाहिए. विकास के लिए सजग प्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहिए. साहित्यकार आशा प्रभात का मानना है कि बिकाउ वोटर ही भ्रष्टाचार के पोषक होते है. वैसे लोगों को चंद पैसों की खातिर अपने मताधिकार का सौदा करने से परहेज करना चाहिए. साथ ही संवैधानिक अधिकार के महत्व को समझना चाहिए. जदयू नेता डॉ. अमरनाथ गुप्ता का कहना है कि चुनाव में जमीनी कार्यकर्ता को तरजीह देना चाहिए. दारू – शराब व पैसा की बदौलत चुनाव में बाजी मारने की मंशा रखने वालों को सबक सिखाना चाहिए. अपने मताधिकार को बुलेट बनाकर वैसे लोगों को बैलेट से जवाब देना चाहिए. पूर्व मंत्री नवल किशोर शाही का कहना है कि विधान परिषद राजनीति का चोर दरवाजा है. इस रास्ते से राजनीति में असामाजिक तत्वों का प्रवेश भी आम हो गया है. पंचायत प्रतिनिधियों को चाहिए कि एकजुट होकर जमीनी व कुशल कार्यकर्ता को वोट दें. राजनीति को व्यवसाय मानने वालों को सबक सिखाना आवश्यक है. डॉ आनंद किशोर का कहना है कि वोटों का सौदागर लोकतंत्र का हत्यारा है. पैसा की राजनीति करने वाले आमजनों की भावना से खिलवाड़ करते हैं. लूटेरे के रूप में पैसा खर्च कर चुनाव बाद समाज के सभी तबके का हकमारी से परहेज नही करता है. आम लोगों को भी अपने प्रतिनिधियों पर पैनी नजर रखनी चाहिए ताकि वह अपने मताधिकार का सौदा करने से पहले सोचने को बाध्य हो जाये.

कुल मिलाकर चुनावी चौपाल सजना शुरू हो गया है. एक ओर कोई चुनाव में पैसा का खेल होने की संभावना व्यक्त करता है तो कोई इस खेल पर चुनाव आयोग व जिला प्रशासन की पैनी नजर होने की बात भी करता है. वैसे चुनाव में अभी वक्त है. हर दिन एक नया शिगूफा चुनावी फिजा में गूंजना आम बात है. परंतु सबसे अधिक पैसा के खेल की चर्चा ही जोरो पर है. चुनावी गलियों में नोटो की पोटली लेकर दस्तक देने वालों को आने वाले दिनों में खुशी मिलेग अथवा गम, अब लोगों की निगाहे वही टिकी है.■

एक नज़र

रामनवमी मेला का उद्घाटन

सीतामढ़ी रामनवमी मेला समिति के तत्वावधान में गोशाला परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. एडीजे प्रथम प्रभुनाथ सिंह, जिप अध्यक्ष इंद्रानी देवी, एडीएम डीएन मंडल, डीडीसी राम शंकर सिंह व सदर एसडीओ संजीव कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर मेला का इदघाटन किया. मौके पर सीजेएम एके दूबे, डीएसपी एमएन इपाध्याय, डीसीएलआर संदीप कुमार, कांग्रेस जिलाध्यक्ष विमल शुक्ला, विमल सिन्हा, अभिषेक मिश्रा, अजय विद्रोही व डीएचओ डॉ बीपी सिन्हा समेत अन्य थे.

– ब्रजेश कुमार

डीएम ने किया पुरस्कृत

कहा गया है कि बेहतर का परिणाम कभी बुरा नही होता. सीतामढ़ी जिला के दो प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने कुशल कार्य प्रणाली का ऐसा मिसाल कायम किया है, जैसा का इम्मीद वर्तमान में बहुत ही कम किया जा सकता है. बताया गया है कि समय पर डाटा बेस इपलब्ध कराने पर खाद्य एवं इपभोक्ता संरक्षण विभाग ने तत्कालीन डीएसओ सह एसडीसी केके इपाध्याय एवं सूचना विज्ञान पदाधिकारी अभिषेक कुमार मिश्रा को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया था. जिसके आलोक में डीएम डॉ प्रतिमा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में दोनो पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया. मौके पर डीटीओ राजेश चौधरी समेत अन्य थे.

– वाल्मीकि कुमार

भरोसा खो चुकी है भाजपा

सीतामढ़ी जिला जदयू इपाध्यक्ष भरत प्रसाद ने कहा कि सूबे में भाजपा का अब कोई खास स्थिति नही रह गयी है. लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी सभाओं में आम जनता को अच्छा दिन दिखाने का भरोसा दिया गया था. परंतु चुनाव बाद से अब तक भाजपा सरकार का हर एक कदम जन विरोधी पटरी पर दौर रही है. जिस इम्मीद से लोगों ने भाजपा पर भरोसा किया था, इसे भाजपा की सरकार ने खो दिया है. आगामी विधानसभा चुनाव में सूबे बिहार की जनता झूठ बोल कर ठगने वाली पार्टी को सबक सिखाने को तैयार है. सिनेमा रोड स्थित अपने आवास पर इन्होने कहा कि सीतामढी जिला में अबकी बार भाजपा को भारी कीमत चुकानी पडेगी. आम जनता ने सीएम नीतीश कुमार को पुन: शासन का कमान देने का मन बना लिया है.

कांग्रेस ने किया बिल का विरोध

भूमि अधिग्रहण बिल, खाद्य सुरक्षा अधिनियम व मनरेगा की राशि में भारी कटौती के विरोध में सीतामढी जिला कांग्रेस कमिटी के तत्वावधान में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया. जिलाध्यक्ष विमल शुक्ला के नेतृत्व में बाजपटटी, पुपरी, चोरौत व सुरसंड के अलावा जिले के सभी प्रखंडों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिलाध्यक्ष ने बताया कि जिले में 50 हजार से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किया है. सूचि प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से राष्ट्रपति को सौपी जायेगी. जिला मुख्यालय डुमरा स्थित प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रभारी सत्येंद्र तिवारी, सीमा गुप्ता, पप्पू परवीन, किसान सेल के जिलाध्यक्ष संजय कुमार, कृष्ण कुमार महान, प्रवक्ता शिव शंकर शर्मा, युवाध्यक्ष अंजारूलहक तौहिद, अनवर हुसैन व मो फरीद, बाजपटटी में प्रखंड अध्यक्ष ताराकांत झा, रमा शंकर झा, राम बरण सिंह, बैरगनिया में प्रखंड प्रभारी ईश्वरचंद्र दीन, सीताराम झा, शिव शंकर सिंह, हरदेव पाठक, चोरौत में राजकुमार साह, दिलीप चौधरी, पंकज चौधरी, पुपरी में प्रखंड अध्यक्ष महेश्वर गिरी, एम रहमान, सुधीर भटनागर, राम कल्याण राय, रून्नीसैदपुर में मणि भूषण कुमार समेत अन्य ने भाग लिया.

– विकास कुमार

बीरगंज की टीम ने फाइनल मैच जीता

चकिया गांधी मैदान में आयोजित छठा अखिल भारतीय सरदार अमृत सिंह विक्की मेमोरियल फूटबॉल टूर्नामेन्ट का फाइनल मुकाबला आज यूथ क्लब बीरगंज व जनकपुर एकादश टीम के बीच हुआ जिसमें युथ क्लब की टीम विजयी रही. जनकपुर एकादस 1-0 से पराजित हो गयी. मैच के मुख्य विजेता टीम बीरगंज व इप मुख्य विजेता टीम को मुख्य अतिथि स्थानीय सांसद सह केन्द्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने सम्मानित किया. खेल के पैसठ वें मीनट पर बीरगंज की टीम के चत्रुधन चौधरी ने एक गोल मार कर अपनी बढ़त बना ली. इस टूर्नामेन्ट का आयोजन चकिया फुटबॉल एकेडमी किया था. मौके पर चिरैया विधायक सह जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण यादव, हरसिद्धि विधायक कृष्णनन्दन पासवान, मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार, केसरिया विधायक सचिन्द्र सिंह, नगर पंचायत मुख्य पार्षद वीणा देवी तथा पत्रकार मो0 इसाइदीन, आयोजन समिति के अध्यक्ष हरजीत सिंह राजू, ओम प्रकाश गुप्ता, भाजपा इपाध्याय सुभाष सिंह कुशवाहा, राधेश्याम गुप्ता, चन्द्रभूषण प्रसाद, टूर्नामेन्ट के इद्घोषक थे. रोहीत सिंह एवं जोहा अफजल थे.

श्रीरामचरितमानस महायज्ञ का शुभारम्भ

मोतिहारी में नगर के महावीर परिसर में दस दिवसीय 44 वां श्री राम चरित मानस नवाहन परायण महायज्ञ का इद्घाटन दीप प्रज्वलित कर पारंबा सेवा शक्ति पीठ के संस्थापक स्वामी शक्ति शरणानन्द जी महाराज चंचल बाबा ने किया. अपने इद्घाटन प्रवचन के दौरान इन्होंने कहा कि किसी भी संस्था द्वारा लगातार 44 वां निर्विहन आयोजन कराना बहुत बड़ी बात है. धर्म परायणता का यह एक इदाहरण है. संस्था के रामाश्रय सिंह एवं नारायण अग्रवाल की मृत्यु पर इन्होंने श्रद्धांजली भी दी. यज्ञ की परिभाषा पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि तीन यज्ञ में में सातशी, राजसी और तामसी होते है. सत्संग में जाने से ही प्राप्ति होती है. इस प्राप्ति में मुख्य है सुख, शांति. इद्घाटन तिथि को इन्होंने नव दुर्गा सिद्धि दात्री का दिन कहा. राम का अवतरण दिन होने से इसका महत्व काफी ज्यादा है. राम ही नारायण बनते है. इनका अवतरण धर्म गलानी के घोर अंधियारे के समय होता है. मानस सत्संग समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सीतामढ़ी के व्यास पं0 वेद प्रकाश पाण्डेय एवं इनकी मंडली द्वारा राम जन्मोत्सव पर कई भक्तिमय गीत प्रस्तुत किए गए.

क्लीनिक का हुआ उद्घाटन

मोतिहारी शहर के मेन रोड स्थित बेलही देवी मंदिर के समीप एक निजी क्लिनिक का इद्घाटन रहमानिया मेडिकल सेन्टर के संचालक डॉ0 तबरेज अजीज एवं पूर्व विधायक मो0 ओबैदुल्लाह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया. डॉ0 तबरेज ने बताया कि इक्त क्लिनिक के चिकित्सक डॉ0 रणधीर सिंह काफी मेघावी चिकित्सक है. इनके द्वारा किया गया सर्जरी हमेशा सराहनीय रहा है. मौके पर इक्त क्लिनिक के संचालक व लेप्रोस्कॉपिक एण्ड जेनरल सर्जन डॉ0 रंधीर सिंह, डॉ0 तस्नीम खातुन ,डॉ0 संतोष कुमार, डॉ0 स्वास्ति सिन्हा, डॉ0 दीपक कुमार, डॉ0 प्रदीप कुमार, डॉ0 नागमणि सिंह, डॉ0 संजय कुमार, डॉ0 निर्भय सिंह, डॉ0 कुमार सौरभ, डॉ0 संगीता, डॉ0 आरके वर्मा, डॉ0 नूतन सिन्हा, कोटवा प्रखण्ड प्रमुख अवधेश सिंह, कैप्टन हमीद सहित अनेक लोग इपस्थित थे.

– इन्तेजारूल हक

सुमन की सादगी पर मैं फ़िदा हो गया

राधिका

feedback@chauthiduniya.com

जैसे हिमाचल की खूबसूरती देखते बनती है, वैसे ही इस जोड़े के प्यार की खूबसूरती का भी कोई जवाब नहीं है. साथ ही जैसे हिमालय को उसकी जगह से कोई नहीं हिला सकता ठीक वैसे ही इन दोनों के प्यार की ताकत ने ज़माने को उनके सामने सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया. इस बार की कहानी है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा और उनकी पत्नी सुमन की. लड़की हिमाचल की और लड़का बिहार का. शायद ये भी एक कारण था जिस वजह से इन दोनों को मुश्किलों का कुछ ज्यादा ही सामना करना पड़ा.

जब शादी के बाद दुल्हन घर आई और जब सबने सुमन को जानना शुरू किया तब जाकर लोगों को लगा कि मेरा फैसला ठीक था और मैंने सही लड़की को अपने जीवनसाथी के रूप में चुना था और धीरे-धीरे सबने सुमन को एक्सेप्ट कर लिया.

ये सिलसिला तब शुरु हुआ था जब प्रेमचंद्र मिश्रा एनएसयूआई के जेनेरल सेक्रेटरी थे, और सुमन कॉलेज स्टूडेंट थीं. अपने काम के सिलसिले में प्रेमचंद्र को हिमाचल आना जाना पड़ता था. बात 1987 की है जब प्रेमचंद्र एचपी यूनिवर्सिटी गए थे. इसी यूनिवर्सिटी में सुमन पढ़ती थीं. इसी दौरान एक कॉमन फ्रेंड के जरिये दोनों की मुलाकात हुई थी. और मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा और फिर सिलसिला कभी थमा हीं नहीं. इस मुलाकात के बाद प्रेमचंद्र वापस आ गए. लेकिन सुमन का चेहरा उनके जेहन से नहीं गया. फिर एक दिन उन्होंने सुमन को प्रपोज किया. इसके बाद शुरू हुआ बातों का और मुलाकातों का सिलसिला. सुमन ने बताया कि उस समय मोबाईल फोन नहीं हुआ करते थे तो हमारी बात लैंडलाइन पर और चिट्ठियों के जरिये होती थी.

प्रेमचंद्र बताते हैं कि मैं मिथिला का हूं और सुमन हिमाचल की. परिवार की स्वीकृति के साथ-साथ राजनीतिक कार्यकर्ता होने की वजह से समाज की भी स्वीकृति लेनी थी. राजनीतिक स्तर पर लोगों ने समझाया कि इंटरकास्ट शादी करने से मेरे राजनीतिक जीवन पर भी असर पड़ सकता है लेकिन मेरा मानना था कि सुमन के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा. बस इसी बात की तसल्ली के साथ मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ता गया, और आखिरकर हम साथ हो गए.

इन दोनों ने कई मुश्किलों का सामना किया और आखिरकर सुमन के माता-पिता प्रेमचंद्र से मिलने को राजी हो गए. हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन दोनों की शादी तय करने के लिए लड़के के घर से कोई नहीं गया. सुमन के माता-पिता सिर्फ प्रेमचंद्र से मिल कर इतने प्रभावित हुए कि उनमें प्रेमचंद्र के प्रति एक विश्वास जग गया और उन्होंने इस शादी को लिए हामी भर दी. दोनों की शादी तय हो गई. दोनों की शादी 1991 में शिमला से हुई. दोनों के परिवार वाले एक दूसरे से शादी के दिन ही मिले थे, इससे पहले दोनों परिवारों की कभी मुलाकात तक नहीं हुई.

प्रेमचंद्र बताते हैं कि जब शादी के बाद दुल्हन घर आई और जब सबने सुमन को जानना शुरू किया, तब जाकर लोगों को लगा कि मेरा फैसला ठीक था और मैंने सही लड़की को अपने जीवनसाथी के रूप में चुना था और धीरे-धीरे सबने सुमन को एक्सेप्ट कर लिया.

प्रेमचंद्र का ये मानना कि सुमन के आने से सब ठीक हो जाएगा बिल्कुल सही साबित हुआ. घरवालों ने तो सुमन को एक्सेप्ट कर हीं लिया था और साथ-साथ राजनीतिक जीवन में भी सुमन प्रेमचंद्र के लिए लेडी लक साबित हुईं. प्रेमचंद्र बताते हैं कि जब मैंने 1990 में चुनाव लड़ा था तब मुझे हार का सामना करना पड़ा था लेकिन सुमन से शादी होने का बाद जब 1995 में मैंने चुनाव लड़ा तो जीत का सेहरा मेरे सिर बंधा. इसी से साबित होता है कि सुमन से बेहतर जीवन साथी मेरे लिए कोई और नहीं हो सकता है. मेरे अंदर जो सेल्फ कांफिडेंस है वो सुमन से ही आता है. आगे बढ़ने की प्रेरणा भी सुमन से ही मिलती है. प्रेमचंद्र आगे कहते हैं कि जिस चीज ने मुझे उनकी तरफ एट्रेक्ट किया था वो था उनका सहज स्वभाव और सुंदरता या यूं कहें की उनकी ब्यूटी विद सिंप्लीसिटी की वजह से मैं उनकी तरफ खिंचा चला गया और वहीं से वो मेरे दिल में बस गईं.

आज इन दोनों को शादी के बंधन में बंधे 24 साल हो गए हैं. दोनों साथ में बहुत खुश हैं. इन दोनों के दो बच्चे हैं. एक बेटा और एक बेटी. बेटा नौंवी में पढ़ता है और बेटी ने डीयू से इकोनॉमिक ऑनर्स किया है.■

विवाद में फंसा मविवि कर्मचारी आवास निर्माण

सुनील सौरभ

मगध विश्वविद्यालय हमेशा अपने कारनामों से सुर्खियों में रहा है. कुछ वर्षों पूर्व तो फर्जी डिग्री के मामले में मगध विश्वविद्यालय पूरे देश में चर्चा में रहा था. यहां के कई कर्मी व पदाधिकारी देश के कई जेलों में सजा भी काट चुके हैं. इन दिनों मगध विश्वविद्यालय, प्राचार्य बहाली, आईआईएम को भूमि देने का मामला हो या फिर विश्वविद्यालय मुख्यालय के तृतीय व चतुर्थवर्गीय कर्मियों के लिए बनने वाले आवास का मामला हो, को लेकर सुर्खियों में है. ताजा मामला है मगध विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए बनने वाली बहुमंजिली इमारत का. कहा जाता है कि इसमें ढाई करोड़ रुपये कमीशन का मामला फंसा है. 9.5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले तीन मंजिले भवन के चार ब्लॉक में 56 चतुर्थवर्गीय व 40 तृतीय वर्गीय कर्मचारियों का आवास होगा. इसके लिए 27 मार्च 2015 को मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एम. इश्तेयाक ने विश्वद्यिालय परिसर में भूमि पूजन कर भवन निर्माण का शिलान्यास किया. लेकिन कर्मचारी आवास में निर्माण कार्य के बाद ही इसका मामला विवाद में आ गया है. विश्वविद्यालय के आंतरिक सूत्रों से कर्मचारी आवास निर्माण किये जाने तथा इसके लिए संवेदक (ठेकेदार) को दस प्रतिशत अग्रिम राशि दिये जाने के कुलपति के कथित आदेश के बाद ही यह मामला विवाद में आ गया. बताया तो यह भी जाता है कि कुलपति ने कुलसचिव डॉ. डीके यादव को इस भवन निर्माण के ठेकेदार को कुल लागत का दस प्रतिशत लगभग 95 लाख रुपया अग्रिम देने को कहा. इस पर कुलसचिव ने अग्रिम राशि देने के लिए मगध विश्वविद्यालय की भवन समिति, वित्त समिति तथा वित्त पदाधिकारी से फाइल को अनुमोदित होने के बाद नियमानुसार अग्रिम भुगतान की बात कही. इस बात पर कुलपति तथा कुलसचिव में ठन गयी. अनियमित कार्य कराये जाने के प्रयास पर कुलसचिव ने इस्तीफा देने तक की धमकी दे डाली. बाद में इस मामले को किसी तरह शांत किया गया. मगध विश्वविद्यालय शिक्षेकत्तर कर्मचारी संघ के पूर्व महासचिव अमरनाथ पाठक ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार से भवन आदि बनाने के लिए पर्याप्त राशि बराबर मिलती रही है. कर्मचारी आवास के लिए राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है. विश्वविद्यालय को राज्य सरकार के निर्णय का इंतजार करना चाहिए था. विश्वविद्यालय के आंतरिक स्रोत से भवन निर्माण के लिए शिलान्यास करने की जल्दबाजी क्यों की गयी? इसमें कहीं न कही दाल में काला है. एक तरफ मविवि में अनुकंपा पर बहाल कर्मियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है. वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय के आतंरिक स्रोत की राशि को किसी न किसी रूप में बंदरबांट किये जाने का प्रयास किया जा रहा है. अमरनाथ पाठक ने कुलसचिव डॉ. डीके यादव पर कुलपति द्वारा उपयुक्त कार्य के लिए ठेकेदार को अग्रिम भुगतान समेत अन्य तरह के अनियमित कार्यों के लिए भुगतान हेतु दबाव दिये जाने का विरोध किया है. बताया जाता है कि कुलपति अपने कार्यकाल में मविवि में भवन निर्माण के कई कार्य कर विवि मुख्यालय को एक नया लुक देना चाहते हैं. लेकिन विवि कर्मियों का कहना है कि कुलपति अपने बचे शेष कार्यकाल में मविवि के तमाम आतंरिक स्रोत के राशि का वारा-न्यारा कर देना चाहते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

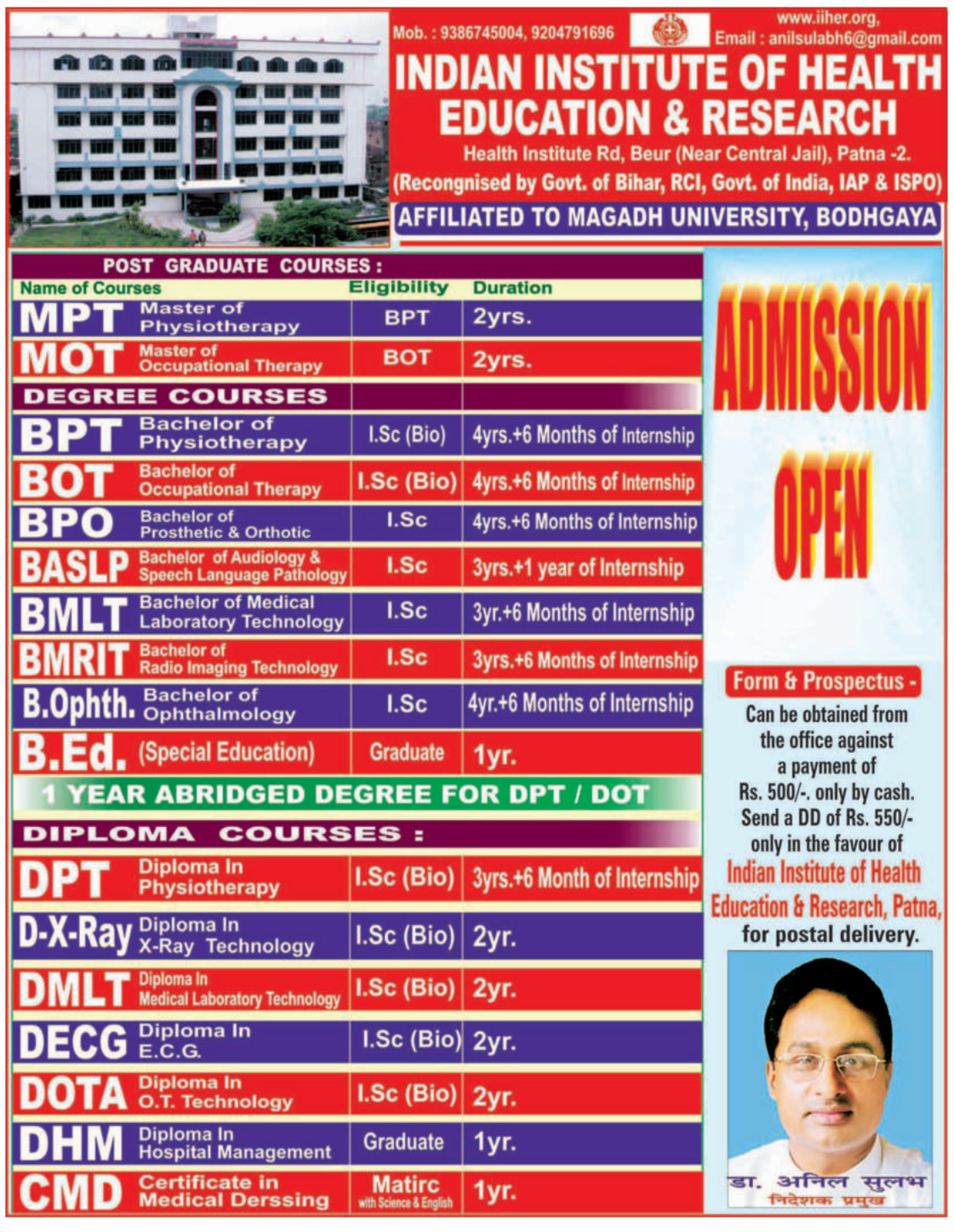

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

13 अप्रैल –19 अप्रैल 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

समाजवादी सरकार और विधायकों की जन–पक्षधरता का सच

किसान मरे तो मरे, अपना तो वेतन बढ़े...

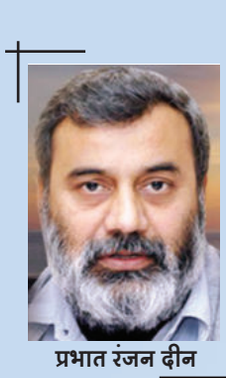

प्रभात रंजन दीन

यह आधुनिक उत्तर प्रदेशीय समाजवाद का ही तकाजा है कि जिस समय प्रदेश का किसान आत्महत्याएं कर रहा होता है, जिस समय वह अपनी बर्बादी का खुद ही गवाह हो रहा होता है, उस समय उन्हीं किसानों का जन प्रतिनिधि विधानसभा में अपना वेतन और सुविधाएं बढ़वाने के लिए समाजवादी सत्ता की चाटुकारिता कर रहा होता है. समाजवादी सरकार ऐसे ही जन प्रतिनिधियों के लिए लजीज भोज दे रही होती है और वेतन और सुविधाएं बढ़ाने का फैसला कर रही होती है. मंचों से बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश में जनता की सरकार है और प्रपंचों से इसके विपरीत कृत्य सामने उजागर होते हैं. सारा विपक्ष जनता से जुड़े मसलों पर सदन में विरोध का प्रहसन खेलता है और अपनी सुविधाओं के लिए सरकार के समक्ष औंधे मुंह गिर पड़ता है.

समाजवादी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधायकों के लिए खजाना ही खोल दिया. विधायकों के कुल वेतन में 25,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी कर दी गई. पूर्व विधायकों की पेंशन 8,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई. इससे सरकारी खजाने पर सालाना 47.81 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ा. लेकिन इससे मुख्यमंत्री या अन्य जन प्रतिनिधियों पर क्या फर्क पड़ता है. जिन आम लोगों पर फर्क पड़ता है, उनकी औकात ही क्या है. अब विधायकों की बेसिक सैलरी 8,000 रुपये प्रति महीने से बढ़कर 10,000 रुपये हो गई. निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 22,000 रुपये से बढ़कर 30,000 रुपये हो गया. विधायकों का मेडिकल भत्ता 10,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया. उनका सेक्रेटरी भत्ता भी 10,000 रुपये से बढ़कर 15,000 रुपये हो गया. अभी बात खत्म नहीं हुई है. विधायकों को इजाफाशुदा वेतन और भत्तों के अलावा सवा तीन लाख रुपये तक के रेल कूपन या हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी. पहले यह सुविधा ढाई लाख रुपये तक थी. अब तक विधायकों को सदन की बैठक या समितियों के सदस्य के रूप में बैठक में भाग लेने पर साढ़े सात सौ रुपये का दैनिक भत्ता भी मिलता था. यह अब बढ़कर 1000 रुपये हो गया है. यदि सदन और समिति की बैठक नहीं भी चलेगी तो विधायकों को आठ सौ रुपये रोजाना दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने सरकारी धन को विधायकों के बीच ऐसे ही बांट दिया जैसे सरकारी खजाना उनकी विरासत में हो. लेकिन इससे अधिक विडंबना यह है कि सरकारी खजाने के इस बेजा इस्तेमाल पर एक भी विधायक ने नैतिक विरोध नहीं दर्ज कराया.

मुख्यमंत्री प्रदेश के किसानों और बेरोजगारों के साथ जैसा भी रुखा रुख रखते हों, पर सदन में उनका यश–गायन चलता रहे इसके लिए उन्होंने न केवल विधायकों बल्कि विधानसभा के कर्मचारियों का भी मानदेय 6000 से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिदिन कर दिया. विधानसभा और विधान परिषद के पूर्व सदस्यों के बेसिक पेंशन राशि में दो हजार रुपये प्रतिमाह की वृद्धि कर दी गई. यदि कोई विधायक एक दिन या एक साल तक सदन का सदस्य रहा है, तो उसे प्रथम वर्ष की बेसिक पेंशन आठ हजार रुपये के बजाए अब दस हजार रुपये मिलेगी. एक साल के बाद विधायकी के वर्षों के आधार पर पेंशन तय होती है. पेंशन में प्रति वर्ष के हिसाब से 750 रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त जोड़ा जाता था. अब यह राशि 1000 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है. इसके अलावा पूर्व विधायक की मृत्यु होने के बाद उसके जीवनसाथी को आजीवन कम से कम दस हजार रुपये पेंशन दी जाएगी. पूर्व विधायकों को भी मुफ्त रेल कूपन की लिमिट 60,000 से बढ़ा कर 80,000 रुपये कर दी गई है. विधायकों के वेतन–भत्तों में बढ़ोतरी के बाद विधानसभा और विधान परिषद के विधायकों को अब 99 हजार प्रतिमाह वेतन–भत्ता मिलेगा. इसके अलावा 3.25 लाख रुपये के रेल कूपन भी मिलेंगे. रेल कूपन में हर महीने पेट्रोल–डीजल के लिए 18 हजार रुपये नकद प्राप्त करने की सुविधा होगी. सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में सदन में एक विधेयक पेश किया गया, जिसे पक्ष–विपक्ष ने ध्वनिमत से पारित कर दिया.

अब नेताओं की अमानवीय कुटिलता देखिए विधानसभा और विधान परिषद में सारे विधायकों ने मिल कर अपना वेतन और सुविधाएं बढ़वाईं और ध्वनिमत से इसका प्रस्ताव पारित कराया. बाहर जनता को झांसा देने के लिए बैठी इनकी पार्टियां विधायकों के वेतन–भत्तों में की गई बढ़ोत्तरी के खिलाफ बयान जारी करती रहीं. भाजपा ने विधायकों के वेतन बढ़ोत्तरी की निंदा की. कहा कि प्रदेश अतिवृष्टि से जूझ रहा है. ऐसे में किसानों की दशा पर विचार करने के बजाय विधायकों ने विधान परिषद व विधान सभा में विधेयक पास कर अपना वेतन और भत्ता बढ़ा लिया. इसके लिए भाजपा किसान मोर्चा के जिला प्रभारी सूर्यपाल सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा कि प्रदेश दैवीय आपदा से जूझ रहा है. किसानों की खून पसीने से तैयार फसलें अतिवृष्टि से नष्ट हो गईं. किसानों को मुआवजे के रूप में नाम मात्र की धनराशि दी जा रही है. किसान आत्महत्याएं कर रहा है. ऐसे में सरकार व विधायकों को किसानों की कोई चिंता नही है. वह विधान परिषद व विधानसभा में बैठकर अपना वेतन बढ़ा रहे हैं जो निंदा का विषय है. वेतन बढ़ोत्तरी के सवाल पर किसी भी विधायक ने विधेयक का विरोध नही किया. पत्र में मांग की गई कि विधायकों का आधा वेतन छह माह तक आपदा राहत कोष में जमा कराया जाए. लेकिन इसके लिए कोई भी विधायक आगे नहीं आया. सूर्यपाल सिंह की पार्टी का भी कोई विधायक जनहित के इस काम के लिए आगे नहीं आया.

विधायकों के वेतन वृद्धि पर सभी राजनीतिक दलों के विधायक उत्तर प्रदेश विधानसभा में एकमत रहे. श्रमिक और किसान वर्ग की हित चिंता केवल नारा है. सामाजिक संगठन भी इन नारों के बूते अपनी दुकान चलाती हैं. द सोशलिस्ट फाउंडेशन ऐसी अकेली संस्था सामने दिखी जिसने विधायकों की वेतन–वृद्धि को मसला बनाया और इसके खिलाफ राजधानी लखनऊ में गांधी प्रतिमा के समक्ष सांकेतिक अनशन किया. फाउंडेशन ने इस बारे में समाजवादी पार्टी आलाकमान को एक ज्ञापन भी सौंपा है. फाउंडेशन के कर्ताधर्ता मनीष जगन ने कहा कि ये निर्वाचित जनप्रतिनिधि पूंजीवादी व्यवस्था के वाहक और धनलोलुप हैं और कुछ नहीं. श्रमिक और किसान हित के नाम पर राहत और बख्शीश की राजनीति तत्काल बंद होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की करतूतों के कारण विधायकों के वेतन–भत्तों में वृद्धि से सलाना 47 करोड़, 81 लाख 40 हजार रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा. सबसे ज्यादा बोझ पेंशन मद में पड़ेगा. सरकार को उन्हें पेंशन देने के लिए 13 करोड़, 53 लाख, 60 हजार रुपये अतिरिक्त देना होगा. वहीं, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने से छह करोड़, चार लाख, 80 हजार, पेंशन राशि बढ़ाने से 3.90 करोड़ तथा रेलवे कूपन से 3.78 करोड़ रुपये का व्ययभार बढ़ेगा. मनीष जगन कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों के वेतन भत्ते और सुविधाओं के नाम पर जो बढ़ोत्तरी की गई है उसका द सोशलिस्ट फाउंडेशन विरोध करता है और शासन से मांग करता है कि इसे वापस लिया जाए. फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों से भी अनुरोध किया है कि उक्त वेतन, भत्ता, सुविधा बढ़ोत्तरी को लेने से वे इनकार कर दें और अपने जनप्रतिनिधि होने को जनता के समक्ष सार्थकता प्रदान करें.

किसानों को उनकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है, मौसम में परिवर्तन से फसल समूल नष्ट हो गई है, मजदूर की मजदूरी पर दलालों का साया है और बढ़ती महंगाई से दो जून की रोटी जुटा पाना दुश्वार हो गया है, बेरोजगार नौजवान परेशान हैं, उसकी बेरोजगारी उसकी मौत का सबब बन रही है, आम आदमी महंगाई से बेहाल है. ऐसे में मुख्यमंत्री को गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए था. धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए था. मजदूरों की मजदूरी बढ़ानी चाहिए थी. नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए थी. आम आदमी को महंगाई से निजात दिलाना चाहिए था. लेकिन इसके विपरीत समाजवादी होने का दावा करने वाली प्रदेश सरकार ने सफ़ेद खद्दर का कुर्ता पैजामा धारण करने वाले ठेका टेंडर और व्यवसाय से सम्पन्न दोनों हाथों से रकम बटोरते आलीशान गाड़ियों में गनर और समर्थकों से लदे–फदे विचरण करते विधायकों का वेतन–भत्ता और सुविधाएं बढ़ा कर जनता से क्रूर मजाक किया है. लोहिया के अनुयायी होने का दावा करने वाली समाजवादी सरकार को आडंबरवादी बताते हुए फाउंडेशन ने सरकार की जन–विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेशभर में मुहिम चलाने की घोषणा की है. फाउंडेशन ने विधायकों से अनुरोध भी किया है कि वे इस मुहिम में साथ दें और आमजन की आवाज मजबूत करें. उनसे बढ़े हुए वेतन–भत्ते वापस लौटाने की भी अपील की गई है. फाउंडेशन ने कहा है कि जो विधायक इसे वापस करेगा, उसके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के समय फाउंडेशन उनकी मदद के लिए उतरेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

किसानों की हालत भिखमंगों से भी बदतर

देश के किसानों की आर्थिक हालत भिखमंगों से भी बदतर हो गई है. किसानों के लिए निश्चित आय का प्रावधान करने या सरकारी कर्मचारियों के वेतन आयोग की तर्ज पर किसान आय आयोग गठित करने की बातें नेता करते रहे हैं, लेकिन वही नेता विधानसभाओं या संसद में अपना वेतन और सुविधाएं बढ़वा कर मौज करते रहते हैं. किसानों के लिए सुनिश्चित मासिक आय का प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव अर्से से लंबित है. यह सब देखते-देखते देश का हताश किसान समुदाय आत्महत्या का रास्ता चुनने पर विवश होने लगा. विडंबना यह है कि किसानों को देश की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ माना जाता है. बहुत अधिक समय नहीं बीता है. भाजपा की एक किसान रैली में लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि अगर उनका दल सत्ता में आया तो वह किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देने का स्थायी प्रावधान करेंगे. लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार आई भी तो इसकी कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई दे रही. गुजारे की खेती को बचाने का एकमात्र उपाय यही है कि विकसित और धनी देशों की तर्ज पर किसानों को भी प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग दिया जाए. लेकिन सरकारों का ध्यान तो किसानों की जमीनें छीनने पर लगा रहता है. एक किसान परिवार की मासिक आय मात्र दो से तीन हजार रुपये के बीच होती है. किसान परिवार में पांच सदस्यों के साथ-साथ दो पशु भी शामिल कर लिए जाएं तो इस आय में उनका क्या होता होगा, इसकी वीभत्स कल्पना की जा सकती है. छठे वेतन आयोग के बाद सरकारी चपरासी को भी 15 हजार रुपये से अधिक वेतन मिलता है. कितना शर्मनाक है कि देश के नेता एक किसान की कम से कम उतनी भी आय नहीं कर सकते जितना कि एक चपरासी वेतन पाता है. लेकिन नेताओं और नौकरशाहों को शर्म कहां आती है. किसान दिन-रात एक करके भी जितना कमाते हैं, उससे उनके परिवार का महीने भर का खर्च भी नहीं चल पाता. इसका खुलासा खुद सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की रिपोर्ट भी करती है. इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012-13 में देश में कुल 9.02 करोड़ किसान परिवार थे. इनमें से 8.65 करोड़ परिवार ऐसे हैं, जिनकी खेती की आय से महीने भर का घर का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है. किसान परिवारों की महीने में खेती से औसत आय दो से तीन हजार रुपये के बीच है, जबकि उनका कुल उपभोग खर्च साढ़े छह हजार रुपये से अधिक है. चिंताजनक बात यह है कि ऐसी दयनीय स्थिति सिर्फ छोटे किसानों की नहीं, बल्कि उनकी भी है जिनके पास दो से चार हेक्टेयर (करीब पांच से दस एकड़) जमीन है. यह स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है, क्योंकि 63.5 प्रतिशत किसानों की आय का मुख्य स्रोत खेती ही है. ऐसे में इन किसानों का सिर्फ खेती के सहारे गुजारा होना संभव नहीं है. यह रिपोर्ट दिखाती है कि खेती से पर्याप्त आय न होने की स्थिति में देश में 45 प्रतिशत किसान मनरेगा में मजदूरी करने को मजबूर हैं. वहीं 40 प्रतिशत किसानों ने अंत्योदय और बीपीएल कार्ड बनवाए हैं. खेती से कम आय की भरपाई के लिए कुछ किसान गैर-कृषि कार्यों का सहारा भी ले रहे हैं. इस तरह खेती, मजदूरी, पशुपालन और गैर-कृषि कार्य सहित सब साधनों को मिलाकर भी किसान परिवार की औसत मासिक आय छह हजार रुपये नहीं हो पाती है. जहां तक उत्तर प्रदेश की स्थिति है तो अन्य राज्यों की तुलना में यह और भी भयावह है. उत्तर प्रदेश में किसान परिवार की औसत आय मात्र 2,531 रुपये होती है.

सरकार ने कहा, कानून व्यवस्था बदहाल

जहां पुलिस नहीं सुरक्षित, वहां जनता की कैसे हो हिफाजत

दीनबंधु कबीर

तीन वर्ष पूरे होने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी खूब उपलब्धियां गिनाईं और अपनी पीठ खूब ठोकी. खूबी यह है कि इन उपलब्धियों में दुरुस्त कानून व्यवस्था को भी शुमार किया गया. सत्ता मिलते ही नेताओं की खाल इतनी मोटी क्यों हो जाती है, यह आम जनता को समझ में नहीं आता. आम जनता सरकारी आंकड़ों और सरकारी दावों के बीच बुरी तरह उलझ जाती है. सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर है. प्रशासन पर अपराधी हावी हैं. अखिलेश शासन के ढाई साल में ही अपराधियों के हमलों में आधिकारिक तौर पर 69 से अधिक पुलिसकर्मी मारे जा चुके हैं और गंभीर रूप से जख्मी होने वाले में सौ से अधिक पुलिसकर्मी शामिल हैं. जबकि अनधिकृत आंकड़े बताते हैं कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में पुलिस पर 662 हमले हुए जिनमें 225 पुलिसवालों की जानें गईं. अगर यह आंकड़ा सच है तो यह वाकई खौफनाक है. दुरुस्त कानून व्यवस्था के सरकारी दावे के बरक्स जमीनी हकीकत यही है.

अखिलेश यादव को जब पुरस्कार में सत्ता की बागडोर मिली थी तो उन्होंने वादा किया था कि राज्य में कानून व्यवस्था की तस्वीर बदल देंगे. वाकई तस्वीर बदल गई. ढाई साल के कार्यकाल में 622 पुलिस कर्मियों पर हमले हुए. इसमें 69 से अधिक पुलिसकर्मी मारे गए और सैकड़ों घायल हुए. ये आंकड़े तो सरकारी हैं, लिहाजा इनमें अर्ध सत्य हो सकता है. हालात और भी खौफनाक है. हमलों के आंकड़े तो वे हैं, जो मुकदमे दर्ज करवाने के कारण सामने आए. अनगिनत ऐसे मामले हैं, जो किसी न किसी दबाव के चलते दर्ज ही नहीं किए जाते इसलिए सामने नहीं आ पाते. सरकार ने खुद ही विधानसभा में यह स्वीकार किया है कि पुलिस पर हमले बढ़े हैं. फिर सरकार आम जनता को सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकती है. विधानसभा में ही विपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिम्मेदारी से यह बयान दिया है कि इस दरम्यान 662 हमले हुए हैं जिसमें 225 पुलिसवालों की जानें गई हैं. सरकार ने मौर्य के बयान का खंडन नहीं किया है.

भाजपा विधायक सुरेश खन्ना को विधानसभा में दिए जवाब में प्रदेश सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री आजम खान ने बताया कि 15 मार्च 2012 से सितंबर 2014 तक राज्य में पुलिस पर हमले की कुल 622 घटनाएं हुईं. इन सभी मामलों में एफआईआर दर्ज कराकर 3,936 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई. इसके अलावा सितंबर 2014 से लेकर मार्च 2015 तक की अवधि भी पुलिस के लिए अच्छी नहीं रही. इस दौरान भी दर्जनों पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता और अपराधियों के हिंसक हमलों का शिकार होकर होना पड़ा. किसी को जान गंवानी पड़ी तो कई घायल और जलील हुए. हालांकि इनमें से अधिकांश घटनाओं के आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं.

राजकुमार सिंह

सीओ जिआउल हक

प्रतापगढ़ में कुंडा के सीओ जियाउल हक की नृशंस हत्या के साथ कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ना शुरू हुई थीं. इसमें सत्ताधारी दल के वरिष्ठ नेता भी शरीक थे. सीओ की हत्या को सीधे सियासत और धर्म से जोड़ने का तिकड़म रचा गया था. एक वरिष्ठ नेता के इशारे पर फर्जी एफआईआर लिखवाई गई और एक अन्य कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को उसमें अभियुक्त बना दिया गया. अखिलेश को मुंह के बल गिराने के लिए उन्हीं के वरिष्ठ मंत्री ने ऐसी व्यूह रचना की कि अगर मामले की सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया गया होता तो अखिलेश धराशाई हो गए होते और प्रदेश को साम्प्रदायिक उन्माद में धकेल दिया गया होता. लेकिन सीबीआई जांच हुई और सच का पर्दाफाश हो गया. राजा भैया को क्लीन चिट तो मिल गई, लेकिन साजिश के सूत्रधार नेता जितना ऐंठ सकते थे, उतना तो ऐंठ ही लिया. मामले को फर्जी शक्ल देने की कोशिश करने वालों का कुछ नहीं बिगड़ा.

तब से लेकर अब तक सहारनपुर, इटावा, बरेली, इलाहाबाद, फिरोजाबाद और फर्रुखाबाद जैसी तमाम जगहों पर बदमाशों और भीड़ के हमले में 69 पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं. सौ के ऊपर पुलिस वाले घटना में घायल हुए हैं. अब अपराधियों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वे पुलिसवालों पर हाथ उठाते और गोलियां चलाने से नहीं हिचकते. यहां तक कि पुलिस का वाहन रुकवा कर हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी जख्मी हो रहे हैं या मर रहे हैं. फर्रुखाबाद नगर कोतवाली के इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह की सरेआम हुई हत्या ने प्रदेश के लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे. यह घटना लोगों के जेहन में आज भी ताजा है. रायबरेली के दुधवन गांव निवासी इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह फर्रुखाबाद कोतवाली में तैनात थे. 29 नवंबर 2014 को पप्पू उर्फ चंद्रकुमार ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी. ऐसी घटनाओं के बावजूद इन स्थितियों से निपटने के कोई पुख्ता उपाय नहीं किए जा रहे हैं. बस, अखिलेश सरकार सबको सुरक्षा देने का नारा जरूर देती रहती है. बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइनें शुरू की गई हैं, लेकिन जब पुलिस को खुद ही सुरक्षा की दरकार हो तो आम लोगों की हिफाजत कैसे हो. प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री आजम खान ने विधानसभा में यह स्वीकार किया कि इटावा, औरैया, सहारनपुर, ज्योतिबाफुलेनगर, आगरा और लखनऊ के थानों के दरोगा और सिपाहियों पर असामाजिक तत्वों का लगातार हमला हुआ है. कभी मुठभेड़ के लिए कुख्यात रही यूपी पुलिस आज खुद अपराधियों की गोलियों का शिकार बन रही है.

कानून व्यवस्था की बदहाली का मसला विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उठा. लेकिन हमेशा की तरह मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करने की परंपरा निभाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था समाजवादी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है. जबकि उसी सदन में उसी सरकार ने अपराधियों द्वारा पुलिस पर किए जा रहे हमलों की स्वीकारोक्ति कर चुकी थी. तभी विपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राज्य में जंगलराज है. अपराधियों की चांदी है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 662 हमलों में 225 पुलिसवालों की जानें गईं. इससे सरकार में बैठे लोगों की अपराधियों से साठगांठ का पता चलता है. नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के पहले बड़े पैमाने पर हुए साम्प्रदायिक दंगों से स्पष्ट है कि भाजपा-सपा में गुप्त समझौता है. लोकसभा चुनाव के बाद दंगों में अचानक आई कमी इसका प्रमाण है. भाजपा विधानमंडल दल के नेता सुरेश खन्ना ने कानून व्यवस्था के मामले में सरकार पर तीखे हमले करते हुए पुलिस भर्ती में व्यापक धांधली का आरोप लगाया और पुलिस भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की.

पुलिस पर हमले की प्रमुख घटनाएं

वर्ष 2012- लखीमपुर खीरी में एक सब इंस्पेक्टपर की हत्या और सर्विस रिवॉल्वर की लूट. कासगंज में पुलिस स्टेशन पर हमला. प्रदेश भर में तीन पुलिस अधिकारियों पर हमला कर उनके हथियारों की लूट. राजधानी लखनऊ में एक ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमला. मुख्यमंत्री सुरक्षा में लगे एक सर्किल अफसर की खुलेआम पिटाई. राजधानी के सचिवालय बापू भवन के पास बाइक सवार ने ट्रैफिक कांस्टेबल को पीटा. राजधानी में ट्रैफिक विभाग के एक सब इंस्पेक्टर की महानगर में पिटाई. एटीएस के एक कांस्टेबल की सिटी बस में पिटाई. **वर्ष-2013** फैजाबाद में एक होम गार्ड पर हमला. कुंडा के सीओ जियाउल हक की हत्या. फिरोजाबाद के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज पर अज्ञात लोगों द्वारा हमला. सहारनपुर में सीओ सदर उमेश यादव के सामने ही गनर राहुल ढाका को गोलियों से भून डाला गया. इटावा में गुस्साई भीड़ ने सीओ सिटी को सरेराह पीट डाला. बरेली के बभिया में पुलिस चालक अनिरुद्ध यादव को गोली मार कर अपराधी को छुड़ा लिया. सीओ सिविल लाइंस इलाहाबाद सिराज अहमद को हिंसा पर उतारू भीड़ ने दौड़ाया. नैनी में दारोगा और सिपाहियों को पीटा गया. कौशांबी में सिपाही को पीट-पीटकर मारा गया. प्रतापगढ़ के बिहारगंज बाजार में सिपाही को गिराकर मारा गया. प्रतापगढ़ में सिटी चौकी के सिपाही अरविंद तिवारी को पीटने के बाद खौलता तेल डाल दिया गया. **वर्ष 2014**-फिरोजाबाद में दो सिपाहियों की गोली मारकर हत्या. फर्रुखाबाद के कोतवाल राजकुमार सिंह की पप्पू उर्फ चंद्रकुमार ने गोली मारकर हत्या कर दी.

वर्ष 2015- वकीलों द्वारा इलाहाबाद कचहरी परिसर में दारोगा को दौड़ाकर पीटा गया. एक कांस्टेबल को गोली मारी गई. फिरोजाबाद में दो सिपाहियों पर हमला कर उनके हथियार लूटे गए. रामपुर डिस्टिलरी में दो आबकारी सिपाहियों की हत्या कर दी गई. लखनऊ में पीजीआई थाना के चौकी इंचार्ज और एक सिपाही के साथ मारपीट. ■

feedback@chauthiduniya.com

लोक सेवा आयोग बना धंधेबाजों का अड्डा

यूपी की साख पर सवाल

मृत्युंजय दीक्षित

बिहार बदनाम जरूर है, पर उत्तर प्रदेश में परीक्षा प्रणाली पूरी तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुकी है. कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं बची है जो पूरी तरह से दुरुस्त हो. प्रशासनिक शुचिता पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, दूसरी ओर छात्रों व विभिन्न नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य भी दांव पर लग गया है. साथ ही प्रदेश की शिक्षा प्रणाली की साख भी दांव पर लग गई है. आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली की जग-हंसाई हो रही है.

अभी कुछ समय पूर्व समाप्त हुई माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटर व हाईस्कूल की परीक्षाओं में जमकर नकलबाजी हुई. मीडिया बिहार पर ध्यान दिए रहा और उत्तर प्रदेश की तरफ आपराधिक उपेक्षा बरतता रहा. हालात यह थे कि यूपी के विद्यालयों में बकायदा ब्लैक-बोर्ड पर प्रश्नपत्र हल करवाए गए. नकल माफियाओं का धंधा 100 करोड़ से अधिक का हो गया है. टीवी चैनलों में उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में हुई नकल केवल चर्चा में निपट गई. कुछ अखबारों में संपादकीय जरूर लिखे गए. नकल का आलम यह रहा कि दिखावे के लिए जब सख्ती की गई तो बहुत से केंद्रों की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं. पेपर लीक होना तो प्रदेश में अब आम बात हो गई है. अति-आधुनिक मोबाइल संसाधनों के चलते तो यह सब और आसान हो गया है. नकलयुक्त शिक्षा व परीक्षा प्रणाली के कारण आज युवा का भविष्य अंधकारमय और चौपट हो रहा है. आज बोर्ड का परीक्षार्थी बिना किसी भय व चिंता के परीक्षा देने जाता है क्योंकि उसे पता है कि वह कम से कम समाजवादी सरकार में तो फेल नहीं ही होने जा रहा है, साथ ही नकल का भी जुगाड़ हो ही जाएगा.

अब यह नकल रोग इतना गहरा गया है कि यह सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं पर भी छाने लगा है. अभी हाल ही में यूपी पीसीएस की 2015 की परीक्षा का पर्चा 5 लाख रुपये में लीक हो गया. इससे पहले वर्ष 1992 में आईएएस-प्री का पेपर आउट हुआ था. विभिन्न प्रशासनिक और विभागीय पदों पर अधिकारियों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1937 में हुई थी. तब से अब तक कभी पीसीएस परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक नहीं हुआ था. वर्तमान में लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर अनिल कुमार यादव विराजमान हैं, जिन पर समाजवादी सरकार काफी मेहरबान रहती है. वे हमेशा विवादों में रहते हैं. अनिल यादव के कार्यकाल में दो परीक्षाओं के परिणाम संशोधित हो चुके हैं और यह काफी विवादित भी रहे हैं. इस बार पर्चे लीक होने से अभ्यर्थियों का समय, पैसा और विश्वास सबकुछ टूटा है. पीसीएस की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी लगातार कड़ी मेहनत करते हैं तथा फीस व किताबों आदि के लिए अपने से बड़ों पर निर्भर रहते हैं. उनका एक सपना होता है. परीक्षार्थी दूरदराज के क्षेत्रों से परीक्षा देने के लिए केंद्रों तक पहुचते हैं. उनके आवास व ठहरने की भी समस्या होती है. बड़ी जद्दोजहद के बाद वह परीक्षा भवन में प्रवेश करता है. लेकिन परीक्षा देने के बाद उसे पता चलता है कि प्रश्नपत्र तो पहले ही लीक हो गया था. आज लोकसेवा आयोग मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हस्तक्षेप के बाद लीक हुई परीक्षा को दोबारा कराने को तैयार तो हो गया है लेकिन पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर लीक होने के पीछे लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष ही जिम्मेदार है. उसे बर्खास्त करने के बाद ही दोबारा परीक्षा होनी चाहिए. लेकिन ऐसे कारनामों के लिए

अनिल यादव जैसे लोगों को सजा नहीं मिलती. पीसीएस का पर्चा लीक होने के बाद अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समेत कई संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया और आयोग के चेयरमैन अनिल यादव का पुतला भी फूंका. यह लगातार जारी है. लेकिन इस पर सरकार का ध्यान नहीं जाता. आज सोशल मीडिया सशक्त मीडिया बनकर उभरा है. इसका नकारात्मक इस्तेमाल भी हो रहा है. परीक्षा का पर्चा पहली बार इलाहाबाद में व्हाटस-एप पर देखा गया जो बाद में पूरी तरह से फैल गया. आज यह सोशल मीडिया का ही प्रभाव है कि आडियो-वीडियो, फोटो अथवा कोई भी किसी भी प्रकार का मैसेज समूह में बड़ी आसानी से फैलाया जा सकता है. जब तक मैसेज को डिलीट करवाया जाए तब तक वह अपना काम कर चुका होता है. यही कारण है कि व्हाटस-एप पर पेपर लीक होते ही पेपर की फोटो वायरल हो गयी. बड़ी संख्या में पेपर लीक होने के कारण एसटीएफ को मुख्य साजिशकर्ता तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है. एसटीएफ दावा कर रही है कि इस मामले में अब तक परीक्षा केंद्र के नियंत्रक सहित तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. लेकिन अभ्यर्थियों का एक बड़ा समूह एसटीएफ की दलीलों को मानने से इंकार कर रहा है. उनका मत है कि इतने बड़े कांड को केवल दो-तीन लोग अंजाम नहीं दे सकते.

बहरहाल, नकल व लीक के इस गोरखधंधे का सबसे दुखद पहलू यह है कि उसी दिन आयोजित हो रही भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की भर्ती परीक्षा में भी सेंधमारी हो गई. बरेली में बारादरी व किलाथाना क्षेत्र के दो परीक्षा केंद्रों पर तीन लोगों को हिरासत में लिया गया. ये लोग परीक्षा में नकल करवाने का प्रयास कर रहे थे. ये किसी अन्य के नाम पर परीक्षा देकर पेपर हल करवाना चाह रहे थे. समाजवादी शासन में ही यह सबकुछ संभव हो रहा है. यहां अब कुछ भी सुरक्षित और स्वच्छ नहीं रह गया है. परीक्षा भ्रष्टाचार का प्रथम पायदान बनकर रह गई है. चारों ओर बेरोजगारी का वातावरण है, युवाओं में घोर निराशा है, ऐसे में भ्रष्टाचार उनका सपना चूर कर रहा है. यह सब कुछ सरकार चाहती तो रोक सकती थी. लेकिन प्रदेश में कानून का राज रह ही नहीं गया है.

यूपीपीएससी के सचिव रिजवानुर रहमान का कहना है कि आयोग ने प्रश्नपत्र के लीक होने के आरोपों की प्रारंभिक जांच कराई और प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया. मामले की जांच कर रही प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार तो किया लेकिन वह आयोग की सफाई में प्रवक्ता बन कर सामने उतर आई. एसटीएफ ने आयोग को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे डाला और कहा कि इस लीक में आयोग की कोई भूमिका नहीं है. इससे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव आलोक रंजन समेत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी बुलाई थी, जिसमें पुलिस महानिदेशक एके जैन तथा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव भी मौजूद थे. प्रश्नपत्र लीक हो जाने के मामले की जांच कर रही एसटीएफ ने इस मामले में विशाल, ज्ञानेन्द्र तथा जय नामक व्यक्तियों को गिरफ्तार करके राज्य लोक सेवा आयोग को क्लीन चिट दे दी. एसटीएफ के पुलिस महानिरीक्षक सुजीत पांडेय ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक मामले में आयोग अथवा सरकार के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी का हाथ नहीं है. यह स्थानीय मामला है और सारा कारनामा गिरफ्तार कर लिए गए तीनों युवकों का है, जिन्होंने पूछताछ में बताया है कि उन्होंने यह योजना दो दिन पहले बनाई थी. तीनों युवकों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उन्होंने परीक्षा शुरू होने से लगभग डेढ़ घंटे पहले पर्चा खोला और उसकी तस्वीर लेकर उसे व्हाट्स-एप पर डाल दिया. प्रश्नपत्र लखनऊ के आदर्श भारतीय विद्यालय कॉलेज से लीक किया गया था. प्रश्नपत्र एक-एक लाख रुपये में बेचे गए थे. लेकिन कितने अभ्यर्थियों को बेचे और भेजे गए, इस बारे में एसटीएफ बताने में असमर्थ है. गिरफ्तार विशाल, आदर्श भारतीय विद्यालय कालेज के प्रबंधक बलदेव मेहता का बेटा है. इस कालेज को पहली बार पीसीएस परीक्षा का केंद्र बनाया गया था. इस मामले में पकड़े गए दो अन्य लोगों ज्ञानेन्द्र और जय सिंह अनुबंध पर रखे गए थे, वे कक्ष निरीक्षक के तौर पर ड्यूटी कर रहे थे.

एसटीएफ की बचकानी बातें सुन कर ही इसके पीछे बैठे कद्दावर तत्वों के बारे में संकेत मिलता है. आयोग के ही एक अधिकारी ने कहा कि आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के बगैर पर्चा लीक हो ही नहीं सकता. इसीलिए नाराज परीक्षार्थी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बर्खास्तगी की मांग करते हुए प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं. प्रदेश के सभी विपक्षी दलों ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की है. सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने पीसीएस परीक्षा पर्चा लीक मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने के सम्बन्ध में राजभवन जा कर राज्यपाल राम नाइक को ज्ञापन दिया है. ज्ञापन में आईजी एसटीएफ द्वारा जांच शुरू होते ही मामले को स्थानीय बताने और आयोग के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों को क्लीन चिट देने, प्रेस कांफ्रेंस में आयोग की भूमिका नहीं होने की बात बार-बार कहने और आयोग द्वारा लम्बे समय तक लीक की घटना को नकारते रहने जैसे 22 बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है. डॉ. ठाकुर ने कहा है कि चूंकि सरकार और उसके नुमाइंदे शुरू से ही असली अभियुक्तों को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, इसलिए सच्चाई तक पहुंचने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है.

पीसीएस परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी अखिलेश ने बताया कि प्रश्नपत्र बहुत आसान था. परीक्षार्थी रेखा ने कहा कि हमें उस गुनाह की सजा मिल रही है, जो हमने किया ही नहीं. यूपी पीसीएस 2015 के लिए हुई प्रारम्भिक परीक्षा का पहला प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले आउट हो गया था. वह पर्चा व्हाट्स-एप के जरिए लीक हुआ था. उस पर भेजे गए प्रश्न पत्र का पीसीएस परीक्षा के पर्चे से मिलान किया गया तो प्रश्नपत्र लीक होने की पुष्टि हुई. पर्चा लीक होने की बात सार्वजनिक होते ही पुलिस महानिदेशक एके जैन ने मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी थी. प्रदेश की प्रशासनिक सेवाओं के लिए होने वाली इस परीक्षा में कुल साढ़े चार लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और उसके लिए प्रदेश में कुल 917 परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे. अकेले राजधानी लखनऊ में 148 परीक्षा केंद्रों पर 70 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश के 12 महापुरुषों को मिल चुका है भारत रत्न

भारत रत्न महामना और वाजपेयी

वैष्णवी वंदना

महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिलने के साथ ही अब उत्तर प्रदेश से जुड़े भारत रत्नों की संख्या एक दर्जन हो गई है. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 27 मार्च और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को 31 मार्च को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया. यह पहली बार हुआ कि देश के राष्ट्रपति ने किसी हस्ती के घर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अटल के घर जाकर उन्हें सम्मानित करना इतिहास में दर्ज हो गया है. महामना के परिजनों को राष्ट्रपति भवन में यह भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया. भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है. इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी. महामना और अटल को भारत रत्न दिए जाने के साथ ही यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले लोगों की संख्या 45 पहुंच गई है. यह सम्मान हासिल करने में उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी है. यहां से अब तक 12 लोगों को यह सम्मान मिल चुका है. उत्तर प्रदेश से अब तक महामना मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रो. सीएन आर राव, बिस्मिल्लाह खान, पंडित रवि शंकर, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद वल्लभ पंत, डॉ. सर्वपल्ली राधा कृष्णन, डॉ. भगवान दास भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं.

अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषण, कविता और राष्ट्रीय-राजनीतिक-सामाजिक समझ के लिए विख्यात हैं. श्री वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के छावनी में हुआ था. उनके पिता पं. कृष्ण बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के प्राचीन धार्मिक स्थान बटेश्वर के रहने वाले थे. अटल ने राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश को अपना कर्मस्थल बनाया था. 1957 में जनसंघ के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने बलरामपुर सीट से चुनाव जीता था. उस समय यह जिला गोंडा में शामिल था. वे लखनऊ सीट से लगातार पांच बार और ऐसे 10 बार लगातार सांसद रहे हैं. अटल बिहारी वाजपेयी तीन बार देश के प्रधानमंत्री रहे. वे 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. अटल दो बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए. वे विपक्ष में भी उतने ही लोकप्रिय रहे, जितना पक्ष में. अटल बिहारी वाजपेयी बहुमुखी प्रतिभा से सम्पन्न हैं. वह न केवल एक राजनीतिज्ञ रहे, बल्कि वे एक महान कवि भी हैं. उन्होंने ढेरों कविताएं लिखीं. वे पत्रकार के रूप में भी सक्रिय रहे. वे इतने उच्च कोटि के वक्ता रहे हैं कि संसद में उनके भाषणों को पंडित नेहरू जैसे राजनीतिक विरोधियों ने भी सराहा. वाजपेयी के नेतृत्व की क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे राजग सरकार के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर पांच साल बिना किसी समस्या के पूरे किए. उन्होंने 24 दलों के गठबंधन से सरकार बनाई थी जिसमें 81 मंत्री थे. अटल उन चंद लोगों में शामिल रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी. वे वर्ष 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे. एक पत्रकार के तौर पर उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर-अर्जुन आदि पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन किया और समसामयिक मामलों पर अपने विचार रखे. वर्ष 1977 में पहली बार वाजपेयी गैर कांग्रेसी विदेश मंत्री बने थे. उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी. वह 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे और इस दौरान संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया. वे पहले ऐसे विदेश मंत्री थे, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया था.

महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को संगम नगरी प्रयाग के अहियापुर (लालडिग्गी) मोहल्ले में साधारण से ब्राह्मण परिवार में हुआ था. इनके घर को अब भारती भवन के नाम से जाना जाता है. उनके पिता ब्रजनाथ और माता श्रीमति मूना देवी के छह बेटे और दो लड़कियां थीं. इन सब में मदन मोहन ही विशेष रूप से प्रतिभाशाली सिद्ध हुए. महामना का 16 साल की उम्र में 1978 में मिर्जापुर की कुंदन देवी से विवाह हुआ. उनकी पत्नी भी हिंदी और संस्कृत भाषा की जानकार थीं. मालवीय जी के पिता सनातनी ब्राह्मण थे और वे भगवत गीता का पाठ करके ही अपने परिवार का जीवनयापन करते थे. लिहाजा महामना की शिक्षा-दीक्षा बेहद परेशानियों के बीच हुई. मालवीय न सिर्फ एक सच्चे देशभक्त थे बल्कि वे सफल वकील, दार्शनिक, शिक्षाविद, प्रभावशाली समाज सुधारक, जुझारू पत्रकार और अध्यापक होने के साथ-साथ प्रभावशाली वक्ता भी थे. उन्होंने 4 फरवरी 1916 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी. 1919 में वे वहां के कुलपति बने और लगातार 20 साल तक बने रहे. वे दीवानी के बड़े वकील भी थे. पं. मदन मोहन मालवीय ने मात्र 40 रुपये महीने से नौकरी शुरू की थी. स्कूल में अध्यापक की नौकरी से देश के बड़े वकील और फिर 20 साल तक बीएचयू के कुलपति के रूप में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी.

राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था. वे फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के सबसे बड़े बेटे थे. 40 साल की उम्र में वह देश के प्रधानमंत्री बने. संसद में पहुंचने के लिए उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को ही अपने राजनीतिक करियर से जोड़ा. परिवार की पारंपरिक अमेठी सीट से वे चुनाव लड़कर सदन में पहुंचे. गांधी परिवार से जुड़ा होने की वजह राजीव का जनता में जुड़ाव था, लेकिन इससे इतर उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने कामों से अलग पहचान बनाई. भारत में कम्प्यूटर लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है. राजीव गांधी को आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा जाता है. राजीव 1981 के बाद 1984 में दूसरी बार और 1989 में तीसरी बार सदन में पहुंचे थे. 1991 लोकसभा चुनाव के दौरान तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में लिट्टे के आत्मघाती हमले में उनकी मौत हो गई थी. उन्हें 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया.

1971 में भारत रत्न से सम्मानित इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 में इलाहाबाद में हुआ था. उनके पिता देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और माता कमला नेहरू थीं. पति फिरोज गांधी के निधन के बाद रायबरेली की रिक्त सीट पर इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा. इसके बाद वह आजीवन रायबरेली का प्रतिनिधित्व करती रहीं. वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यहां से ही सांसद हैं. इंदिरा गांधी लगातार तीन बार 1966 से 1977 तक देश की प्रधानमंत्री रहीं. 1980 में वे चौथी बार देश की प्रधानमंत्री बनीं. उसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई. वे भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं हैं. 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ कर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के निर्माण का पूरा श्रेय इंदिरा गांधी को ही दिया जाता है.

देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न मिला था. आजादी के बाद 1952 में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ. इसमें वे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की फूलपुर सीट से पहली बार चुने गए थे. इसके बाद 1957 और 1962 में जवाहरलाल नेहरू दोबारा विजयी हुए. 1916 में लखनऊ अधिवेशन में वे सर्वप्रथम महात्मा गांधी के संपर्क में आए. 1947 में वे आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने. नेहरू ने भारत के पुनर्गठन के रास्ते में उभरी हर चुनौती का समझदारी पूर्वक सामना किया. उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया और तीन लगातार पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया. नेहरू ने भारत की विदेश नीति के विकास में भी प्रमुख भूमिका निभाई.

साल 1961 में भारत रत्न से सम्मानित पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म 1 अगस्त, 1882 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था. उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की और 1906 में प्रैक्टिस के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में काम करना शुरू किया. 1921 में सामाजिक कार्यों में अधिक भागीदारी और देश के स्वतंत्रता संग्राम में पूर्ण रूप से काम करने के लिए उन्होंने वकालत छोड़ दी. हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करवाने में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान था. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के नेता होने के साथ-साथ पुरुषोत्तम दास जी हिंदी के अनन्य सेवक, कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक भी थे. आजादी के बाद पुरुषोत्तम दास टंडन ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के प्रवक्ता के रूप में 13 साल तक काम किया. 31 जुलाई, 1937 से लेकर 10 अगस्त, 1950 तक के लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने विधान सभा को कई बार संबोधित किया.

एक समय हिंदी लिपि के लिए गांधीजी समेत कई अन्य महापुरुष हिंदुस्तानी भाषा जो कि हिंदी और उर्दू का मिश्रण थी उसे मान्य बनाना चाहते थे. लेकिन टंडन जी ने देवनागरी को ही हिंदी की मानक लिपि मानने पर जोर दिया. इस बात पर कांग्रेस में जबरदस्त बहस हुई और अंत में हिंदी राष्ट्रभाषा और देवनागरी राजलिपि घोषित हुई. इसके लिए पुरुषोत्तम दास जी ने करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर और समर्थन पत्र भी एकत्र किए थे. 1961 में हिंदी भाषा को देश में अग्रणी स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाने के लिए उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया. 23 अप्रैल, 1961 को उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया था.

गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे. उनका जन्म 10 सितंबर, 1887 को वर्तमान में उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित खूंट गाव में हुआ था. साल 1905 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और 1909 में उन्होंने कानून की परीक्षा पास की. काकोरी मुकदमे ने एक वकील के तौर पर उन्हें पहचान दी और उन्हें राष्ट्रीय प्रतिष्ठा मिली. 1957 में भारत रत्न पाए गोविंद बल्लभ पंत को राजनीतिक रूप से पिछड़े माने जाने वाले पहाड़ी इलाकों को देश के राजनीतिक मानचित्र पर जगह दिलाने का श्रेय जाता है. साल 1937 में पंत जी संयुक्त प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और 1946 में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने. 10 जनवरी 1955 को उन्होंने भारत के गृह मंत्री का पद संभाला. साल 1957 में गणतंत्र दिवस पर महान देशभक्त, कुशल प्रशासक, सफल वक्ता, तर्क के धनी और उदारमना पंत जी को भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से विभूषित किया गया था. हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने में गोविंद वल्लभ पंत का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा. सात मार्च 1961 को उनका निधन हो गया.

शहनाई सम्राट बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न मिला. शहनाई की गूंज केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहुंचाने का श्रेय उन्हीं को जाता है. 21 मार्च 1916 को बिहार में बक्सर जिले के डुमरांव राज के मुलाजिम पैगंबर बख्श मियां के घर उनका जन्म हुआ था. 21 अगस्त 2006 को उनका निधन हुआ. बिस्मिल्लाह खान को साल 1956 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, 1968 में पद्म विभूषण, 1980 में पद्म भूषण और 1992 में तराल मौसिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. धर्म और जाति जैसे बंधन से ऊपर उठकर बिस्मिल्लाह खान सरस्वती, विद्या और कला के सच्चे उपासक थे. वह पांच वक्त की नमाज अदा करते थे. वाराणसी के बाबा विश्वनाथ मंदिर समेत अन्य धर्मस्थलों पर शहनाई बजाने और अभ्यास करने वाले बिस्मिल्लाह खान सर्व-धर्म समभाव की मिसाल थे.

सर्वपल्ली डॉ. राधा कृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुपति में हुआ था. अपने जीवन के 40 साल उन्होंने एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे. काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महामना मदन मोहन मालवीय के साथ उन्होंने काफी योगदान दिया. इनके जन्म दिवस 5 सितंबर को पूरा देश शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है. ब्रिटिश काल में इनको सर की उपाधि से नवाजा गया और 1931 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. 17 सितंबर 1939 को महामना मालवीय के बाद डॉ. राधा कृष्णन ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चौथे कुलपति बने थे.

डॉ. भगवान दास का जन्म 12 जनवरी 1869 को वाराणसी में हुआ था. 1955 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया. डॉ. भगवान दास ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर सेंट्रल हिंदू स्कूल बनाने में काफी मदद की थी. देश में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इनका काफी योगदान रहा है.

दुनियाभर में सितार को पहचान दिलाने वाले पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को काशी में हुआ था. पंडित रविशंकर ने 1936 से 1941 तक मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खान से तालीम हासिल की थी. उन्हें 1999 में भारत रत्न दिया गया था. काशी के ध्रुपद मेले में पंडित रविशंकर तुलसी घाट पर सितार बजाया करते थे.

प्रो. सीएन आर राव का जन्म 30 जून 1934 को बेंगलुरु में हुआ था. देश के रसायनविदों में प्रोफेसर राव का नाम सर्वोपरि है. 4 फरवरी 2014 को इन्हें भारत रत्न के रूप में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला. प्रोफेसर राव ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही रसायनशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी. इन्होंने कई विश्वविद्यालयों से डॉक्टर मानद की उपाधि प्राप्त की है. प्रोफेसर राव ने 1500 से अधिक शोध पत्र और 45 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड

महिला जासूस ने आईएएस एकेडमी पर लगाए गंभीर आरोप

राजकुमार शर्मा

देश के सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर करीब छह महीने तक अकादमी परिसर में प्रशिक्षु आईएएस के तौर पर जासूसी करने वाली महिला के गायब होने के बाद हड़कम्प मचा हुआ था. अकादमी, मसूरी की सुरक्षा में यह सेंध माना जा रहा था, लेकिन यह वहां के अधिकारियों का ही कारनामा था. यह सबकुछ कहना है आरोपी महिला रूबी चौधरी का. वह अचानक से 2 अप्रैल को मीडिया के सामने आकर अपने ऊपर लगे आरोंपो पर सफाई दी और संस्थान पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. रूबी चौधरी ने डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ही उसकी यहां रहने मदद की. उसके मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर ने उससे पांच लाख रुपये लेने के बाद अकादमी में उसके रहने की व्यवस्था की थी. रूबी ने बताया कि इस बारे में संस्थान के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर से लेकर कई बड़े अधिकारियों को पता था. डिप्टी डायरेक्टर ने ही उसे आई कार्ड उपलब्ध करवाया था. रूबी ने बताया कि पिछले साल जुलाई में दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल समारोह के दौरान डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन से मुलाकत हुई थी.

रूबी ने कहा कि जैन ने उसे बताया कि अकादमी की लाइब्रेरियन जल्द सेवानिवृत्त होने वाली है. इस पद पर रूबी को नौकरी मिल सकती है. कई दौर की बातचीत के बाद सौरभ जैन ने इस नौकरी के बदले 20 लाख रुपये की मांग की. रूबी ने पति और परिवार की मदद से पांच लाख रुपये जमा किए. आरोप है कि पहली किस्त में सवा लाख रुपये डिप्टी डायरेक्टर को उनके ऑफिस में दिए, जबकि पौने चार लाख मसूरी के लाइब्रेरी चौक पर दिए. इसी बीच जैन ने अकादमी में प्रवेश के लिए फर्जी आई कार्ड बनाकर उसे दिए. वह कोई जासूस नहीं है और न ही कोई अपराधी है. वह दो दिनों से एसपी सिटी के संपर्क में है. उसने यह भी आरोप लगाया कि उसे मुंह बंद करने के लिए पांच करोड़ का ऑफर दिया जा रहा था. रूबी ने मीडिया के माध्यम से मांग की कि इस मामले में जो भी दोषी है उन्हें सजा दी जाए. रूबी ने कहा अगर मैं दोषी हूं तो मझे भी दंड मिलना चाहिए. उसने संस्थान के अधिकारियों के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उससे संस्थान के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है. मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धू ने एसआईटी का गठन किया है. सीबीसीआईडी की एसपी शाजिया अंसारी को इसका प्रभारी बनाया गया है.

आरोपी फर्जी महिला आईएएस

रूबी चौधरी ने डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ही उसकी यहां रहने मदद की. उसके मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर ने उससे पांच लाख रुपये लेने के बाद अकादमी में उसके रहने की व्यवस्था की थी. रूबी ने बताया कि इस बारे में संस्थान के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर से लेकर कई बड़े अधिकारियों को पता था. डिप्टी डायरेक्टर ने ही उसे आई कार्ड उपलब्ध करवाया था.रूबी ने बताया कि पिछले साल जुलाई में दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल समारोह के दौरान डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन से मुलाकत हुई थी.

उधर, अकादमी के संयुक्त निदेशक डी नरियाला ने बताया कि रूबी चौधरी दो बार एकेडमी परिसर में आई थी. वह सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में ठहरी थी. गार्ड देव सिंह को निलंबित कर आंतरिक जांच शुरू कर दी है. मामला यह है कि एक युवती अकादमी की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर करीब छह महीने तक अकादमी परिसर में प्रशिक्षु आइएएस के तौर पर रहती रही, किसी को इसकी भनक नहीं लगी. युवती अत्यंत महत्वपूर्ण व गोपनीय स्थानों पर खुलेआम घूमती रही और रहस्यमय अंदाज में गायब हो गई. अकादमी प्रशासन को इसका पता तब चला, जब युवती गायब हो गई.

यह पुरा मामला अकादमी की रेकी का माना जा रहा था. पुलिस व खुफिया एजेंसियां युवती की तलाश में जुट हुई थीं. मामले की जानकारी मिलते ही अकादमी के सुरक्षा अधिकारी सत्यवीर सिंह ने मसूरी कोतवाली में प्राथमिक सूचना दर्ज कराई. अकादमी में छह माह से रूबी चौधरी पुत्री सत्यवीर सिंह निवासी ग्राम कुटबा जिला मुजफ्फरनगर (उप्र) बतौर प्रशिक्षु आइएएस रह रही थी. आरोप है कि वह फर्जी दस्तावेज बनाकर स्वयं को प्रशिक्षु आइएएस अधिकारी व लाईब्रेरी कर्मचारी बताते हुए सितंबर-2014 में यहां प्रवेश किया था. लेकिन अब उसके सामने आने के बाद मामला कुछ और ही नजर आ रहा है. दूसरी ओर, रूबी चौधरी के पति वीरेंद्र मलिक का कहना है कि उनकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. वीरेंद्र ने कहा कि शादी के वक्त उन्हें नहीं पता था कि रूबी की आईएएस की ट्रेनिंग फर्जी है. अब तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है ■

feedback@chauthiduniya.com

> मुजफ्फरनगर की ताजरियान पर उसके देवर ने एसिड से हमला किया था. बाजार से घर लाने के बजाए उसने गाड़ी खेत में घुमा कर उसका शारीरिक शोषण करने की कोशिश की. बचने के लिए शोर मचाया तो देवर ने मुंह पर तेजाब डाल दिया. ससुराल पक्ष वाले केस वापस लेने को कहते हैं. पुलिस भी कार्रवाई करने के लिए पैसे की मांग करती है. वह सरकार द्वारा मिली राहत राशि से अपना केस मजबूती से लड़कर दोषियों को सजा दिलाना चाहती हैं.

तेजाब के जख्म पर अखिलेश का मरहम

वैष्णवी वंदना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तेजाब के हमलों में शिकार हुई युवतियों को तीन-तीन लाख रुपये का चेक देकर उनके जख्मों और आजीवन रिसते अंतर्मन के घाव पर मरहम लगाने की कोशिश की है. अखिलेश ने यह आश्वासन भी दिया कि उनके इलाज के लिए जितनी भी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी, वह खर्च की जाएगी. एसिड हमलों की पीड़ितों को अब सरकारी अस्पतालों में इधर-उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पीड़ितों को एक परिचय पत्र भी जारी किया है जिसे दिखाकर वे किसी भी सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज करा सकेंगी. साथ ही उन्होंने एसिड अटैक की पीड़ितों के उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों को भी निर्देश दिया गया है कि उपचार में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि तेजाबी हमलों का शिकार हुई अन्य पीड़िताओं की भी पहचान की जा रही है और चेक के माध्यम से उनके घरों पर सहायता राशि भेजी जाएगी. एसिड अटैक पीड़ितों की दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी घटनाएं सभ्य समाज के लिए कलंक हैं. उन्होंने पीड़ित महिलाओं-लड़कियों को तीन-तीन लाख रुपये का चेक प्रदान करते हुए कहा कि यह सहायता सभी पीड़ितों को फिलहाल सामान्य रूप से दी गई है. विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने पर और मदद की जाएगी. मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका गठन बहुत ही कम समय में हुआ है. इस कोष के गठन के लिए उन्होंने सांसद डिम्पल यादव तथा महिला कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव रेणुका कुमार को विशेष रूप से धन्यवाद दिया.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस सम्मान कोष हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि इस कोष की स्थापना महिला सशक्तीकरण और उनके आर्थिक स्वावलम्बन के लिए की जा रही है. इसके माध्यम से विभिन्न अपराधों से पीड़ित महिलाओं, बालिकाओं को आर्थिक सहायता एवं चिकित्सा सुविधा देने की भी व्यवस्था की गई है. महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से स्थापित इस कोष में सरकार की नियमित बजट व्यवस्था के अतिरिक्त जनता की सहभागिता एवं सहयोग की व्यवस्था भी परिकल्पित की गई है. जनसामान्य द्वारा भी इस कोष में अपना योगदान किया जा सकता है.

मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों अपने सरकारी आवास पर आयोजित उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अंतर्गत एसिड हमले की पीड़िताओं से मुलाकात की, उनका दुख बांटा और उनसे बातचीत की. अखिलेश ने उन युवतियों के लिए आर्थिक सहायता का वितरण किया, रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार दिए तथा महिला सम्मान कोष की वेबसाइट का शुभारम्भ किया. मुख्यमंत्री द्वारा किया गया यह प्रयास स्वागतयोग्य एवं सराहनीय है. मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के भावनात्मक पहलू को विचार में रख कर ये सारी सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही है. लेकिन उनकी पीड़ा केवल आर्थिक मदद से दूर होने वाली नहीं है. पीड़िताओं का कहना है कि उन्होंने जो मानसिक और शारीरिक यातनाएं झेली हैं वह केवल पैसे से कम नहीं होने वाली. उनकी वीरान पड़ी जिन्दगी को नई दिशा मिले इसके लिए सरकार को चाहिए कि उन जैसी पीड़ितों को रोजगार मुहैया कराया जाए ताकि वह आत्मनिर्भर होकर समाज में सिर उठा कर अपना जीवन व्यतीत कर सकें. साथ ही जिन लोगों ने इन अमानवीय कृत्यों को अंजाम दिया, उनकी शिनाख्त कर उन पर कठोरतम कार्रवाई भी सरकार की प्राथमिकता में होनी चाहिए. समारोह में पहुंची पीड़ित महिलाओं में से ज्यादातर को गुनहगारों को सजा न मिल पाने का दर्द है. सभी को इस बात की टीस है कि अपराधी बाहर घूम रहे हैं और उन्हें बिना किसी कसूर के, मजबूरन समाज से मुंह चुराकर रहना पड़ रहा है.

अपने चेहरे को लेकर महिलाएं बहुत ही सजग रहती हैं. महिलाएं भले ही जीवन के अंतिम पड़ाव पर ही क्यों न हों, चेहरे पर एक दाग भी वे बर्दाश्त नहीं करतीं. ऐसे में उन पीड़ितों की बेचैनी का अंदाजा लगाया जा सकता है जो तेजाबी हमलों का शिकार हुई हैं. बिना किसी कसूर के मिली कुरूपता के साथ जीवन गुजारना कितना मुश्किल होता है, इसका दर्द उन पीड़ितों से ज्यादा कौन जान पाएगा जो यह दंश जिन्दगी भर झेलने को विवश हैं. उनका दर्द तब और बढ़ गया जब वे अपने सगे और समाज द्वारा बहिष्कृत कर दी गईं. कुछ ऐसी पीड़ितांए भी हैं जो बिना हार माने अपनी लड़खड़ाती जिंदगी को फिर से संभालने की जिद लेकर चल रही हैं. कार्यक्रम के दौरान गोरखपुर से आईं संध्या देवी के आंसू थम नहीं रहे थे. उनके पिता ने रिक्शा चालक होते हुए भी अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज देकर शादी की थी. लेकिन पति की शराब पीने की आदत से परेशान होकर पिता के घर रहने लगी. एक दिन रात के अंधेरे में चेहरे पर किसी ने कुछ फेंका और पूरा चेहरा बदल गया. घटना को दो साल होने वाले हैं, घाव अभी तक भरे नहीं हैं, मवाद आता रहता है. रोकर कहती हैं, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पैसे तो दे दिए, लेकिन इससे अपने तीन बच्चे कैसे पालूंगी.

इसी तरह मुजफ्फरनगर की ताजरियान पर उसके देवर ने एसिड से हमला किया था. बाजार से घर लाने के बजाए उसने गाड़ी खेत में घुमा कर उसका शारीरिक शोषण करने की कोशिश की. बचने के लिए शोर मचाया तो देवर ने मुंह पर तेजाब डाल दिया. ससुराल पक्ष वाले केस वापस लेने को कहते हैं. पुलिस भी कार्रवाई करने के लिए पैसे की मांग करती है. वह सरकार द्वारा मिली राहत राशि से अपना केस मजबूती से लड़कर दोषियों को सजा दिलाना चाहती हैं.

अलीगढ़ की प्रिया वर्मा अपनी आपबीती बताते हुए अभी भी सहम जाती हैं. प्रिया वर्मा के लिए 17 जुलाई 2014 का वह दिन कभी नहीं भूलने वाला दिन बन गया है. जब एक सनकी और एकतरफा प्यार का मारा 45 साल के अधेड़ ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक कर उसका जीवन अंधकारमय बना दिया. प्रिया भी चाहती हैं कि सरकार उनके जैसी पीड़ित महिलाओं को नौकरी देने के लिए कोई ठोस पहल करे. तेजाबी हमले का शिकार सोनभद्र की अंजलि गुप्ता को बोलने में परेशानी होती है. ऐसे में वह अपना ज्यादातर काम इशारों में बात करके करती हैं. लेकिन एक बात आज भी वह काफी बुलंद हौसले से कहती हैं कि आरोपित को सजा दिलानी है. अंजली बोलीं कि उनको पैसे से ज्यादा खुशी तब होगी जब वह आरोपित को ऐसी सजा दिलाएं, जिससे ऐसा करने की सोचने के पहले उसकी रूह कांप जाए.

यह कहानी सिर्फ संध्या, तजरियान, प्रिया वर्मा या अंजलि गुप्ता की नहीं है, बल्कि एसिड हमलों का शिकार हुई उन सभी महिलाओं की कहानी कमोबेश मिलती-जुलती ही है, जो आर्थिक मदद पाने और न्याय का ठोस आश्वासन पाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर एकत्र हुई थीं. इनमें से कोई पति और देवर का शिकार हैं तो कोई सच के लिए लड़ते हुए दंबगों का शिकार बनी हैं. सरकार की तरफ से मदद राशि मिलने के बाद सभी पीड़ितों ने एक सुर में खुद के लिए नौकरी और बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर शिक्षा की मांग की. उनका कहना था कि सरकार के इन पैसों से कुछ समय के लिए गुजारा किया जा सकता है, लेकिन इससे वह और उनके बच्चे पूरी जिंदगी जीवन यापन नहीं कर सकते.

अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं इस तरह के हमले का शिकार तब होती हैं जब वे किसी पुरुष के अशालीन प्रस्ताव या एकतरफा प्यार को ठुकरा देती हैं. जिसे पुरुष अपनी बेइज्जती समझ बैठते हैं. इसी अपमानबोध से ग्रसित व्यक्ति अपनी जिद, नासमझी और विकृत मानसिकता के कारण हैवानियत की हदें पार कर इस तरह के जुर्म को अंजाम देता है. ऐसे छद्म इंसानों को इस बात की जरा भी परवाह नहीं होती कि वे किसी और की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं. एक सर्वे के अनुसार एसिड हमलों का शिकार अस्सी फीसदी केवल महिलाएं ही हैं जिसमें 70 फीसदी नाबालिग लड़कियां हैं.

देश के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं पर तेजाब के हमलों की घटनाओं पर न्यायपालिका की गंभीर चिंता के बावजूद घटनाओं का सिलसिला जारी है. तेजाब के हमले का शिकार युवतियों के उपचार और पुनर्वास के प्रति कई राज्य सरकार अभी भी उदासीन हैं. तेजाब फेंककर किसी को जख्मी करने का कृत्य बेहद हिंसक अपराध की श्रेणी में आता है. यह ऐसा अपराध है जो आमतौर पर ईर्ष्यावश या फिर बदला लेने की मंशा से किया जाता है. देखा जा रहा है कि तेजाब का हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ जांच बहुत तेजी से नहीं होती. इसके बाद मुकदमे की कार्यवाही शुरू होने तथा दोषियों को सजा दिलाने में लंबा वक्त निकल जाता है. इस दौरान तेजाब के हमले से पीड़ित महिला के शारीरिक और मानसिक कष्ट की कल्पना की जा सकती है.

तेजाब के हमलों की घटनाओं से प्रभावी तरीके से निबटने के इरादे से पहले ही भारतीय दंड संहिता की धारा 326 में संशोधन कर इसमें धारा 326 (क) और धारा 326 (ख) जोड़ी गई है. धारा 326 (क) के तहत किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंक कर उसे स्थाई या आंशिक रूप से कुरूप बनाने या शरीर के विभिन्न अंगों को गंभीर रूप से जख्मी करना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है. कानून में इसके लिए दोषी व्यक्ति को कम से कम दस साल और अधिकतम उम्रकैद की सजा का प्रावधान है. इसी तरह, धारा 326 (ख) में किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंकने या तेजाब फेंकने के प्रयास को दंडनीय अपराध बनाया गया है. इस अपराध के लिए कानून में कम से कम पांच साल और अधिकतम सात साल तक की सजा का प्रावधान है. दोनों ही प्रावधानों में दोषी पर जुर्माना लगाने की भी व्यवस्था है. तेजाब के हमलों में आए जख्म का इलाज बहुत ही महंगा और दीर्घकालीन होता है. इसीलिये पीड़ित को तत्काल मुआवजा दिलाने और नि:शुल्क उपचार सुनिश्चित कराने की दिशा में न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया है. न्यायपालिका के सख्त रुख के कारण ही दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करके कानून में तेजाब के हमले का निशाना बने पीड़ितों के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज का प्रावधान किया गया. लेकिन इस प्रावधान पर कारगर तरीके से अमल नहीं होने की शिकायतें मिलने पर अब शीर्ष अदालत केन्द्र सरकार से जानना चाहती है कि इस प्रावधान पर प्रभावी तरीके से अमल के बारे उसकी क्या योजना है.

ऐसे ही एक हमले का शिकार दिल्ली की नाबालिग लड़की लक्ष्मी ने उच्चतम न्यायालय में 2006 में एक जनहित याचिका दायर की थी. पिछले नौ साल में इस याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने समय-समय पर अनेक निर्देश दिए. इसमें तेजाब के हमले के पीड़ित को तत्काल मुआवजा देने और देश भर में तेजाब जैसे ज्वलनशील पदार्थों की खुले बाजार में होने वाली बिक्री को नियंत्रित करने सहित अनेक निर्देश शामिल थे. न्यायपालिका के कठोर रुख के बावजूद राज्य सरकारों के ढुलमुल रवैये की वजह से इस विषय पर भी कछुआ रफ्तार से ही प्रगति हो रही है. वैसे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तेजाब और दूसरे ज्वलनशील पदार्थों की बिक्री को नियमित करने के लिये नियम तैयार किए गए हैं लेकिन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अभी भी तेजाब सहजता से उपलब्ध है. जबकि सुप्रीमकोर्ट की गाइड लाइन है कि ग्राहक से बिना आईडी प्रूफ लिए किसी को तेजाब न दिया जाए. तेजाब हमले के आरोपी अपराधी को अधिकतम सात साल की सजा होती है, जिसमें उसे आसानी से जमानत मिल जाती है. ऐसे में एक लड़की की जिंदगी नर्क बन जाती है और आरोपी बाहर आकर पीड़ित को डराता-धमकाता रहता है. ■

राहत सूची में नाम नहीं

एसिड हमलों की पीड़िताओं को मुख्यमंत्री की तरफ से आर्थिक सहायता दिए जाने की खबर सुनते ही लखनऊ की कई बेटियां राहत की उम्मीद लगाकर मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचीं, लेकिन आर्थिक सहायता पाने वालों की लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था. घन्टों धूप में इन्तजार के बाद भी जब कोई उम्मीद नहीं दिखी तो वे दुपट्टे से मुंह ढंके निराश वापस लौट गईं. आलमबाग की रेलवे कॉलोनी में रहने वाली कविता जून 2012 में एसिड हमले का शिकार हुई थीं. दो महीने अस्पताल में रहने के बाद घर पहुंचीं तो घरवालों ने लाज का हवाला देकर उससे नाता तोड़ लिया. चेहरे व हाथ से झुलसी कविता अब छोटे भाई के साथ किराए पर कमरा लेकर गुजर-बसर कर रही हैं. दो वक्त की रोटी की खातिर वह कागज की जूलरी बनाती हैं. उन्हें आज तक कोई सरकारी मदद नहीं मिली. यह बात अलग है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसी साल महिला दिवस पर उसे सम्मानित कर चुके हैं. कविता के अनुसार उसे चेहरे की सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत है. अगर मदद मिल गई तो वह सर्जरी करवा लेंगी. कुछ ऐसी ही कहानी चौक में रहने वाली मीना की भी है. मीना पर उसके पति ने ही एसिड फेंका था. मीना कहती हैं कि हमले के बाद तो मानों उनका इस दुनिया में कोई बचा ही नहीं. तीन महीने अस्पताल में रहने के बाद वह जब घर लौटीं तो मायके वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए. तब से आज तक अपना इलाज करवाने के साथ मीना तीन बच्चों को लेकर किराए के मकान में रहती हैं. एक संस्था में काम करके किसी तरह से घर चला रही हैं. कहती हैं कि मदद मिल जाती तो पुनर्वास हो जाता. मीना को भी मुख्यमंत्री सम्मानित कर चुके हैं. ■

मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों अपने सरकारी आवास पर आयोजित उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अंतर्गत एसिड हमले की पीड़िताओं से मुलाकात की, उनका दुख बांटा और उनसे बातचीत की. अखिलेश ने उन युवतियों के लिए आर्थिक सहायता का वितरण किया, रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार दिए तथा महिला सम्मान कोष की वेबसाइट का शुभारम्भ किया. मुख्यमंत्री द्वारा किया गया यह प्रयास स्वागतयोग्य एवं सराहनीय है. मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के भावनात्मक पहलू को विचार में रख कर ये सारी सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही है. लेकिन उनकी पीड़ा केवल आर्थिक मदद से दूर होने वाली नहीं है.